सूर्योदय 6.01 सूर्यास्त 6:36

आज का तापमान

शिमला	15.4 न्यू	23.2 अधि
धर्मशाला	17.5 न्यू	29.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	76,132
निफ्टी	23,779
सोना	1,52,000
चांदी	2,35,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | मंगलवार, 8 सितंबर 2026 | 23 भाद्रपद, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 134, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

सागर में जहरीली शराब से पिता-बेटा समेत 22 की मौत

एजेंसी, सागर। सागर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। मरने वालों में पिता-पुत्र भी शामिल हैं। 112 लोग ऐसे हैं, जिनकी जहरीली शराब पीने से हालत बिगड़ी है। उन्हें सागर और भोपाल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मामले में शराब बेंचने वाले ठेकेदार समेत 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 10 को अरेस्ट कर लिया गया है। सोमवार सुबह महेश रावत (55), श्याम बाई अहिरवार (50) और कृष्ण कुमार लोधी ने दम तोड़ा। इससे पहले एयरलिफ्ट कर भोपाल लाए गए राम प्रसाद लोधी की रविवार देर रात को मौत हुई थी। उनके पिता गोविंद लोधी ने भी रविवार को दम तोड़ दिया था। रामप्रसाद का छोटा भाई भूरे लोधी सागर में भर्ती है। वहीं, दोपहर में गूगरा खुर्द निवासी भगवान सिंह (35), खटोरा निवासी गोपाल आदिवासी (40) और देश कुमार लोधी, निवासी मुड़ना पैरा की भी मौत हुई है।

चिकित्सा क्षेत्र में परीक्षण उपकरणों का सौ फीसदी खर्च उठाएगी सरकार

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को

वैश्विक ग्राहकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरण विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षण उपकरणों की खरीद के लिए 100 फीसदी धन उपलब्ध कराने को तैयार है। पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में दवा उद्योग से जुड़े दो कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि घरेलू कंपनियों को प्रौद्योगिकी साझेदारी करनी चाहिए, संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए तथा वैश्विक नवोन्मेषकों और बड़ी दवा कंपनियों को भारत आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।

बागपत सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 24 घायल

एजेंसी, बागपत। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के थाना खेकड़ा क्षेत्र में रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई। बागपत पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर ने बागपत पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उन्होंने बताया कि सभी घायलों का इलाज जारी है। रविवार देर रात करीब 12:30 बजे एक वाहन डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गया। उसकी सूचना डायल 112 को मिली थी। वाहन में सवार सभी लोग राजस्थान से जनपद बदायूं की ओर जा रहे थे। सूचना मिलते ही चार पीआरवी, एंबुलेंस सेवा, थाना खेकड़ा पुलिस और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसा इतना भीषण था कि वाहन में सवार कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। दुर्घटना में करीब 24 लोग घायल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हॉस्टल हादसे के लिए नगर निगम व डीयू जिम्मेदार : दिल्ली हाईकोर्ट

सरकार भी जवाबदेही से नहीं बच सकती; बिल्डिंग मालिक हिरासत में; 7 की मौत

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली हॉस्टल मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा– हादसे के लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने कहा कि बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों के हॉस्टलों की हालत बेहद दयनीय और खराब है। सरकार जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है।

अदालत ने एमसीडी, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एनएचआरसी और दिल्ली विश्वविद्यालय को 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, पुलिस ने हॉस्टल के मालिक हरिराम बंसल को राजस्थान के भिवाड़ी से हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस

जारी किया था। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 लोगों को बचाया गया है। इनमें 5 की हालत गंभीर है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। हॉस्टल हादसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। हॉस्टल 5 मंजिला इमारत में था, जो करीब 40 साल पुरानी थी। दिल्ली नगर निगम के रिकॉर्ड में इस इमारत को खतरनाक घोषित नहीं किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि संबंधित अधिकारियों ने अपने वैधानिक कर्तव्यों का ठीक से पालन किया होता, तो ऐसे हादसों को टाला जा सकता था।

कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ पीजी मालिक बेखौफ होकर अवैध निर्माण करते हैं। यह हैरान करने वाला है कि जिन इमारतों का नक्शा सिर्फ दो मंजिलों के लिए पास होता है, उन्हें पुरानी नींव पर ही छह मंजिला तक खड़ा कर दिया जाता है। इसके लिए एक उचित नियामक व्यवस्था होना बेहद जरूरी है।

कुछ छोटे अफसरों पर मढ़ दी जाती है जिम्मेदारी : राहुल

राहुल गांधी ने सोमवार को एक्स पर लिखा कि हर बार भाजपा सरकार का वही शर्मनाक पैटर्न-हादसों से पहले रोकथाम नहीं, उनके बाद बयानबाजी होती है, कुछ छोटे अफसरों पर जिम्मेदारी मढ़ दी जाती है, और असली गुनहगार जवाबदेही मुक्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि 12 साल में ये सरकार दुनिया भर की बातें कर के आपको गोल-गोल घुमाती रही, लेकिन मुद्दे की बात नहीं की।

दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे में दक्षिण जोन उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को सत्य निकेतन पीजी इमारत हादसे में कार्रवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के दक्षिण जोन के उपायुक्त समेत पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया।

मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों को निलंबित किया है उनमें दक्षिण उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता (भवन) ललित कुमार गोयल, सहायक अभियंता (भवन) सुनील चौहान और जूनियर इंजीनियर (भवन निर्माण) आशीष कुमार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार सुबह फिर से हादसा स्थल का दौरा करके राहत एवं बचाव की कार्य की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकारों से कहा कि लगभग

◆ दिल्लीवासियों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा: सीएम

अस्सी फीसद मलबा हटा दिया गया है, बस बेसमेंट का मलबा बचा है। बेसमेंट में पानी भरा हुआ था और पानी जमा होने के साथ-साथ पुरानी इमारत में चल रहे मरम्मत के काम की वजह से इमारत गिर गई। अब तक 12 लोगों को निकाला जा चुका है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पांचवीं मंजिल वाले भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आसपास के पीजी एवं भवनों की भी सघन जांच, नियमों का उल्लंघन मिलने पर सीलिंग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्लीवासियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, लापरवाही पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

ग्रामीण इलाकों में भी अब 25 दिन में होगी एलपीजी बुकिंग

एजेंसी, नई दिल्ली। अब गांवों में भी लोग 25 दिन में गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक करने का 45 दिन का नियम खत्म कर दिया है। शहरी क्षेत्रों में सिलेंडर रिफिल बुकिंग का अंतराल 25 दिन है। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को बताया कि सरकार ने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इस नए नियम को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने मंत्रालय का एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव का नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर शेयर किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री गोपी ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग के दौरानएलपीजी सप्लाई पर दबाव था। इसके चलते 9 मार्च 2026 को शहरी इलाकों में रिफिल बुकिंग का अंतर 25 दिन और 12 मार्च को ग्रामीण इलाकों में 45 दिन कर दिया गया था।

डॉक्टरों पर हमले को सामान्य नहीं मान सकते : सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा डॉक्टरों की पिटाई की बढ़ती घटनाओं पर गहरी नाराजगी जाहिर की है।

जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र में डॉक्टर की पिटाई के मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि एक ही विचारधारा के लोग डॉक्टरों पर हमले में शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी शिवसेना के पार्षद रमेश म्हात्रे की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। उन्होंने कल्याण के शास्त्रीनगर अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट के मामले में मिली जमानत की शर्तों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं

◆ कोर्ट ने डॉक्टरों की पिटाई पर जताई गहरी नाराजगी

को तुरंत हिरासत में लिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को खुलेआम सड़कों पर घूमने नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों के चैंबर में जाकर उन्हें बुरी तरह पीटने को किसी भी हालत में सामान्य नहीं माना जा सकता। डॉक्टरों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरे भी ऐसी हरकत करने से डरें।

मियामी शहर में एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद रनवे से बाहर निकला प्लेन

कार्गो प्लेन गाड़ियों से टकराया, 5 की मौत

एजेंसी, मियामी। मियामी शहर में एयरपोर्ट पर प्लेन लैंडिंग के बाद रनवे से बाहर निकल गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से टकरा गया।

अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को एक बोइंग कार्गो प्लेन लैंडिंग के बाद रनवे से बाहर निकल गया। इस दौरान प्लेन कई गाड़ियों से टकरा गया और उसमें भीषण आग लग गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। 5 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा स्थानीय समय अनुसार रविवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। प्लेन अमेजन के प्राइम एयर नेटवर्क के लिए संचालित हो रही था।

विमान से निकला काले धुएं का गुबार

विमान की चपेट में आई कई गाड़ियों में लोग फंस गए थे। वहीं, विमान के पायलट और को-पायलट भी कॉकपिट में फंसे हुए थे। मियामी-डेड फायर रेस्क्यू की 60 से ज्यादा यूनिट मौके पर पहुंचीं। करीब 200 से ज्यादा आपातकर्मी बचाव अभियान में लगाए गए। टीमों ने विशेष फोम की मदद से विमान में लगी आग बुझाई और फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे के कई घंटे बाद तक विमान से ईंधन रिसाव की समस्या बनी हुई थी। अधिकारियों ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि मृतकों में कितने लोग विमान में सवार थे और कितने जमीन पर मौजूद थे।

ईसरो का निजीकरण नहीं हुआ सरकारी ही है संस्था : चेयरमैन

एजेंसी, बेंगलुरु। ईसरो चेयरमैन वी. नारायणन ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी सरकारी संस्था है और इसका निजीकरण नहीं हुआ है। उन्होंने ईसरो के कर्मचारियों की चिंताओं को जायज बताते हुए कहा कि उनका समाधान किया जाएगा। नारायणन बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के 9वें संस्करण के उद्घाटन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नारायणन का बयान ईसरो की 9 कर्मचारी संगठनों के 4 सितंबर को भेजे गए पत्र के बाद आया। संगठनों ने ईसरो के मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल कामों को प्राइवेट संस्थाओं को सौंपने के प्रस्ताव पर जवाब मांगा था। नारायणन ने कहा कि भारत के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए हर साल करीब 50 लॉन्च व्हीकल की जरूरत है।

देश में स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाना जरूरी

वी. नारायणन ने कहा, ईसरो का निजीकरण नहीं हुआ है और यह सरकारी संस्था है। हम सरकारी निवेश के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे सामने कई तरह के काम हैं। देश में स्पेस इकोसिस्टम और स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाना जरूरी है। कर्मचारी एसोसिएशनों की ओर से उठाई गई चिंताओं पर उन्होंने कहा, मेरे साथियों की जो भी चिंताएं हैं, वे निश्चित रूप से जायज हैं। उन्हें स्पष्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। हम कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान करेंगे।

सीएम धामी ने मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना का किया शुभारंभ

11 हजार युवाओं को दी जाएगी निशुल्क कोचिंग

एजेंसी, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून में 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना' का शुभारंभ किया। योजना के तहत उत्तराखंड के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को घर बैठे बेहतर अध्ययन सुविधा और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से युवा अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), बैंकिंग, रेलवे और रक्षा क्षेत्र की सीडीएस समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

◆ कहा- युवाओं को अवसर और संसाधन देना सरकार की प्राथमिकता

के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा एटी, मैट, गेट, नेट और सीएसआईआर-नेट जैसी परीक्षाओं के लिए भी युवाओं को आवश्यक मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कमी नहीं है, जरूरत उन्हें उचित अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने की है। सरकार युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उनके भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के पात्र होंगे। प्रथम चरण में 11 हजार युवाओं को नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के शुभारंभ के साथ सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। इससे युवाओं को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण तैयारी का अवसर मिलने के साथ उनके सपनों को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है।

सरकार के अनुसार योजना का मकसद आर्थिक संसाधनों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से वंचित रह जाने वाले युवाओं को समान अवसर उपलब्ध कराना है। नि:शुल्क ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को भी विशेषज्ञ मार्गदर्शन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा बर्दाश्त नहीं करूंगा : सीएम विजय

एजेंसी, चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम विजय ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा उनकी

सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विजय का यह बयान नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन की एक्ट्रेस त्रिशा को लेकर की गई डबल मीनिंग टिप्पणी के विवाद के बीच आया है। पुलिस ने 4 अगस्त को उदयनिधि स्टालिन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें उसी दिन रिहा कर दिया गया था। विजय ने कहा कि विकास के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है।

शिक्षक वह दीप हैं, जो ज्ञान का प्रकाश फैलाकर आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं : मुख्यमंत्री योगी

एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस और आगामी अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों के नाम पाती लिखी है।

इसमें मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर उन्हें राष्ट्र निर्माण की नींव रखने वाले 81 गुरुजनों को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिक्षक वह दीप हैं, जो ज्ञान का प्रकाश फैलाकर आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी ज्ञान के विस्तार और प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में आठ सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बच्चों के विद्यालय जाने का उद्देश्य केवल पढ़ना-लिखना सीखना नहीं है, बल्कि उन्हें ज्ञान, संस्कार, अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन को सही दिशा देने वाली समझ प्रदान करना है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरुकुल समग्र शिक्षा के केंद्र रहे हैं,

तकनीक के दौर में एआई साक्षरता जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तकनीक तेजी से हमारे जीवन को बदल रही है, ऐसे में डिजिटल साक्षरता के साथ एआई साक्षरता भी समय की आवश्यकता है। एआई, डीप-टेक और उभरती प्रौद्योगिकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और रोजगार के नए अवसर खोल रहे हैं। हमारी सरकार परंपरागत ज्ञान को आधुनिक विज्ञान, तकनीक, नवाचार और कौशल से जोड़ रही है। लखनऊ में एआई सिटी और कानपुर में ड्रोन एवं यूएवी तकनीक का विकसित होता पारिस्थितिकी तंत्र उत्तर प्रदेश के तकनीकी भविष्य की नई संभावनाओं का आधार बन रहा है।

◆ कहा- शिक्षा का उद्देश्य संस्कार और जीवन मूल्यों से भी जोड़ना

जहां ज्ञान के साथ जीवन मूल्यों और दायित्वबोध की शिक्षा दी जाती थी। यही भाव आज की शिक्षा व्यवस्था का भी आधार होना चाहिए। ज्ञान तभी सार्थक है, जब वह जीवन को सरल बनाने के साथ समाज के लिए भी उपयोगी साबित हो। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश

◆ बच्चों के जीवन को सही दिशा देने वाली समझ देना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य

सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प, मिशन प्रेरणा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालयी सुविधाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया है।

कैंसर देखभाल संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार व्यय करेगी 800 करोड़ : सीएम सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा अधिकारियों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) प्रदान करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मरीजों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

राज्य सरकार प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दे रही है तथा स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पड़े सभी पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कैंसर के मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार पूरे प्रदेश में कैंसर

◆ चिकित्सा अधिकारियों को एनपीए देने पर विचार कर रही सरकार

देखभाल संस्थानों को मजबूत करने के लिए 800 करोड़ रुपए व्यय करने जा रही है। उन्होंने कैंसर देखभाल संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश भी दिए। राज्य सरकार द्वारा एम्स दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया जारी है। इससे प्रदेश में मरीजों की जांच और उपचार की सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थियों और फैकल्टी को विश्वस्तरीय उपचार पद्धतियों और स्वास्थ्य सेवाओं में अपनाई जा रही आधुनिक कार्यप्रणालियों से अवगत करवाने के लिए विदेशों के प्रतिष्ठित व विश्वस्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों के एक्सपोजर विजिट करवाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्कूलों व तकनीकी संस्थानों के मेधावी विद्यार्थियों को विदेशों में एक्सपोजर विजिट करवाया जा रहा है। इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण से बच्चों को अंतरराष्ट्रीय कार्यशैली से अवगत होने का अवसर मिलता है, जिससे उनका कौशल संवर्द्धन होता है।

स्वीकृति हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 5 लाख डाटा सिम खरीद को दी मंजूरी

दसवीं, 12वीं के पांच लाख विद्यार्थियों को मिलेंगे टैब

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवता व तकनीकी शिक्षा मुहैया करवाने पर बल दे रही है, ताकि विद्यार्थी वर्तमान समय की मांग के अनुसार दक्ष हो सके। सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 5 लाख डाटा सिम खरीद को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री सोमवार को हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कक्षा 10वीं से 12वीं

◆ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 90 करोड़ रुपए से अधिक के सेवा कार्यों को दी मंजूरी

तक के विद्यार्थियों को 5 लाख टेबलेट दिए जाएंगे। इनके लिए डाटा सिम की खरीद की जाएगी। इसके अलावा हरियाणा बिजली प्रसारण निगम के लिए 220 वॉट की टयूबलर टाइप लीड एसिड बैटरी की खरीद प्रक्रिया को भी

◆ दक्षिण और उत्तर जोन के लिए 59 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस मंजूर

स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें 100 एएच, 200 एएच तथा 120 एएच सहित 5 टाईप की बैट्रियों की खरीद शामिल हैं। हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री ने हैफेड द्वारा संचालित असंध शुगर मिल के वार्षिक ओवरहॉलिंग, मरम्मत, रखरखाव एवं सामान सहित एक साल के लिए 11.90 करोड़ रुपए में चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत दक्षिण जॉन के लिए 33 तथा नोर्थ जॉन के लिए 26 एडवांस लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नागरिकों को देने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। एचपीपीसी बैठक में लगभग 90 करोड़ रुपए से अधिक के सेवा कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया, आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़, निदेशक सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग तथा एमडी एचवीपीएन डा. आदित्य दहिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सेनाओं के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को केंद्र की मंजूरी

एजेंसी, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) की बैठक में तीनों सेनाओं के लिए लगभग एक लाख 10 हजार करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इससे भारतीय सेना के लिए केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेकी व्हीकल, हाई मोबिलिटी व्हीकल, सेल्फ-प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद की जाएगी। मंजूर किये गए प्रस्तावों में से लगभग 98 फीसदी खरीद भारतीय इंडस्ट्री से की जाएगी। रक्षा बलों के अलग-अलग अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) यानी सैद्धांतिक एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी मिलने से तीनों सेनाओं को नए हथियार मिलने से युद्धक क्षमता मजबूत होगी।

शिक्षक भर्ती विधेयक पर बढ़ा विरोध, स्वायत्तता की रक्षा को लेकर राज्यपाल से मिलेंगे शिक्षक

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ ने प्रस्तावित शिक्षक भर्ती विधेयक के विरोध में सोमवार को भी विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखा। संघ ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं संस्थागत स्वायत्तता, शिक्षकों की गरिमा तथा उच्च शिक्षा के मूल्यों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है।

संघ ने अब अपनी मांगों और आपत्तियों को राज्यपाल तक पहुंचाने का फैसला किया है। इसके लिए शिक्षक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर प्रस्तावित भर्ती व्यवस्था को लेकर अपनी चिंताएं रखेगा। संघ का कहना है कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और स्वतंत्र शैक्षणिक वातावरण के लिए बेहद जरूरी है।

प्रदर्शन में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ एवं विशिष्ट प्रोफेसरों के साथ विधि संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययन केंद्र, स्नातकोत्तर केंद्र, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा केंद्र तथा सांध्य केंद्र के शिक्षकों ने भाग लिया। शिक्षकों ने कहा कि मामला केवल भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक स्वायत्तता, शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षक की पेशेवर गरिमा भी जुड़ी है। संघ अध्यक्ष प्रो. नितिन व्यास ने कहा कि शिक्षक भर्ती विश्वविद्यालय की अकादमिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भर्ती प्रक्रिया में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, विषय विशेषज्ञता और शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना में शिमला अव्वल, उत्कृष्ट कार्यान्वयन पर मिला राष्ट्रीय सम्मान

सूक्ष्म खाद्य उद्योगों को संबल, शिमला में हजारों आवेदनों पर ऋण स्वीकृति से बढ़ी उद्यमिता

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए जिला शिमला को उत्कृष्ट प्रदर्शन के राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना सम्मेलन के दौरान हिमाचल प्रदेश में योजना के सफल क्रियान्वयन तथा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान के लिए जिला नोडल अधिकारी संजय कंवर को यह सम्मान प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से दिया गया।

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में

पूरी टीम की समर्पित सेवा और महत्वपूर्ण योगदान का यह परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि हिमाचल प्रदेश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय उद्यमियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है।

2,210 मामलों में ऋण स्वीकृत : जिला स्तरीय समिति की बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 से अब तक जिला शिमला में योजना के तहत कुल 3,297 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 3,185 आवेदन ऋण स्वीकृति के लिए विभिन्न बैंकों को भेजे गए हैं।

प्राप्त आवेदनों में से 2,210 मामलों में ऋण स्वीकृत हो चुका है, जबकि 130 आवेदन ऋण प्रक्रिया के अधीन हैं। वहीं, 67 आवेदन अनुशंसित नहीं किए गए, जबकि 748 आवेदन बैंकों द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1 अप्रैल से 5 सितंबर, 2026 तक जिला उद्योग केंद्र शिमला द्वारा 284 नए मामलों को विभिन्न बैंकों के पास ऋण स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार इन मामलों से जिले में स्वरोजगार तथा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

उपायुक्त ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें मजबूत बनाना है। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

कंगना के तेवरों पर विक्रमादित्य का पलटवार मंडी में विकास को लेकर सियासी घमासान तेज

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मंडी में अधिकारियों को फटकार लगाने के सांसद कंगना रनौत के अंदाज को लेकर हिमाचल की सियासत गरमा गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बिना नाम लिए कंगना पर निशाना साधते हुए अधिकारियों से संवाद और प्रशासन चलाने के तौर-तरीकों पर सवाल उठाए हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने अपने आधिकारिक वाट्सएप समूह में एक पोस्टर साझा किया। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों के पास कानून और कलम की ताकत होती है, उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची करने की आवश्यकता नहीं होती। पोस्ट में कहा गया कि आवाज ऊंची करने से आदेश सख्त नहीं बनते, बल्कि कलम की स्याही ही पर्याप्त होती है।

उन्होंने साझा पोस्टर में यह संदेश भी दिया कि प्रशासन ऊंची आवाजों से नहीं, बल्कि शांत और कठोर फैसलों से चलता है। संविधान का उल्लेख करते हुए पोस्ट में कानून की ताकत और प्रशासनिक मर्यादा को महत्वपूर्ण बताया गया है।

विक्रमादित्य सिंह की यह पोस्ट मंडी में शनिवार को हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक के बाद सामने आई। बैठक में सांसद कंगना रनौत ने विकास कार्यों और सांसद निधि से जुड़े मामलों में देरी को लेकर अधिकारियों से जवाब मांगा था। उन्होंने कामकाज की गति और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई थी। बैठक के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाने का कंगना का अंदाज इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा। इसी बीच विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट सामने आने से सियासी बयानबाजी को और हवा मिल गई।

बड़े सपनों संग आगे बढ़ें बच्चे, मेधावियों के लिए उपायुक्त ने खोला प्रोत्साहन का द्वार

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खलग में सोमवार को विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ज्ञान सागर नेगी और उपमंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा ने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें जीवन में अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि बच्चों के जीवन में माता-पिता और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से परिजनों के त्याग और मेहनत को समझने तथा उनका सम्मान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखें और सही-गलत का निर्णय स्वयं लेने की क्षमता विकसित करें। असफलता से घबराने के बजाय उससे सीख लेकर आगे

बढ़ना चाहिए। बच्चों को अपने सपने बड़े रखने और उन्हें हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करने की सलाह दी। उन्होंने नशे से दूर रहने, नियमित व्यायाम एवं खेलकूद करने और अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत विकसित करने पर भी जोर दिया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि नशा और मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से नशा न करने का दृढ़ संकल्प लेने और किसी भी गलत गतिविधि की जानकारी शिक्षकों अथवा पुलिस को देने का आह्वान किया।

जुग्गर में छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता का होगा भव्य समापन समारोह

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह 9 सितंबर, 2026 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुग्गर में आयोजित अंडर-14 छात्राओं की ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह 9 सितंबर को दोपहर 2 बजे जुग्गर पहुंचेंगे। इस दौरान वह छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लेकर प्रतिभागी छात्राओं का उत्साहवर्धन करेंगे। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों से छात्राओं के भाग लेने की संभावना है। प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं को खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की सीख भी मिलेगी। समापन समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं और विजेता टीमों को सम्मानित किए जाने की भी संभावना है।

सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती, हादसे रोकने के लिए जागरूकता पर जोर

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने जिला कांगड़ा में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और जनजागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। सोमवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रशासन, पुलिस, संबंधित विभागों के साथ आम जनता की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है।

डॉ. भारद्वाज ने कहा कि देश में हर वर्ष करीब डेढ़ लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाते हैं। वर्ष 2026 में अब तक कांगड़ा जिले में सड़क हादसों में 87 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 78 लोग गंभीर और 359 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं।

उन्होंने कहा कि बैठक में सामने आए आंकड़ों के अनुसार करीब 93 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं में मानवीय भूल प्रमुख

कारण रही है। ऐसे में केवल चालान और दंड से समस्या का समाधान नहीं होगा। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है।

सांसद ने बताया कि जिले में 11 स्थानों पर बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है। उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी ऐसी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि यातायात नियमों की निगरानी और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई प्रभावी हो सके। उन्होंने आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पशु मालिकों को जागरूक करने तथा सड़कों पर पशुओं को खुला न छोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी बल दिया।

सेवा संकल्प से संगठन सशक्त करेगा भाजपा नेरचौक मंडल, मिशन 2027 को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश

भारतेन्दु संवाददाता, नेरचौक। भारतीय जनता पार्टी नेरचौक मंडल ने संगठन को मजबूत करने और जनसेवा की भावना को धरातल तक पहुंचाने के संकल्प के साथ सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। मंडल कार्यालय घट्टा में आयोजित बैठक मंडल अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में भाजपा जिला प्रभारी सुरेश भारद्वाज ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की आगामी गतिविधियों, जनसंपर्क और सेवा कार्यों को लेकर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत से संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें तथा केंद्र और प्रदेश स्तर पर पार्टी की नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान को केवल संगठनात्मक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने का माध्यम बनाने पर जोर दिया।

17 सितंबर से प्रदेशभर में भाजपा चलाएगी जनसेवा के 25 अभियान

भाजपा का सेवा संकल्प, हिमाचल में जनसंपर्क अभियान को मिलेगी धार

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा और समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पार्टी हिमाचल प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान को प्रदेश के करीब आठ हजार बूथों तक पहुंचाया जाएगा।

डॉ. बिंदल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाकर गरीब, किसान, युवा, महिला और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण को शासन की प्राथमिकता बनाया। उन्होंने कहा कि गरीबों को आवास, शौचालय, नल से जल, स्वास्थ्य सुरक्षा, किसानों को आर्थिक सहायता और जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने जैसी योजनाएं इसी सेवा भावना का परिणाम हैं।

उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को शाम सात बजे प्रदेश के करीब आठ हजार बूथों के अंतर्गत 80 हजार घरों में आशीर्वाद के दीप जलाए जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 100 परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की कामना के साथ वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे।

डॉ. बिंदल के अनुसार 17 से 20 सितंबर तक प्रदेशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए विकसित भारत विषय पर चित्रकला और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं होंगी तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। मंडल, ग्राम केंद्र और बूथ स्तर पर नशा मुक्ति, स्वच्छता, शिक्षा, चिकित्सा, जरूरतमंदों की सहायता और दिव्यांगजनों की सेवा सहित 25 प्रकार के सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के अंतिम चरण में युवा मोर्चा की ओर से सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएगी।

डॉ. बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश की शिक्षा और वित्तीय व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अनेक विद्यालय एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं और कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक, भवन तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी विद्यालयों में शुल्क बढ़ाने और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती पर भी उन्होंने सरकार को घेरा।

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सायर मेले को भव्य बनाने का किया आह्वान

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। राज्य स्तरीय सायर मेले को सफल बनाने के लिए सभी लोगों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है। सोमवार को एसडीएम कार्यालय के सभागार में आयोजित मेले की तैयारियों को लेकर बैठक में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा कि सायर मेला क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर है और इसे हर्षोल्लास के साथ मनाना सभी की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि मेले को सफल बनाने के लिए अर्की विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मेले में आमंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए वह जल्द ही मेला अधिकारी से मुलाकात करेंगे।

बैठक में संजय अवस्थी ने विभिन्न विभागों से मेले की तैयारियों का फीडबैक लिया। उन्होंने पुलिस विभाग को सुरक्षा एवं यातायात की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। हिमाचल पथ परिवहन

निगम के अधिकारियों को मेला स्थल तक लोगों की आवाजाही के लिए पर्याप्त बस सुविधा उपलब्ध करवाने को कहा। नगर पंचायत को सफाई व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य, लोक निर्माण सहित अन्य विभागों को भी आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने को कहा गया।

उन्होंने अधिकारियों को मेले के दौरान प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी लगाने के निर्देश भी दिए। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए युवक मंडलों और महिला मंडलों को भी कार्यक्रमों से जोड़ने पर जोर दिया गया।

गैस कनेक्शन पर केवाईसी की मार, हजारों उपभोक्ताओं की बुकिंग अटकने का खतरा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। रसोई गैस कनेक्शन की पहचान संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गैस कनेक्शन की केवाईसी पूरी नहीं होने पर घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो सकेगी। ऐसे उपभोक्ताओं को पहले संबंधित गैस एजेंसी में जाकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करवानी होगी।

केवाईसी के लिए निर्धारित 31 अगस्त की समयसीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन गैस एजेंसियों में अभी भी उपभोक्ताओं की केवाईसी की जा रही है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई है, वे संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।

शिमला शहर की विभिन्न गैस एजेंसियों में करीब 15 से 18 प्रतिशत उपभोक्ताओं की केवाईसी अभी पूरी नहीं हुई है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे गैस कनेक्शनों की है, जिनके मूल

उपभोक्ता की मृत्यु हो चुकी है। कई परिवारों में गैस कनेक्शन पिता, दादा या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर है और उसी कनेक्शन से वर्तमान में परिवार के दूसरे सदस्य सिलेंडर की बुकिंग करवा रहे हैं।

ऐसे मामलों में पहले गैस कनेक्शन को परिवार के पात्र सदस्य के नाम स्थानांतरित करवाना होगा। इसके बाद नए उपभोक्ता की पहचान संबंधी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नामांतरण के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद गैस कनेक्शन नए उपभोक्ता के नाम किया जा रहा है।

गैस एजेंसियों के अनुसार जिन उपभोक्ताओं की केवाईसी पूरी नहीं होगी, उनकी सिलेंडर बुकिंग आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द संबंधित एजेंसी में संपर्क कर अपनी जानकारी और दस्तावेज दुरुस्त करवाने की सलाह दी गई है।

वर्तमान में शिमला में पात्र उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर करीब 1045 रुपये में मिल रहा है।

रोज़गार वैकल्पिक व्यवस्था की मांग को लेकर तहबाजारियों ने नगर निगम के खिलाफ खोला मोर्चा

रोजगार बचाने के लिए लक्कड़ बाजार में तहबाजारियों का जोरदार प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। नगर निगम शिमला द्वारा तहबाजारियों, रेहड़ी-फड़ी वालों और छोटे कारोबारियों को हटाने की कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को लक्कड़ बाजार में तहबाजारी यूनियन ने सीटू के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में तहबाजारी मौके पर एकत्रित हुए और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान तहबाजारियों ने लक्कड़ बाजार में अपनी दुकानें लगाकर सामान भी बेचा। पुलिस बल की मौजूदगी के बीच प्रदर्शन के चलते मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, महासचिव प्रेम गौतम, जिला शिमला सचिव अमित कुमार, जिला कोषाध्यक्ष बालक राम और विवेक कश्यप ने कहा कि नगर निगम प्रशासन गरीब मेहनतकशों की रोजी-रोटी छीनने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि वर्षों से रेहड़ी-फड़ी और तहबाजारी के माध्यम से हजारों परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसे लोगों को अतिक्रमणकारी मानने के बजाय उनके

रोजगार और अधिकारों की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि लक्कड़ बाजार में यातायात और लोगों की आवाजाही प्रभावित होने तथा जमीन धंसने जैसे तर्क देकर तहबाजारियों को हटाया गया, लेकिन उसी स्थान पर नगर निगम की बड़ी गाड़ियों के लिए पार्किंग बना दी गई। सीटू नेताओं ने सवाल उठाया कि यदि वहां गाड़ियों की पार्किंग से यातायात, आवाजाही और जमीन धंसने की समस्या नहीं हो रही है, तो तहबाजारियों को हटाने के तर्क पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने लक्कड़ बाजार को पहले की तरह वेंडिंग क्षेत्र में रखने की मांग की।

वैकल्पिक व्यवस्था के बिना न हटाने की मांग : सीटू ने कहा कि यदि किसी स्थान पर यातायात, अग्नि सुरक्षा या अन्य सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी समस्या है तो उसका समाधान बातचीत और उचित योजना के माध्यम से किया जाना चाहिए। गरीब परिवारों का रोजगार छीनना इसका समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने मांग की कि जिन तहबाजारियों को हटाया जा रहा है, उन्हें पहले ऐसी वैकल्पिक जगह उपलब्ध करवाई जाए जहां पर्याप्त ग्राहक पहुंच सकें और वे सम्मानपूर्वक कारोबार कर सकें।

यूनियन ने आजीविका भवन की छत, भज्जी हाउस सहित अन्य स्थानों पर तहबाजारियों को स्थान देने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि ऐसे स्थानों पर ग्राहक नहीं पहुंचते, जिससे कारोबार चलाना मुश्किल है।

कानून के तहत अधिकार देने की मांग : सीटू ने तहबाजारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष 2014 के सड़क विक्रेता कानून के प्रावधानों को लागू करने की मांग की। यूनियन ने सभी पात्र तहबाजारियों का सर्वेक्षण एवं पंजीकरण, विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने और पर्याप्त वेंडिंग क्षेत्र विकसित करने की मांग उठाई।

सीटू ने मनमाने चालान, सामान जब्त करने और प्रशासनिक उत्पीड़न पर रोक लगाने की भी मांग की। संगठन ने कहा कि शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर गरीबों का रोजगार नहीं छीना जा सकता। छोटे विक्रेता शिमला की स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सीटू ने नगर निगम से तत्काल कार्रवाई रोककर तहबाजारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने और स्थायी समाधान निकालने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उजाड़ने की कार्रवाई जारी रही तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

नाहन नगर परिषद में लाखों की वित्तीय अनियमितता, दो कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन । नगर परिषद नाहन में घर-घर कूड़ा संग्रहण के लिए वसूले जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क में 5.25 लाख रुपये से अधिक की कथित अनियमितता का मामला सामने आया है। पुलिस ने नगर परिषद के दो कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार नगर परिषद नाहन के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार की शिकायत पर सोमवार को मामला दर्ज किया गया। शिकायत में बताया गया कि घर-घर कूड़ा संग्रहण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने हेतु नितिन कल्याण को रसीद पुस्तिकाएं जारी की गई थीं। वह वाल्मीकि बस्ती नाहन का निवासी है और संविदा श्रम व्यवस्था के माध्यम से आउटसोर्स सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था।

शिकायत के अनुसार जून 2023 से 15 सितंबर 2025 के बीच नितिन कल्याण ने कुल 11,18,660 रुपये उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्र किए। इनमें से नगर परिषद के संबंधित कर्मचारी अहसान अहमद, जो सहायक के रूप में कार्यरत था, के पास केवल 5,93,450 रुपये जमा करवाए गए। इस तरह कुल 5,25,210 रुपये की राशि कम जमा पाई गई। इसके अतिरिक्त 3,94,300 रुपये से संबंधित दूसरी प्रति वाली रसीदें भी उपलब्ध नहीं मिलीं। नगर परिषद की ओर से जारी 16 रसीद पुस्तिकाओं में से पांच पुस्तिकाएं और संबंधित अभिलेख भी कार्यालय में वापस जमा नहीं किए गए।

शिकायत में दोनों कर्मचारियों पर आपसी मिलीभगत से सरकारी धन के कथित गबन और अभिलेखों में अनियमितता करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कार्यालय ग्राम पंचायत डोहगी
विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना (हि.प्र.)

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत डोहगी द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2026-27 के लिए पंजीकृत ठेकेदारों/सप्लायरों/फर्मों/व्यकितयों से निर्माण गामग्री की आपूर्ति हेतू सील बन्द लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जिसके लिए इच्छुक ठेकेदार/सप्लायर/व्यक्ति दिनांक 16.09.2026 से पूर्व इस कार्यालय में सायं पांच बजे तक (अवकाश को छोड़ कर पूर्ण रूप से भरी अपनी निविदाएं कार्यालय ग्राम पंचायत डोहगी में जमा करवा सकता है। किसी भी प्रतिनिधि व सगे सम्बन्धी की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदाएं दिनांक 17.09.2026 को समय सुबह 11:00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई समिति के समक्ष खोली जाएंगी। अतः स्थान व समय पर उपस्थित होना भी सुनिश्चित करें। निविदाएं निम्न नियमों एवं शर्तों के आधार पर ही मान्य होंगी। 1. निविदाएं सीलबंद लिफाफे में देनी अनिवार्य है। अधूरी, खुली अवधि उपरान्त प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी। 2. GST/CGST दरें निविदा प्रपत्र में भरी गई दरों में ही शामिल होगी। 3. पंजीकृत ठेकेदार/सप्लायर अपना पंजीकृत नम्बर निविदा पर भरना सुनिश्चित करें GST नम्बर CGST नम्बर की छायाप्रति लगाना आवश्यक है। 4. सप्लाई की जाने वाली सामग्री की गुणवना उत्तम होनी चाहिए। 5. कम दर वानी निविदा को ही स्वीकृति दी जाएगी। 6. सप्लायर द्वारा समय पर सामग्री नहीं दी जाती है या सामग्री की गुणवत्ता महीं नहीं पाई जाती है तो कार्यालय द्वारा उस निविदा को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा बैंडर के खिलाफ हि0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम 1994 अनुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी। धरोहर राती जब्त करली जाएगी। 7. सामग्री की दरें एक वर्ष के लिए वही रहेगी तथा सामग्री जहां तक वाहन योग्य सड़क है वहां तक पहुंचानी होगी। सामग्री की अदायगी मैटीरियल देने के उपरान्त ही की जाएगी। 8. जिस विक्रेता (Vendor) की निविदा स्वीकार होगी उसे 20000/- रू. की राशि बतौर अमानत पंचायत में जमा करवाने होंगे। 9. सामग्री बिल के गाथ M/W/X फॉर्म लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा सरकारी दरों पर रॉयल्टी काट ली जाएगी। बाकी शर्तें मौका पर बता दी जाएंगी। 10. बजरी/रेता 200 वर्ग फुट के बाहन में ही कार्य स्थल तक, जहां तक गाडी जाती हो, उपलब्ध करवाया जाए । किसी भी कोटेशन को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार पंचायत का होगा । **सामग्री का ब्यौरा-** 1.बजरी क्रैशर 10/20/40एमएम, रेत धुला हुआ क्रशर डस्ट-प्रति वर्ग फुट। 2. गैल्वनाइज्ड आयरन वायर (GI Wire) (क्रेट बायर बांध के लिए)-प्रति किलोग्राम। 3. क्वारी बोल्डर/पत्थरों की आपूर्ति (पत्थरों का न्यूनतम आकार 150 मिमी में 250 मिमी के बीच होना चाहिए)- प्रति m3। 4. इंटरलॉक टाईल/पेवर ब्लॉक 40/60/80 एमएम ISI मार्का-प्रति पीस। 5. पक्की ईंट प्रथम/द्वितीय श्रेणी- प्रति पीस। 6. पीवीसी पाईप्स ISI मार्का (2 से 6 इंच मोटाई की साईज व प्रेशर दर्शाते हुए रेट प्रस्तुत करें- प्रति फुट। 7. आरसीसी पाईप्स (साईज दर्शाते हुए रेट प्रस्तुत करें)-प्रति फुट। 8. हार्डवेयर सामग्री (आइटम वाईज रेट प्रस्तुत करें)। 9. इलेक्ट्रिक फिटिंग (Along with Quality Material)- प्रति प्वाईंट। 10. सैनिटरी फिटिंग (Along with Quality Material)- प्रति प्वाईंट। 1. स्टील कार्य (रेलिंग, रूफिंग आदि)- प्रति वर्ग फुट। 12. एल्युमिनियम फिटिंग ग्लेजिंग के साथ- प्रति वर्ग फुट 13. खेल व फिटनेस उपकरण। 14. दरवाजे, खिड़की लकड़ी /जापानी शीट-प्रति वर्ग फुट। 15 शटरिंग स्टील व लकड़ी- प्रति वर्ग फुट। 16. पब्लिक सूचना बोर्ड (Writing & Wall Painting)- प्रति वर्ग फुट। 17. जे.सी.बी खुदाई पक्की /कची-प्रति घंटा। 18. पानी टैंकर (स्टोरेज क्षमता दर्शाते हुए)-प्रति टैंक। 19. मिक्सर मशीन (डीजल व कार्य स्थल पर पहुँच सहित)-प्रति दिन। 20. सीमेन्ट किराया with loading /unloading बंगाणा से कार्य स्थल- प्रति वैग। 21. लोकल चक्कर (ट्रिप किराया)-प्रति फेरा।

प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत डोहगी
विकास खंड बंगाणा, जिला ऊना (हि.प्र.)

न्यूज ब्रीफ

सच्चा शिक्षक ही देश का असली निर्माता: डॉ. एस. फारुख

अनिल थपलियाल। देहरादून में उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद के बाल भवन सभागार में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 138वीं जयंती और शिक्षक दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. एस. फारुख ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर किया। महासचिव आशा रानी पैन्यूली ने अतिथियों और विद्यार्थियों का स्वागत किया। इस अवसर पर डॉ. मोना बाली, अंजली चंदोला, प्रो. आई.पी. पांडेय और रवीन्द्र सिंह रावत को सम्मानित किया गया। डॉ. फारुख ने कहा कि सच्चा शिक्षक देश का वास्तविक निर्माता होता है। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों को प्रेमपूर्वक शिक्षा देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान बाल भवन परिसर में पौधरोपण भी किया गया।

उद्गार का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया

अनिल थपलियाल। देहरादून में साहित्यिक सामाजिक संस्था उद्गार का वार्षिकोत्सव हिंदी भवन में धूमधाम से मनाया गया। समारोह में शिक्षक एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित नीरज नैथानी और महिला वर्ग में शिक्षिका डा. विद्या सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकारों और रचनाकारों की गरिमामयी उपस्थिति रही। संस्था ने डा. राम विनय सिंह, कन्हैयालाल पंत, डा. मुनिराम सकलानी, शायर अंबर खरबंदा और क्षमा कौशिक सहित कई साहित्यकारों को भी सम्मानित किया। समारोह में सम्मानित व्यक्तित्वों के शैक्षणिक एवं साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर शायर शादाब, डा. राकेश बलूनी, मदन मोहन डोभाल, लक्ष्मी प्रसाद बडोनी और पवन शर्मा समेत अनेक साहित्यप्रेमी मौजूद रहे।

एक साल में जिला पंचायत की आय 50 फीसदी तक बढ़ी

शिव सिंह थलवाल। उत्तरकाशी में जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान ने एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां साझा करते हुए बताया कि पंचायत की आय में करीब 40 से 50 फीसदी तक वृद्धि हुई है। यमुनोत्री-जानकीचट्टी कुली एजेंसी की निविदा प्रक्रिया से 2.46 करोड़ रुपये और पालीगाड़ ईको टैक्स बैरियर से 15 दिनों में करीब 12 लाख रुपये राजस्व मिला। माघ मेले से आय भी 18 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपये हुई। पंचायत अब डोडीताल-कल्याणी और गंगोत्री-गोमुख कुली एजेंसी शुरू कर नए आय स्रोत विकसित करेगी।

स्कूल जाते 15 बच्चों के सामने आया भालू

गिरीश चंदोला। चमोली में पोखरी में नेल गांव से स्कूल जा रहे 15 छात्र-छात्राओं के सामने सोमवार सुबह ढोगड़म तोक के पास भालू अपने बच्चों के साथ आ गया। भालू को देखते ही बच्चे घबरा गए और शोर मचाते हुए वापस गांव की ओर भागे। सभी सुरक्षित घर पहुंच गए। घटना से अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की है।

बीआरपी-सीआरपी कर्मियों को 66 दिन से वेतन नहीं

उदित नैनवाल। प्रदेशभर में कार्यरत बीआरपी-सीआरपी कर्मियों ने 66 दिन से वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। प्रतिनिधियों ने विधायक भोपाल राम टम्टा को ज्ञापन सौंपकर लंबित वेतन का तत्काल भुगतान कराने की मांग की। कर्मियों का आरोप है कि 40 हजार रुपये निर्धारित वेतन के बावजूद 22 से 27 हजार रुपये ही खाते में पहुंचते हैं। उन्होंने कटौती का स्पष्ट विवरण और पारदर्शी वेतन स्लिप उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही भविष्य में समग्र शिक्षा के माध्यम से सीधे पूरा वेतन देने की मांग उठाई। समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

योजनाओं को जनता के द्वार तक पहुंचा रही सरकार : महाराज

अनिल थपलियाल

पोखड़ा (पौड़ी) में चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण के दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री एवं विधायक सतपाल महाराज ने पोखड़ा ब्लॉक सभागार में आयोजित श्रमिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शिविर में शिरकत की। उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं तथा उनके समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

सतपाल महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। श्रमिक प्रदेश और देश के विकास की मजबूत कड़ी हैं। सड़क, भवन, औद्योगिक क्षेत्र समेत विभिन्न निर्माण कार्यों में श्रमिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य श्रमिकों को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है।

◆ पोखड़ा में आयोजित श्रमिक पंजीकरण शिविर में सतपाल महाराज ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

उन्होंने श्रमिकों से अपना पंजीकरण समय पर कराने और पहले से पंजीकृत श्रमिकों से नवीनीकरण कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा मिलती है। शिविरों के माध्यम से श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

हल्द्वानी प्रकरण को लेकर भाजपा ने निकाली आक्रोश रैली

भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया जातीय विभाजन की राजनीति का आरोप

अनिल थपलियाल

देहरादून में भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद सामने आए कथित शुद्धिकरण प्रकरण को लेकर आक्रोश रैली आयोजित की गई। रैली में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर मामले को राजनीतिक रंग देने और जातीय आधार पर समाज में विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इस विषय पर बयान देकर इसे जातीय भेदभाव से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता सामाजिक एकता और शांतिपूर्ण वातावरण में विश्वास करती है तथा राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने की कोशिशों को स्वीकार नहीं करेगी।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि हल्द्वानी की घटना के बाद कथित अनुष्ठान को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं। ऐसे संवेदनशील मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सकें।

सभी वर्गों को साथ लेकर बढ़ेगी भाजपा

राज्य मंत्री सुरेंद्र मोगा ने कांग्रेस पर लंबे समय से जातीय राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसी राजनीति को समझ चुकी है और समाज को बांटने के प्रयास सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने की नीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉ. भीमराव आंबेडकर से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को सम्मान और राष्ट्रीय पहचान देने का काम किया गया है।

भाजपा नेताओं ने सामाजिक एकता का लिया संकल्प

रैली के दौरान भाजपा नेताओं ने सामाजिक एकता, राष्ट्रवाद और संविधान के मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान सामाजिक समरसता और सभी वर्गों के सम्मान से है। जाति के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति के बजाय सभी समुदायों को साथ लेकर चलना जरूरी है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक विनोद चमोली, विधायक सविता कपूर, महापौर सौरभ थपलियाल समेत भाजपा के कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

उदीयमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति में कर्णप्रयाग विद्यालय के छह विद्यार्थी चयनित

उदित नैनवाल

कर्णप्रयाग (चमोली) में श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल कर्णप्रयाग (जयकंडी) के छह छात्र-छात्राओं का मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना 2026 के लिए चयन होने पर सोमवार को विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। चयनित विद्यार्थियों में आठ से नौ वर्ष की बालिका वर्ग में आराध्या और बालक वर्ग में मानस, नौ से दस वर्ष के बालक वर्ग में लक्की रावत तथा बालिका वर्ग में आराधना, दस से 11 वर्ष के बालक वर्ग में दीक्षांत रावत और 11 से 12 वर्ष के बालक वर्ग में वैभव शामिल हैं। योजना के तहत प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को प्रतिमाह 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

विद्यालय प्रशासन के अनुसार वर्ष 2022-23 में योजना शुरू होने के बाद अब तक विद्यालय के 30 छात्र-छात्राएं इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं। वर्ष 2022-23 में सात, 2023-24 में चार, 2024-25 में सात, 2025-26 में छह और वर्ष 2026-27 में छह विद्यार्थियों का चयन हुआ है।

विद्यार्थियों की उपलब्धि पर प्रधानाचार्य बुद्धिबल्लभ डोभाल, प्रबंधन की ओर से महंत देवेंद्र दास महाराज तथा अभिभावक संघ की ओर से नवीन नवानी ने सभी चयनित विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई दी। इस अवसर पर विद्यालय के समन्वयक, सहायक समन्वयक सहित सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

जिला योजना समिति चुनाव की तैयारियां शुरू

शिव सिंह थलवाल

उत्तरकाशी में जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला पंचायत और नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की मतदाता सूची तैयार की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला योजना समिति के निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि आठ सितंबर को निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद संबंधित निर्वाचित सदस्य 10 सितंबर तक सूची का निरीक्षण कर दावा-आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 12 सितंबर तक किया जाएगा। 15 सितंबर को अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी। दावा-आपत्ति दाखिल करने और उनके निस्तारण की प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय उत्तरकाशी में होगी। प्रशासन ने सभी निर्वाचित सदस्यों से निर्धारित तिथियों के भीतर मतदाता सूची की जांच करने और किसी त्रुटि या संशोधन की आवश्यकता होने पर समय पर आवेदन करने की अपील की है।

नंदा बड़ी जात यात्रा की तीनों डोलियां तीसरे पड़ाव पर पहुंचीं

गिरीश चंदोला

थराली में सिद्धपीठ कुरूड़ से कैलाश की ओर रवाना हुई श्री नंदा राजराजेश्वरी बड़ी जात यात्रा की तीनों देव डोलियां अपने-अपने तीसरे पड़ाव पर पहुंच गई हैं। यात्रा मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने डोलियों का भव्य स्वागत कर पूजा-अर्चना की और भेंट व पवाड़ा अर्पित कर मनौतियां मांगीं। बधाण की डोली करीब आठ किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भेंटी गांव पहुंची, जहां द्वारी माता की पूजा शुरू हुई। दशोली की डोली लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर कांडई गांव पहुंची।

◆ जगह-जगह हुआ देव डोलियों का स्वागत

डोली के साथ चल रहे दो चौसिंगा खाडू श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बंड की डोली करीब छह किलोमीटर की यात्रा कर दिगोली स्थित नंदा देवी मंदिर पहुंची, जहां देवी पूजन किया गया।

मंगलवार को तीनों डोलियां अपने अगले पड़ावों की ओर रवाना होंगी। आयोजन समिति के अध्यक्ष कर्नल हरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है।

लंबित शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर डीएम सख्त

उदित नैनवाल। जिला चमोली में जिलाधिकारी गौरव कुमार ने सोमवार को सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने 36 दिन से अधिक समय से लंबित 60 शिकायतों की विभागवार समीक्षा की और प्रत्येक मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उनकी स्थिति सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर तत्काल अपडेट की जाए। साथ ही शिकायतकर्ताओं को की गई कार्रवाई और प्रगति की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ शिकायतों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बहुविभागीय मामलों में संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

गड्ढों से जूझता देहरादून कैसे बनेगा स्मार्ट सिटी?

टूटी सड़कें, बंद ट्रैफिक लाइट और गंदगी के बीच स्मार्ट सिटी के दावों पर उठ रहे सवाल

विकास बलोनी

देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की योजनाएं लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन शहर की मौजूदा स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े करती है। कई प्रमुख सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हैं और सड़कें टूट चुकी हैं। बरसात में गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। कई चौराहों पर यातायात संकेतक भी सुचारु रूप से काम नहीं करते, जिससे जाम और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है। दूसरी ओर कुछ इलाकों में सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। चंद्रबनी श्मशान घाट जैसे संवेदनशील स्थानों तक जाने वाले रास्तों की खराब स्थिति प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

स्मार्ट शहर का मतलब केवल आधुनिक कैमरे, सेंसर और डिजिटल सुविधाएं नहीं है। नागरिकों के लिए सुरक्षित सड़कें, सुचारु यातायात, पर्याप्त रोशनी, स्वच्छ वातावरण और बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं ही स्मार्ट शहर की वास्तविक पहचान हैं। प्रशासन को दफ्तरों और कागजी रिपोर्टों से आगे बढ़कर मौके पर निरीक्षण करना चाहिए।

अधिकारियों को नियमित रूप से सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। पहले गड्ढामुक्त सड़कें, व्यवस्थित यातायात और स्वच्छ शहर सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही स्मार्ट सिटी की बड़ी योजनाएं वास्तव में नागरिकों के जीवन में बदलाव ला सकेंगी।

जनता मिलन में डीएम ने सुनीं 27 समस्याएं

उदित नैनवाल। गोपेश्वर में सोमवार को जिला सभागार में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम हुआ। विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 27 लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें रखीं। जिलाधिकारी ने सभी प्रकरणों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वरोजगार के लिए विद्यालय भवन, अनापत्ति प्रमाण पत्र, चैन लिंक फेंसिंग और वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामले प्रमुख रहे। डीएम ने अधिकारियों को पात्रता और नियमों के अनुसार कार्रवाई कर शिकायतकर्ताओं को राहत पहुंचाने को कहा। वन भूमि हस्तांतरण मामले के समाधान के लिए संबंधित विभागों की बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।

शिक्षा में अनुशासन बड़ी चुनौती : सुनील अग्रवाल

देहरादून में 30 शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला सम्मान

अनिल थपलियाल

देहरादून में शिक्षक दिवस के अवसर पर मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन उत्तराखंड तथा उत्तरांचल आयुर्वैदिक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रमों में अखिल भारतीय अनऐडेड विश्वविद्यालय महाविद्यालय एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. सुनील अग्रवाल ने शिक्षकों की वर्तमान चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज के दौर में स्कूल और उच्च शिक्षा के शिक्षकों के सामने अलग-अलग प्रकार की जिम्मेदारियां और चुनौतियां हैं।

डा. अग्रवाल ने कहा कि स्कूली शिक्षकों को शिक्षण कार्य के साथ जनगणना, चुनाव तथा अन्य सरकारी कार्यों में भी लगातार लगाया जाता है। इसके बावजूद उनसे विद्यार्थियों के बेहतर परीक्षा परिणाम की अपेक्षा की जाती है। इससे शिक्षकों पर काम का अतिरिक्त दबाव बढ़ता है और उनका मुख्य ध्यान शिक्षण कार्य से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति चुनौतीपूर्ण है। महाविद्यालयों में छात्रों की कक्षाओं में नियमित उपस्थिति लगातार कम हो रही है। कई विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद नियमित कक्षाओं में आने के बजाय अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं और केवल परीक्षाओं के समय कॉलेज पहुंचते हैं।

कहा- नैतिक शिक्षा भी जरूरी

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ते चलन और कोरोना काल के बाद विद्यार्थियों की बदलती अध्ययन प्रवृत्ति ने इस समस्या को और बढ़ाया है। ऐसे में शिक्षकों के सामने एक ओर विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और दूसरी ओर बेहतर परीक्षा परिणाम देने की चुनौती बनी रहती है। डा. अग्रवाल ने कहा कि समाज में सही और गलत के बीच अंतर समझने की प्रवृत्ति कमजोर होती जा रही है। ऐसे समय में शिक्षक केवल शिक्षा देने तक सीमित न रहें, बल्कि विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों और सही दिशा का मार्गदर्शन भी दें।

कार्यक्रमों के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 30 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, कॉलेज प्रबंधन, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।

गढ़वाली फिल्म 'घस्यारी' का ट्रेलर और पोस्टर जारी

अनिल थपलियाल

देहरादून में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में रविवार को गढ़वाली फिल्म घस्यारी का ट्रेलर और पोस्टर जारी किया गया। फिल्म के लेखक और निर्देशक सुनील बडोनी ने बताया कि इस फिल्म की परिकल्पना करीब 26 वर्ष पहले की गई थी, जो अब जाकर साकार हुई है। फिल्म में पहाड़ की घस्यारियों के कठिन जीवन और रोजमर्रा के संघर्ष को प्रमुखता से दर्शाया गया है। कथानक में जंगल में घास काटने के दौरान महिलाओं के पेड़ से गिरने तथा गुलदार और भालू जैसे वन्यजीवों के हमलों का शिकार होने की घटनाओं को दिखाया गया है। फिल्म के माध्यम से घस्यारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार से ठोस योजनाएं बनाने का संदेश दिया गया है। फिल्म के प्रमुख कलाकार अजय सिंह बिष्ट ने कहा कि यह फिल्म दर्शकों को निश्चित रूप से पसंद आएगी। मां शक्ति पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म की निर्माता परिणीता बडोनी हैं, जबकि छायांकन सारांश बडोनी ने किया है।

फिल्म की शूटिंग तुंगनाथ मंदिर के आसपास मक्खू मठ क्षेत्र में की गई है। संगीत संतोष खेतवाल ने दिया है और नरेंद्र सिंह नेगी, संतोष खेतवाल, अनुराधा निराला तथा शशि जोशी ने गीतों को आवाज दी है। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ उत्तराखंड फिल्म जगत के कलाकार, निर्माता और निर्देशक मौजूद रहे।

उत्तरांचल प्रेस क्लब में सजी शायरी की महफिल

दर्द गढ़वाली की सौ ग़ज़लों का हुआ लोकार्पण

अनिल थपलियाल। देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब सभागार में वरिष्ठ पत्रकार एवं शायर दर्द गढ़वाली के पांचवें ग़ज़ल संग्रह 'दर्द गढ़वाली की सौ ग़ज़लें' का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शायरों ने सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक परिस्थितियों, मानवीय संवेदनाओं और प्रेम पर आधारित ग़ज़लें प्रस्तुत कर श्रोताओं की खूब वाहवाही लूटी। वक्ताओं ने कहा कि दर्द गढ़वाली की रचनाएं समसामयिक विषयों और सामाजिक सरोकारों को प्रभावशाली ढंग से सामने लाती हैं। कार्यक्रम में नवीन नीर, जिक्रिया गौहर, परमवीर कौशिक, अब्दुल कय्यूम बिस्मिल, राजकुमार 'राज', अमन रतूड़ी, जिगर देवबंदी, राशिद कमाल समेत कई शायरों ने अपनी रचनाएं सुनाईं।

सीडीओ ने विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण

शिव सिंह थलवाल। (उत्तरकाशी) मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह ने भटवाड़ी के सिरोर स्थित प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षक उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, स्वच्छता, शौचालय और पेयजल व्यवस्था जांची। सीडीओ ने शिक्षकों को नवाचारी शिक्षण से बच्चों में जिज्ञासा और रचनात्मकता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर ज्ञान परखा और नियमित अध्ययन, अनुशासन व लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा।

पंजाब में नशा मुक्ति केंद्रों में उपचार के लिए तेजी से बढ़ी लोगों की संख्या

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के बीच सरकारी नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों में उपचार के लिए पहुंचने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में वर्ष 2024 में 9,577 लोगों ने दाखिला लिया था। यह संख्या वर्ष 2025 में बढ़कर 25,290 हो गई। इस तरह एक वर्ष में दाखिलों में 164 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 2026 में भी उपचार के लिए पहुंचने वालों का सिलसिला जारी है। जुलाई तक 14 हजार से अधिक लोग सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में दाखिल हो चुके हैं। इसे नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों और उनके परिवारों में उपचार व्यवस्था के प्रति बढ़ते भरोसे का संकेत माना जा रहा है। अब परिवार नशे की समस्या को छिपाने के बजाय प्रभावित परिजनों को उपचार दिलाने के लिए आगे आ रहे हैं।

सरकारी पुनर्वास केंद्रों में भी दाखिलों में बड़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में 2,644 लोगों ने यहां दाखिला लिया था, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 8,574 हो गई। यानी एक वर्ष में 224 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई। जुलाई 2026 तक 5,800 से अधिक लोग पुनर्वास केंद्रों में पहुंच चुके हैं।

नशे की लत के उपचार के लिए संचालित ओओएटी क्लीनिकों में भी नए मरीज बढ़े हैं। वर्ष 2024 में 13,033 नए पंजीकरण हुए थे, जो 2025 में बढ़कर 17,702 हो गए। अगस्त 2026 तक 12,500 से अधिक नए मरीज पंजीकृत हो चुके हैं।

सरकार के अनुसार, 27 अगस्त 2026 तक 11 हजार से अधिक लोगों को संबंधित कानूनी प्रावधान के तहत उपचार की दिशा में आगे बढ़ने पर राहत दी गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि बढ़ते दाखिले अभियान का सकारात्मक संकेत हैं। सरकार का जोर नशा तस्करों पर कार्रवाई के साथ उपचार, पुनर्वास और रोकथाम पर है।

चंडीगढ़ वित्त विभाग की कार्यप्रणाली पर कर्मचारियों ने उठाए सवाल

राष्ट्रपति भवन तक पहुंची शिकायत, कर्मचारियों ने नियमों और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता की उठाई मांग

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ में वित्त विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कर्मचारियों की ओर से उठाई गई शिकायत अब प्रशासन के स्तर तक पहुंच गई है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स यूटी कर्मचारी यूनियन ने वित्त विभाग के कामकाज की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से ऑडिट जांच करवाने की मांग की है। कमेटी ने विभाग में डेपुटेशन नियमों के कथित उल्लंघन, बिना आवश्यक अनुमति के कर्मचारियों की सेवाएं जारी रहने और इसके बावजूद वेतन भुगतान किए जाने पर सवाल उठाए हैं। शिकायत को राष्ट्रपति भवन ने चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद को भेजते हुए मामले में आवश्यक कार्रवाई और समाधान के निर्देश दिए हैं।

कमेटी पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय सेवा नियम लागू होने के बाद दूसरे राज्यों से डेपुटेशन पर चंडीगढ़ आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद सेवा जारी रखने के लिए संबंधित मूल राज्य और चंडीगढ़ प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसके लिए बाकायदा सेवा अवधि बढ़ाने की स्वीकृति यानी विस्तार आदेश की जरूरत होती है। कमेटी का आरोप है कि शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में डेपुटेशन पर आए कर्मचारी निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी आवश्यक अनुमति के बिना लंबे समय से चंडीगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं।

यूनियन के अनुसार कुछ कर्मचारी पंजाब सेवा नियमों का हवाला देकर चंडीगढ़ प्रशासन से विस्तार की अनुमति लिए बिना ही अपनी सेवाएं जारी रखे हुए हैं। कमेटी ने सवाल उठाया है कि यदि संबंधित कर्मचारियों की डेपुटेशन अवधि समाप्त हो चुकी है और आवश्यक अनुमति नहीं ली गई है तो ऐसी स्थिति में उनका वेतन किस आधार पर लगातार जारी किया जा रहा है। यूनियन ने इसे प्रशासन के वित्तीय हितों से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

वित्तीय लाभ रोकने पर भी विवाद : कमेटी ने वित्त विभाग की ओर से कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न वित्तीय लाभों से जुड़े मामलों को भी शिकायत में शामिल किया है। यूनियन का कहना है कि कुछ कर्मचारियों को अदालत के निर्देशों के आधार पर मिलने वाले वित्तीय लाभों को विभाग की ओर से रोक दिया गया है। कमेटी ने इन मामलों की भी नियमों के अनुसार समीक्षा करने की मांग की है।

वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में यह तर्क दिया गया है कि अदालत के आदेश के तहत दिए जा रहे कुछ लाभ पंजाब सेवा नियमों के आधार पर थे। चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब सेवा नियमों के साथ चंडीगढ़ के लागू नियम भी प्रभावी हैं।

मुख्य सचिव से निष्पक्ष जांच की उम्मीद

कमेटी प्रधान रणबीर राणा ने कहा कि राष्ट्रपति भवन की ओर से शिकायत को मुख्य सचिव को भेजे जाने के बाद अब प्रशासन को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि डेपुटेशन, वेतन भुगतान और वित्तीय लाभ से जुड़े मामलों में यदि कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। कमेटी का कहना है कि ऑडिट जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि डेपुटेशन पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अवधि और वेतन भुगतान के दौरान निर्धारित नियमों का पालन हुआ या नहीं। साथ ही कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय लाभों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यूनियन ने प्रशासन से मामले में समयबद्ध जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों के हितों के साथ-साथ चंडीगढ़ प्रशासन के वित्तीय हित भी सुरक्षित रह सकें।

न्यूज ब्रीफ

आपदा राहत के नाम पर साइबर ठगी का बढ़ा खतरा

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या किसी संकट के समय मदद की भावना का फायदा साइबर ठग उठाने लगे हैं। नेपाल में हाल की त्रासदी के बाद राहत के नाम पर फर्जी लिंक और संदेश भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बनाने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सतर्क रहने की अपील की है। साइबर अपराधी बाढ़ पीड़ितों, अनाथ बच्चों और गंभीर बीमार लोगों की मदद के नाम पर फर्जी वेबसाइट, क्यूआर कोड और भुगतान लिंक प्रसारित करते हैं। भावुक संदेश और तस्वीरों के जरिए लोगों को जल्दबाजी में भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसे लिंक पर क्लिक करने से बैंक संबंधी जानकारी चोरी होने या फोन में हानिकारक सॉफ्टवेयर पहुंचने का खतरा रहता है। पुलिस ने राहत राशि भेजने से पहले संस्था और बैंक खाते की आधिकारिक पुष्टि करने की सलाह दी है। ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत करें।

अमृतसर में नशे और हथियारों की बड़ी खेप बरामद

भारतेन्दु संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच किलो हेरोइन और 15 अवैध पिस्तौल बरामद की हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में आरोपियों के विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में होने की जानकारी सामने आई है। आरोपी कथित तौर पर सीमा पार से नशे और हथियारों की खेप हासिल कर निर्देश के अनुसार आगे सप्लाई करते थे। पुलिस ने घरिंडा थाने में एनडीपीएस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और आरोपियों के आगे-पीछे के संपर्कों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस का लक्ष्य पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है।

स्वाइन फ्लू से मोगा में बढ़ी स्वास्थ्य चिंता

भारतेन्दु संवाददाता, मोगा। मोगा जिले में स्वाइन फ्लू के अब तक छह मामले सामने आए हैं, जिनमें एक मरीज की मौत हो चुकी है। फिलहाल पांच मरीज स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में घर पर पृथक हैं। सरकारी अस्पताल मोगा में गंभीर मरीजों के उपचार के लिए चार बिस्तरों का पृथक केंद्र तैयार किया गया है। जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. सुमी के अनुसार गंभीर श्रेणी के मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, जबकि अन्य मरीजों का घर पर उपचार और निगरानी जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मरीजों के घर जाकर स्वास्थ्य जांच कर रही हैं और आवश्यक दवाएं उपलब्ध करा रही हैं। लोगों को बुखार, जुकाम या अन्य लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी गई है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।

लुधियाना में प्रमुख हिंदू नेताओं की बढ़ी सुरक्षा

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना । पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। खुफिया विभाग से मिले इनपुट के बाद लुधियाना पुलिस ने आरएसएस, भाजपा और हिंदू संगठनों से जुड़े कई प्रमुख नेताओं को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने नेताओं से संपर्क कर उन्हें बिना सुरक्षा के भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी। संबंधित थाना प्रभारियों ने कुछ नेताओं के घर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की जांच भी की।

मोगा हैंड ग्रेनेड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, मोगा। मोगा पुलिस ने आठ जुलाई को हुए हैंड ग्रेनेड हमले के मामले में एक और कथित आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 19 आरोपियों को काबू किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक सरताज सिंह चाहल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में घटना को अंजाम देने वाले तीन मुख्य आरोपी भी शामिल हैं। जांच के दौरान पुलिस ने आईईडी सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, नौ एमएम पिस्तौल, मैगजीन और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने फिरोजपुर से जम्मू जा रही ट्रेन में आईईडी लगाने की साजिश रची थी। थाना सदर पुलिस ने मक्खू निवासी रंजीत सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे आठ सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया।

खरगे विवाद के बीच पंजाब कांग्रेस में जोश आज सरकार के खिलाफ होगा शक्ति प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से जुड़े विवाद को लेकर पार्टी ने सोमवार को देशभर में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए। पंजाब में भी पटियाला, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर समेत कई जिलों में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता कर पार्टी का पक्ष रखा। हालांकि चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस का निर्धारित कार्यक्रम नहीं हो सका।

सेक्टर-15 स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में प्रस्तावित प्रेस वार्ता में न तो दिल्ली से आने वाले नेता पहुंचे और न ही प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रभारी भूपेश बघेल के शामिल होने की योजना थी। इसी बीच पांच सितंबर को कांग्रेस हाईकमान ने बघेल को पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी से हटाकर सचिन पायलट को नया प्रभारी नियुक्त कर दिया। इसके बाद चंडीगढ़ में होने वाले कार्यक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं रही।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी दिल्ली में होने के कारण कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। ऐसे में चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता नहीं हो सकी, जबकि पंजाब के अन्य प्रमुख शहरों में पार्टी ने कार्यक्रम किए।

आज पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन : कांग्रेस आज पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदेशभर में बड़ा प्रदर्शन करेगी। पार्टी की ओर से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलने, कर्मचारियों को स्थायी नहीं किए जाने और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस ने इन प्रदर्शनों में कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी का लक्ष्य रखा है।

चंडीगढ़ में मुख्य कार्यक्रम सेक्टर-15 स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में सुबह 10:30 बजे आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के शामिल होने का कार्यक्रम है।

सलाखों के पीछे सजेगा साहित्य का मंच 27 जेलों में बंदी दिखाएंगे अपनी प्रतिभा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब की 27 जेलों में बंद कैदियों और बंदियों को अपनी भावनाओं, अनुभवों और कल्पनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर मिलने जा रहा है। इसके लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में जेल साहित्य उत्सव आयोजित करने की तैयारी है। प्रदेश की सभी जेलों के बंदी इस आयोजन में हिस्सा ले सकेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बंदियों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को मजबूत करना है।

जेल की सलाखें बंदियों को बाहरी दुनिया से भले दूर रखती हैं, लेकिन उनकी सोच और कल्पनाओं पर कोई बंदिश नहीं है। इसी सोच के तहत उन्हें कहानी, कविता और अन्य साहित्यिक विधाओं के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। बंदी अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों, यादों, भावनाओं और भविष्य की उम्मीदों को कागज पर उतार सकेंगे।

इस पहल को 'गुलदस्ता' परियोजना के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। बेल्बा फाउंडेशन के सहयोग से संचालित परियोजना के माध्यम से जेलों में साहित्यिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। बंदियों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें अपनी रचनाएं लिखने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

जेल प्रशासन का मानना है कि पढ़ने और लिखने की आदत बंदियों को सकारात्मक दिशा देने में मदद कर सकती है। जेल में उपलब्ध खाली समय का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में करने से उनमें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित हो सकती है। लेखन उन्हें अपने विचारों और भावनाओं को समझने तथा व्यक्त करने का माध्यम भी उपलब्ध कराएगा।

पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल : जेल साहित्य उत्सव को केवल साहित्यिक आयोजन के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इसे बंदियों के सुधार और पुनर्वास से भी जोड़ा गया है।

स्काडा प्रणाली से निगरानी आसान, खराबी पर दूसरे फीडर से तुरंत बहाल होगी आपूर्ति

चंडीगढ़ः सेक्टर एक से आठ तक भूमिगत बिजली नेटवर्क से पच्चीस हजार लोगों को मिलेगी राहत

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

शहर के उत्तरी हिस्से में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सेक्टर-1 से 8 तक करीब 18 किलोमीटर लंबी 11 केवी विद्युत वितरण लाइन को भूमिगत कर दिया गया है। करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना से लगभग 25 हजार निवासियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने रविवार को परियोजना का उद्घाटन किया।

भूमिगत विद्युत नेटवर्क के दायरे में आवासीय क्षेत्रों के अलावा पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, रॉक गार्डन और सुखना झील जैसे महत्वपूर्ण संस्थान और पर्यटन स्थल भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना से इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ेगी और खराब मौसम के दौरान होने वाली बिजली बाधाओं को कम करने में मदद मिलेगी।

प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ओवरहेड बिजली लाइनें तेज हवाओं, तूफान और पेड़ों के गिरने जैसी घटनाओं से प्रभावित हो जाती हैं। कई बार एक स्थान पर तकनीकी खराबी आने से बड़े क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। भूमिगत नेटवर्क इस जोखिम को कम करेगा। इसके अलावा बिजली के खंभे और तार हटने से शहर का स्वरूप भी बेहतर होगा। खासकर रॉक गार्डन और सुखना झील के आसपास के क्षेत्र अधिक साफ और व्यवस्थित दिखाई देंगे।

इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता आधुनिक निगरानी व्यवस्था है। भूमिगत नेटवर्क को स्काडा प्रणाली से जोड़ा गया है। इससे बिजली व्यवस्था की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। किसी एक फीडर में खराबी आने पर कमांड सेंटर से बिजली का भार दूसरे फीडर पर स्थानांतरित किया जा सकेगा। इससे खराब हिस्से को अलग कर प्रभावित क्षेत्र में कम समय में बिजली आपूर्ति बहाल करने में मदद मिलेगी।

सीपीडीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रजेश कुमार के अनुसार, वन क्षेत्र से गुजरने वाले चार वितरण फीडरों पर 14 स्काडा नियंत्रित रिंग मेन यूनिटें भी स्थापित की गई हैं। इनका संचालन सेक्टर-18 स्थित कमांड सेंटर से दूरस्थ रूप से किया जाएगा। इससे बिजली नेटवर्क पर लगातार नजर रखने और खराबी की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने में सुविधा होगी। सीपीडीएल ने शहर की बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अगले पांच वर्षों में 956 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है।

छेड़छाड़, मारपीट और ओवरचार्जिंग के आरोपों से घिरी पीजीआई टक शॉप

टक शॉप में छात्रा से कथित बदसलूकी, महंगे सामान पर भी होगी कार्रवाई

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पीजीआई की लाइब्रेरी के सामने संचालित टक शॉप पर नियमों के उल्लंघन के आरोपों के बाद कार्रवाई की तैयारी है। दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। पीजीआई प्रशासन ने विभिन्न शिकायतों के आधार पर 15 हजार रुपये प्लस जीएसटी जुर्माना लगाने की बात कही है। साथ ही गंभीर मामलों में टक शॉप का लाइसेंस समाप्त करने पर भी विचार किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, टक शॉप अरविंद चमोली को 19 जुलाई 2024 को दो साल के लिए आवंटित की गई थी। करीब एक माह पहले कृष्णा नाम के व्यक्ति ने शिकायत कर आरोप लगाया था कि दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूली जा रही है। शिकायत में चाय 20 रुपये और कॉफी 30 रुपये में बेचने का उल्लेख किया गया। इसके अलावा दुकान के बाहर फ्रिज, मेज और कुर्सियां रखकर निर्धारित स्थान से बाहर अतिक्रमण करने की शिकायत भी की गई।

मामले में 31 जुलाई को एक पीएचडी छात्रा की शिकायत भी प्रशासन को मिली थी। सुरक्षा विभाग के माध्यम से मिली शिकायत में टक शॉप परिसर में कथित छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया गया था। इसके बाद डीन कार्यालय ने भी प्रशासन को इस संबंध में पत्र भेजा। पीजीआई ने मामले को महिला की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा गंभीर विषय माना।

संचालक ने अपने जवाब में बताया कि संबंधित कर्मचारी दीपक को नौकरी से हटा दिया गया है। कर्मचारी का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर पीजीआई पुलिस चौकी में जमा कराने की जानकारी भी दी गई।

डीए बकाया पर हाई कोर्ट सख्त, कहा- दबाव में नहीं आएगी अदालत

पंजाब सरकार की याचिका पर अदालत ने अगली सुनवाई तक स्थिति स्पष्ट रखने के दिए संकेत

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के पहले ही दिन स्पष्ट किया कि अदालत किसी भी दबाव में नहीं आएगी और मामले में फैसला कानून के अनुसार ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है और वह उसका पालन तथा रक्षा करना जानते हैं।

मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ डीए से संबंधित आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष की दलील, रणनीति या दबाव न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता। अदालत कानून के शासन के अनुसार ही मामले को आगे बढ़ाएगी।

31 अगस्त तक भुगतान का था आदेश : दरअसल, हाई कोर्ट ने अगस्त में पंजाब सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित डीए और डीआर की अद्यतन किस्तें 31 अगस्त तक जारी करने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि बकाया भुगतान किए जाने तक सरकार को प्रिंट और इंटरनेट माध्यमों पर बड़े पैमाने पर विज्ञापन जैसे गैर-उत्पादक खर्चों से बचना चाहिए।

पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सोमवार को हाई कोर्ट में इसी आदेश से जुड़े दो आवेदन सुनवाई के लिए आए। एक आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल ने कहा कि सरकार ने अभी तक अदालत के निर्देश के अनुपालन को लेकर शपथपत्र दाखिल नहीं किया है।

वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कौशल ने अदालत को बताया कि पंजाब सरकार ने 31 अगस्त के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। हालांकि, शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री की ओर से अपील में कुछ कमियां बताई गई हैं और उन्हें अभी तक दूर नहीं किया गया है।

सरकारी खर्च को लेकर भी सवाल: सुनवाई के दौरान सरकार के खर्चों को लेकर भी सवाल उठाए गए। अदालत के समक्ष रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के लिए करोड़ों रुपये जारी किए जाने का उल्लेख किया गया और इसे सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं से जोड़कर सवाल उठाए गए। सरकार की ओर से पेश वकील ने इन दलीलों पर आपत्ति जताई ।मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सामने आने के बाद पीठ ने कहा कि वह सोमवार को मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। अदालत ने अब मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर अगली सुनवाई पर टिक गई है।

दबाव से प्रभावित नहीं होगा फैसला : सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने अदालत की स्वतंत्रता को लेकर स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष की ओर से बनाया जाने वाला दबाव अदालत के निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा। न्यायपालिका संविधान और कानून के अनुसार काम करेगी।

डीए और डीआर का मामला पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण है। लंबित भुगतान को लेकर कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं। हाई कोर्ट के पहले के आदेश से उन्हें बकाया राशि मिलने की उम्मीद बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने के बाद मामला फिर कानूनी प्रक्रिया में पहुंच गया।

अब गुरुवार को होने वाली सुनवाई में अदालत सरकार के अनुपालन, सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील और लंबित डीए-डीआर से जुड़े मुद्दों पर आगे की स्थिति स्पष्ट कर सकती है। फिलहाल हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी प्रशासनिक, राजनीतिक या अन्य दबाव का असर न्यायिक निर्णय पर नहीं पड़ेगा और मामले का निपटारा कानून के मुताबिक ही होगा।

जस्टिस अश्वनी शर्मा की नियुक्ति पर एएसजी ने पंजाब सरकार को घेरा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस अश्वनी शर्मा की नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार की ओर से उठाए गए सवालों पर भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने पंजाब सरकार के रुख को दुर्भाग्यपूर्ण और अनावश्यक बताते हुए कहा कि नियुक्ति संविधान और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है। इसमें किसी कानून या संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है।

सत्य पाल जैन ने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 217(1) और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत स्पष्ट व्यवस्था है। जस्टिस अश्वनी शर्मा की नियुक्ति से पहले इस पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छह अगस्त 2026 को महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की थी।

उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के तहत पंजाब और हरियाणा सरकारों को प्रस्ताव की जानकारी दी गई थी और 10 अगस्त को दोनों राज्यों से राय मांगी गई। दोनों राज्यों के राज्यपालों ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। हरियाणा सरकार ने 12 और 13 अगस्त को प्रस्ताव के समर्थन में अपनी राय भेज दी, जबकि पंजाब सरकार ने अभी तक अपनी राय नहीं भेजी है।

जैन के अनुसार, पंजाब सरकार के पास अपनी राय देने के लिए पर्याप्त समय था। सामान्य तौर पर एक से दो सप्ताह का समय उचित माना जाता है। हालांकि, राज्य सरकार की राय नियुक्ति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। राय लेना प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन राज्य सरकार को प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार नहीं है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसी न्यायिक नियुक्ति के प्रस्ताव को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायिक और गैर-राजनीतिक प्रक्रिया का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की कि वह जस्टिस अश्वनी शर्मा की नियुक्ति को अनावश्यक विवाद का विषय न बनाए। उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रपति ने संविधान में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियुक्ति की है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस भर्ती में अब एसपीओ को भी मिलेगा समान अवसर

पुलिस भर्ती में नई व्यवस्था, एसपीओ और विभागीय कर्मचारियों के लिए खुले तरक्की के द्वार

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया में सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब कांस्टेबल के पद तीन अलग-अलग माध्यमों से भरे जाएंगे। नए प्रावधान के तहत कुल स्वीकृत कांस्टेबल पदों में से 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती, 15 प्रतिशत पद पात्र विशेष पुलिस अधिकारियों के समायोजन तथा 5 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत अनुयायियों की पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे।

सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुलिस नियम, 1960 में संशोधन करते हुए नया नियम 174-ए जोड़ा है। गृह विभाग की ओर से सात सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के बाद यह व्यवस्था प्रभावी हो गई है। नई व्यवस्था से जहां बड़ी संख्या में युवाओं को पुलिस में भर्ती होने का अवसर मिलेगा, वहीं लंबे समय से सेवाएं दे रहे विशेष पुलिस अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों के लिए भी नियमित पुलिस बल में आने का रास्ता खुलेगा।

विशेष पुलिस अधिकारियों को मिलेगा नियमित कैडर में आने का अवसर : नए नियम के तहत कांस्टेबल पदों के 15 प्रतिशत हिस्से पर पात्र विशेष पुलिस अधिकारियों का समायोजन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विशेष पुलिस अधिकारी का कम से कम तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा होना आवश्यक होगा। इसके अलावा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा तथा शारीरिक मानक परीक्षा में सफल होना अनिवार्य रहेगा।

विशेष पुलिस अधिकारियों के लिए केवल सेवाकाल पूरा करना ही पर्याप्त नहीं होगा। आतंकरोधी अभियानों में उनके प्रदर्शन को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा। उम्मीदवार का ऐसे अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन होना तथा सक्षम प्राधिकारी से उसका विधिवत अनुमोदन होना आवश्यक होगा। इससे उन विशेष पुलिस अधिकारियों को लाभ मिलने की संभावना है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं।

गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद यह संशोधन लागू हो गया है। सरकार के इस फैसले को पुलिस विभाग में नई भर्ती के साथ-साथ लंबे समय से सेवाएं दे रहे विशेष पुलिस अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

विभागीय कर्मचारियों के लिए पांच प्रतिशत पद

प्रशासनसरकार ने पुलिस विभाग में पहले से कार्यरत अनुयायियों के लिए कांस्टेबल पदों में पांच प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया है। इस श्रेणी में पदोन्नति पाने के लिए संबंधित कर्मचारी का कम से कम पांच वर्ष का सेवाकाल पूरा होना जरूरी होगा। इसके साथ ही निर्धारित शैक्षणिक एवं शारीरिक योग्यता पूरी करनी होगी और शारीरिक मानक परीक्षा में सफल होना जरूरी होगा। इस प्रावधान से विभाग में लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

युवाओं के लिए सबसे अधिक अवसर

नई व्यवस्था में सीधी भर्ती को सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है। कुल कांस्टेबल पदों में 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। इससे पुलिस विभाग में नई प्रतिभाओं और युवाओं के प्रवेश का रास्ता मजबूत होगा। वहीं, विशेष पुलिस अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों के अनुभव को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग कोटा निर्धारित किया गया है। नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और संतुलन बढ़ने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले से जहां बेरोजगार युवाओं को पुलिस बल में शामिल होने के अधिक अवसर मिलेंगे, वहीं अनुभवी एसपीओ और विभागीय कर्मचारियों को भी सेवा के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

आरएसपुरा में मानदेय और सुविधाओं को लेकर वेटरनरी छात्रों ने किया प्रदर्शन

लंबित मांगों पर संस्थान से जवाब की उम्मीद लगाए बैठे छात्र

भारतेंदु संवाददाता, आरएसपुरा। आठ महीने से मानदेय नहीं मिलने और प्रशिक्षण से जुड़ी अन्य समस्याओं का समाधान न होने से नाराज वेटरनरी प्रशिक्षणार्थी छात्रों ने सोमवार को स्कॉस्ट के मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने संस्थान प्रबंधन के खिलाफ रोष जताते हुए जल्द से जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना है कि लंबे समय से मानदेय लंबित होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों पुनीत शर्मा, अजय शर्मा और अनिकेत ने बताया कि वेटरनरी प्रशिक्षण के दौरान उन्हें हर महीने करीब आठ हजार रुपये मानदेय दिया जाना निर्धारित है, लेकिन पिछले आठ महीनों से उन्हें इसका भुगतान नहीं किया गया है। छात्रों का कहना है कि वे प्रशिक्षण से संबंधित अपनी जिम्मेदारियां नियमित रूप से निभा रहे हैं, इसके बावजूद मानदेय नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो रही है।

लद्दाख भ्रमण अवधि घटने से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रभावित होने की आशंका।

छात्रों ने संस्थान परिसर में वाहनों की पार्किंग को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि प्रशिक्षणार्थियों के वाहनों को मुख्य द्वार के बाहर खड़ा करवाया जाता है, जबकि अन्य लोगों के वाहन परिसर के भीतर खड़े किए जाते हैं। छात्रों ने इसे भेदभावपूर्ण व्यवस्था बताते हुए उन्हें भी संस्थान परिसर में वाहन खड़ा करने की सुविधा देने की मांग की।

प्रशिक्षणार्थियों ने लद्दाख भ्रमण की अवधि कम किए जाने पर भी विरोध जताया। छात्रों के अनुसार पहले प्रशिक्षण के दौरान लद्दाख भ्रमण 15 दिनों के लिए निर्धारित था, लेकिन अब इसकी अवधि घटाकर केवल छह दिन कर दी गई है। उनका कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भ्रमण और व्यावहारिक प्रशिक्षण उनके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अवधि कम होने से उन्हें पर्याप्त अनुभव हासिल करने में परेशानी होगी।

न्यूज ब्रीफ

कठुआ में 2.672 किलो अफीम के साथ चार तस्कर हुए गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, कठुआ। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अंतरराज्यीय नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लखनपुर में 2.672 किलो अफीम बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाका लगाकर एक ट्रक की तलाशी ली, जिसमें 1.026 किलो अफीम बरामद हुई। चालक गुरविंदर सिंह और उसके साथी सुखदेव सिंह को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में पता चला कि अफीम की खेप गुजरात से राजस्थान के रास्ते पंजाब पहुंचाई जा रही थी। आरोपियों की जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने पठानकोट के गांव नक्की में दबिश दी। वहां राकेश कुमार के लिए भेजी गई खेप उसके पड़ोसी अजय कुमार के घर से बरामद हुई। इस कार्रवाई में कुल 2.672 किलो अफीम जब्त की गई। पुलिस ने राकेश कुमार और अजय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में लखनपुर थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और गुजरात से पंजाब तक फैली आपूर्ति श्रृंखला की जानकारी जुटा रही है।

गांदरबल में नहर में कूदे युवक-युवती, तलाश जारी

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। गांदरबल के कंगन इलाके के थून में सोमवार को एक युवक और युवती के पावर नहर में कूदने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कंगन पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय बचाव दल मौके पर पहुंचे। दोनों की तलाश के लिए नहर और आसपास के क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाया गया। युवक की पहचान थून निवासी इरशाद अहमद काही के रूप में हुई है, जबकि युवती की पहचान सामने नहीं आई है। पुलिस घटना की परिस्थितियों की भी जांच कर रही है। वहीं बारामूला में रविवार देर रात करीब 10 बजे एक युवक के दीवान बाग फुटब्रिज से झेलम नदी में कूदने की सूचना मिली। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, युवक को नदी में कूदने से कुछ देर पहले पुल पर देखा गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश व अन्य जरूरी कार्रवाई शुरू की। दोनों घटनाओं में फिलहाल विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

जम्मू में खौफ गैंग के छह सदस्य हथियारों सहित गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू । जम्मू पुलिस ने अरनिया इलाके में कार्रवाई करते हुए खौफ गैंग के छह कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने 3 सितंबर को कूल कलां इलाके में अश्वनी कुमार नामक व्यक्ति को पिस्तौल और धारदार हथियार दिखाकर कथित तौर पर धमकाया था। शिकायत मिलने के बाद अरनिया थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से मैगजीन सहित एक पिस्तौल, तीन जिंदा कारतूस और पांच धारदार हथियार बरामद किए गए। सभी आरोपी बिश्नाह क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने के साथ यह पता लगाने में जुटी है कि वे पहले किसी अन्य वारदात में शामिल रहे हैं या नहीं। मामले में आगे की जांच जारी है।

स्वामी हरि चैतन्य महाराज 15 सितंबर को पहुंचेंगे जम्मू

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू । प्रेमावतार एवं श्री हरि कृपा पीठाधीश्वर स्वामी हरि चैतन्य पुरी महाराज 15 सितंबर को 11 दिवसीय प्रवास पर जम्मू पहुंचेंगे। उनके आगमन पर छन्नी और बाहु फोर्ट में भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे बावे वाली माता मंदिर में पूजा-अर्चना कर मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रवास के दौरान जम्मू के अलावा राजौरी, अखनूर और खौड़ में विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 और 18 सितंबर को दलहौड़ी राजौरी, 19 सितंबर को अखनूर तथा 20 सितंबर को चमकलाल खौड़ में प्रवचन होंगे। जम्मू क्लब में 24 और 25 सितंबर को दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्री हरि कृपा सेवा समिति के प्रधान राजीव चाढ़क ने बताया कि कार्यक्रमों की तैयारियां जारी हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में कार्यक्रमों में पहुंचकर स्वामी जी के प्रवचन सुनने की अपील की।

जम्मू बस स्टैंड पार्किंग हुई महंगी वाहन मालिकों की जेब पर बढ़ा बोझ

जम्मू बस स्टैंड में पार्किंग दरें बढ़ने से व्यापारी और स्थानीय लोग हुए परेशान।

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में जम्मू विकास प्राधिकरण की पार्किंग को निजी हाथों में सौंपे जाने के बाद शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरों से रोजाना वाहन खड़ा करने वाले दुकानदारों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पार्किंग में 1300 से अधिक कारों और दोपहिया वाहनों को खड़ा करने की क्षमता है।

नई व्यवस्था के तहत दोपहिया और तिपहिया वाहनों की मासिक दिन वाली पार्किंग का शुल्क करीब 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। वहीं दुकानदारों के लिए चारपहिया या आठ सीटर वाहन को 12 घंटे तक खड़ा करने का मासिक शुल्क 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। चौबीस घंटे की पार्किंग के लिए दोपहिया और तिपहिया वाहनों का मासिक शुल्क करीब 2500 रुपये, जबकि चारपहिया वाहनों का शुल्क 4000 रुपये तक पहुंच गया है।

चारपहिया वाहन मालिक को चौबीस घंटे की पार्किंग सुविधा लेने पर हर महीने करीब 4000 रुपये खर्च करने होंगे। इस हिसाब से सालाना खर्च 48 हजार रुपये तक पहुंच जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि आम परिवारों के लिए इतनी राशि देना काफी मुश्किल है।

जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी संभालेंगे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की कमान

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने रविवार को उनकी नियुक्ति की औपचारिक अधिसूचना जारी की। नियुक्ति उनके पदभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी।

9 सितंबर को शपथ ग्रहण : जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 9 सितंबर को श्रीनगर स्थित एसकेआईसीसी में सुबह 10 बजे मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाएंगे। इससे पहले 31 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की थी।

न्यायिक क्षेत्र में लंबा अनुभव : जस्टिस भाटी को न्यायिक मामलों का लंबा अनुभव है। उन्हें 16 नवंबर 2016 को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। उनके कार्यक्षेत्र में सेवा संबंधी मामले, राजस्व, चुनाव, खनन, शिक्षा, पंचायती राज, आपराधिक मामले और जनहित याचिकाएं शामिल रही हैं।

राजस्थान में अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे : जस्टिस भाटी राजस्थान हाई कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम समेत कई संस्थाओं का न्यायिक पक्ष रखा। इसके अलावा वह रिजर्व बैंक और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय सहित कई संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

उन्होंने करीब 16 वर्षों तक भारतीय रेलवे के स्थायी अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 2009 से 2015 तक वह राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य रहे। वर्ष 2011 से 2013 तक राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के महासचिव रहे।

एम्स जम्मू की सुरक्षा संभालेगा सीआईएसएफ, जल्द होगी तैनाती

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। एम्स जम्मू की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी है। सांबा जिले के विजयपुर में स्थित एम्स जम्मू की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। करीब 226.84 एकड़ में फैला यह संस्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फरवरी 2024 में एम्स जम्मू का उद्घाटन किया था।

◆ **एम्स को मिलेगी केंद्रीय सुरक्षा**

सूत्रों के अनुसार, अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा सर्वे किया जा रहा है। इसके साथ ही आवश्यक जवानों की संख्या का भी आकलन किया जा रहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहां सीआईएसएफ की स्थायी तैनाती की जा सकती है। जम्मू-कश्मीर में हवाई अड्डों और जेलों की सुरक्षा पहले से ही सीआईएसएफ के जिम्मे है। हालांकि, देश के कई अस्पतालों ने भी सीआईएसएफ सुरक्षा की मांग की है, लेकिन सुरक्षा आकलन और बल की सीमित उपलब्धता के कारण सभी प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिल सकी है।

अस्पतालों में मरीजों, तीमारदारों, चिकित्सकों और अन्य लोगों की बड़ी संख्या में आवाजाही होती है। अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वहां सीआईएसएफ की अस्थायी तैनाती की गई थी। एम्स जम्मू में सीआईएसएफ की तैनाती होने से अस्पताल परिसर की सुरक्षा, प्रवेश-निकास व्यवस्था और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

पत्नी संग गुलमर्ग पहुंचे शिखर धवन, प्राकृतिक नजारों के हुए मुरीद

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने रविवार को पत्नी के साथ गुलमर्ग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लिया और यहां के शांत वातावरण से प्रभावित नजर आए। धवन ने गुलमर्ग के कोंगदूरी और अफरवत क्षेत्रों का भ्रमण किया तथा हरे-भरे पहाड़ों, खूबसूरत ढलानों और आसपास के मनमोहक दृश्यों का आनंद लिया।

गुलमर्ग की यात्रा के दौरान धवन ने यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण की सराहना की। पर्यटन की दृष्टि से गुलमर्ग कश्मीर के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। पहाड़ों और हरियाली से घिरे इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। धवन की यात्रा से क्षेत्र के पर्यटन को भी प्रचार मिलने की उम्मीद है।

क्रिकेट लीग के शुभारंभ में भी हुए शामिल : श्रीनगर में आयोजित प्रो स्टार क्रिकेट लीग के दूसरे सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शिखर धवन मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान लीग का आधिकारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी परवेज रसूल भी मौजूद रहे।

प्रो स्टार क्रिकेट लीग के दूसरे सत्र की शुरुआत श्रीनगर से होगी। इसके बाद प्रतियोगिता के मुकाबले विभिन्न चरणों में आयोजित किए जाएंगे और इसका समापन उत्तराखंड के देहरादून में होगा। वहीं सत्र के विजेता को चैंपियन का खिताब दिया जाएगा। आयोजकों के अनुसार लीग का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के क्रिकेट प्रेमियों को एक मंच पर लाना और देश की समृद्ध खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही प्रतियोगिता के माध्यम से उभरती क्रिकेट प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देने की कोशिश की जा रही है। शिखर धवन का कश्मीर दौरा खेल और पर्यटन दोनों दृष्टियों से खास रहा।

50 की उम्र में कर्नल जम्वाल ने 23 दिन में रचा नया कीर्तिमान

कर्नल रणवीर जम्वाल ने 23 दिनों में 20 ऊंची चोटियां फतह कर रचा विश्व रिकॉर्ड

भारतेंदु संवाददाता, सांबा। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के गांव बढ़ोरी निवासी कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनके नेतृत्व में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स (निमास), दिरांग की टीम ने लद्दाख में 6,000 मीटर से अधिक ऊंची 20 चोटियों पर सफलतापूर्वक आरोहण किया। अभियान की सबसे खास बात यह रही कि टीम ने महज 23 दिनों में इन सभी चोटियों पर पहली बार दर्ज आरोहण किया।

50 वर्ष की उम्र में असाधारण उपलब्धि : कर्नल रणवीर जम्वाल ने 50 वर्ष की उम्र में यह चुनौतीपूर्ण अभियान पूरा कर साबित किया कि उम्र पर्वतारोहण के जुनून के सामने बाधा नहीं है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, अत्यधिक ऊंचाई और मौसम की चुनौतियों के बीच उन्होंने पूरी टीम का नेतृत्व किया। उनके 23 वर्षों से अधिक के पर्वतारोहण अनुभव और 80 से ज्यादा अभियानों ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

23 दिनों में 6,000 मीटर से ऊंची 20 चोटियों पर फर्स्ट एसेंट।

पहले भी कई उपलब्धियां हासिल

कर्नल जम्वाल का पर्वतारोहण का रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है। वह माउंट एवरेस्ट पर तीन बार चढ़ने वाले एकमात्र भारतीय पर्वतारोही हैं। इसके अलावा वह सेवन समिट्स पूरा कर चुके हैं और भारत के सभी 28 राज्यों की सर्वोच्च चोटियों पर भी आरोहण कर चुके हैं। उनके नाम दो विश्व रिकॉर्ड, दो एशियाई रिकॉर्ड और चार भारतीय रिकॉर्ड सहित कई राष्ट्रीय सम्मान दर्ज हैं।

तीन वर्षों में तीसरा विश्व रिकॉर्ड

कर्नल जम्वाल के नेतृत्व में निमास ने पिछले तीन वर्षों में लगातार तीसरा विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। लद्दाख का यह अभियान संस्थान की पर्वतारोहण क्षमता और प्रशिक्षण स्तर को भी दर्शाता है।

बारामूला में वाइल्डलाइफ टीम ने पकड़ा दहशत फैलाने वाला तेंदुआ, लोगों ने ली राहत की सांस

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। बारामूला शहर के लोगों के लिए राहत की खबर है। वाइल्डलाइफ विभाग की टीम ने ड्रंगबल इलाके में एक तेंदुए को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। पिछले कई दिनों से तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। लगातार निगरानी के बाद टीम ने उचित मौका देखकर उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया।

पिछले कुछ हफ्तों से बारामूला शहर के कई रिहायशी इलाकों, बागों और शहर के बाहरी हिस्सों में तेंदुए के दिखाई देने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ था। स्थानीय लोगों ने कई बार तेंदुए के देखे जाने की सूचना विभाग को दी थी। इसके बाद वाइल्डलाइफ विभाग ने विशेष टीम को क्षेत्र में तैनात किया। टीम ने इलाके में तेंदुए की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी और उसके संभावित ठिकानों की निगरानी की। कई दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार ड्रंगबल इलाके में तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिली। विभाग की कार्रवाई के दौरान तेंदुए को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया।

तेंदुए के पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों ने वाइल्डलाइफ विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए टीम का आभार जताया। उनका कहना है कि तेंदुए की मौजूदगी के कारण शाम और सुबह के समय घरों से बाहर निकलने में भी डर बना रहता था।

◆ **सुरक्षित कार्रवाई से वन्यजीव विभाग ने बढ़ाया लोगों का भरोसा**

◆ **जंगली जानवर दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील**

विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में जंगली जानवर दिखाई दे तो उसके पास जाने या उसे घेरने की कोशिश न करें और तुरंत वाइल्डलाइफ विभाग को सूचना दें। सुबह-सवेरे और देर शाम अकेले सुनसान इलाकों में जाने से भी बचने की सलाह दी गई है।

मीरा साहिब पहुंचने पर लेफ्टिनेंट अविनाश चौधरी का भव्य स्वागत

भारतेंदु संवाददाता, मीरा साहिब। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने निवास स्थान मीरा साहिब पहुंचे अविनाश चौधरी जोहल का स्थानीय लोगों और राष्ट्रीय लोकदल के संभागीय अध्यक्ष हरबंस चौधरी जोहल की ओर से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर अविनाश चौधरी को सम्मानित भी किया गया। समारोह में पार्टी के कप्तान उत्तम सिंह चिब, आकाश चौधरी जोहल, जंग बहादुर सिंह सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोकदल के संभागीय अध्यक्ष हरबंस चौधरी जोहल ने कहा कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अविनाश चौधरी जोहल ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धि से क्षेत्र के लोगों में खुशी और गर्व का माहौल है। उन्होंने कहा कि अविनाश की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने नौजवानों से मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया। हरबंस चौधरी ने बताया कि अविनाश चौधरी जोहल के पिता राजेंद्र सिंह जोहल भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब उनके बेटे ने भी सेना में शामिल होकर देश सेवा का रास्ता चुना है।

तबादलों के साथ अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को मिले नए चिकित्सक

कारगिल-लेह में 27 चिकित्सकों के तबादले से बदली स्वास्थ्य व्यवस्था

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। लद्दाख के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक हित में 27 मेडिकल ऑफिसर, कंसल्टेंट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े चिकित्सकों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने यह आदेश पांच सितंबर को सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया। सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां तत्काल प्रभाव से संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश के तहत कारगिल के क्यूएएम अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. फातिमा बानो को कारगिल का मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं लेह की जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. फरहाना इकबाल को क्यूएएम अस्पताल कारगिल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गैर-संचारी रोग संबंधी सलाहकार डॉ. रिंचेन आंग्मो को लेह का जिला टीकाकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में गैर-संचारी रोग कार्यक्रम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

पीएचसी शक्ति की मेडिकल ऑफिसर डॉ. जिग्मेट वांगचुक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निदेशक बनाया गया है।

एनसीबी की हिरासत से नशा तस्कर हुआ फरार, तलाश जारी

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। नरवाल क्षेत्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत से एक नशा तस्कर के फरार होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। फरार आरोपित की तलाश में जम्मू शहर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच भी तेज कर दी है।

फरार आरोपित की पहचान पुलवामा जिले के काकापोरा निवासी आकिब बशीर के रूप में हुई है। एनसीबी ने उसे तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सांबा जिले में एक यात्री बस की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 522 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इसके बाद उसे एनसीबी की हिरासत में रखा गया था।

जानकारी के अनुसार रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि नरवाल क्षेत्र में आकिब बशीर एनसीबी की हिरासत से फरार हो गया। उसकी फरारी का पता चलते ही संबंधित अधिकारियों ने पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी। इसके बाद आरोपित की तलाश के लिए तत्काल अभियान शुरू किया गया।

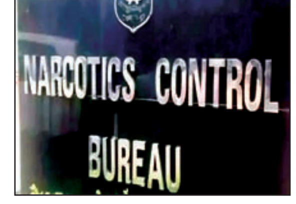

◆ **फरार तस्कर की तलाश में जम्मू में सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई सख्ती**

आरोपित के संभावित भागने के रास्तों और ठिकानों पर सुरक्षा बलों की टीमें तलाशी ले रही हैं। जम्मू में प्रवेश और निकास के प्रमुख मार्गों पर नाके बढ़ाकर वाहनों की जांच की जा रही है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ के साथ आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है।

एल्गोरिदम तय कर रहा लोकप्रियता, लाइक और सब्सक्राइबर के आंकड़े बने प्रभाव का नया पैमाना

विशाल कल्याण
सहायक प्रोफेसर, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, सोलन

आज डिजिटल युग में 'लाइक, शेयर और सब्स क्राइब' केवल सोशल मीडिया की सामान्य गतिविधियां नहीं रह गई हैं, बल्कि ये एक नई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी हैं।

आज किसी व्यक्ति, संस्था, नेता या प्रभावशाली व्यक्तित्व की लोकप्रियता उसके विचारों, कार्यों या योगदान से कम और उसके फॉलोअर्स, लाइक्स तथा सब्सक्राइबर्स से अधिक मापी जाने लगी है। मानो प्रभाव और प्रतिष्ठा का नया पैमाना डिजिटल आंकड़े बन गए हों।

सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक बनाया, लेकिन इसके साथ 'लाइक-सब्सक्राइब का खेल' भी शुरू हुआ, जहां लोकप्रियता कई बार वास्तविक न होकर निर्मित होती है। जो अधिक दिखाई देता है, वही अधिक प्रभावशाली माना जाने लगता है। हाल के दिनों में राघव चड्ढा से जुड़ी खबरों में उनके सोशल मीडिया सब्सक्राइबर्स घटने की चर्चा ने इस बहस को और तेज किया कि क्या डिजिटल संख्या वास्तव में राजनीतिक समर्थन का सही पैमाना है, या यह केवल राजनीति की धारणा का हिस्सा है।

लाइक और सब्सक्राइब अब केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि सामाजिक स्वीकृति और निष्ठा के प्रतीक बन चुके हैं। लोग लाइक के माध्यम से समर्थन, सहमति और पहचान व्यक्त करते हैं, जबकि सब्सक्राइब किसी व्यक्ति या विचार से स्थायी जुड़ाव को दर्शाता है। इससे सामाजिक प्रमाण की ऐसी मानसिकता बनी है, जिसमें लोग वही महत्वपूर्ण मानने लगते हैं जिसे अधिक लोग पसंद कर रहे हों, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या अधिक लाइक्स और सब्सक्राइबर्स वास्तविक लोकप्रियता का प्रमाण हैं? आवश्यक नहीं।

कई बार वायरल सामग्री गुणवत्ता या गंभीरता के कारण नहीं, बल्कि एल्गोरिद्म, विवाद या चलन के कारण लोकप्रिय होती है। इसी संदर्भ में राघव चड्ढा के सब्सक्राइबर कम होने की खबर को कई लोगों ने जनसमर्थन में गिरावट के रूप में देखा, जबकि कई विश्लेषकों ने इसे डिजिटल प्रतिक्रिया, एल्गोरिद्मिक बदलाव या प्रतीकात्मक असहमति के रूप में समझा। यह उदाहरण बताता है कि डिजिटल लोकप्रियता कई बार एक भ्रम भी हो सकती है। सोशल मीडिया के एल्गोरिद्म इस खेल के बड़े संचालक हैं। वे तय करते हैं कि कौन-सी सामग्री किसे और कितनी दिखाई जाएगी। भावनात्मक, विवादित या ध्रुवीकरण पैदा करने वाली सामग्री को अक्सर अधिक पहुंच मिलती है, जबकि गंभीर विमर्श पीछे छूट जाता है। इस तरह कई बार जनता नहीं, बल्कि एल्गोरिद्म लोकप्रियता का निर्माण करता है। डिजिटल युग में प्रभाव का अर्थ तेजी से बदल गया है, जहां अक्सर दृश्यता को वास्तविक प्रभाव मान लिया जाता है।

आज ध्यान-आधारित अर्थव्यवस्था में कंटेंट और व्यक्तित्व अधिक लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। इस कारण कई बार सामग्री की गुणवत्ता से अधिक उसका आकर्षण और वायरल होने की क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है। यह प्रवृत्ति राजनीति में भी स्पष्ट दिखती है। उदाहरण के लिए राघव चड्ढा के सोशल मीडिया सब्सक्राइबर घटने की खबर को राजनीतिक संकेत की तरह प्रस्तुत किया गया, जबकि डिजिटल आंकड़े हमेशा वास्तविक जनसमर्थन को नहीं दर्शाते। फर्जी फॉलोअर्स, बॉट्स और प्रायोजित ट्रेंड इस अंतर को और बढ़ा देते हैं।

इस संस्कृति का प्रभाव आम लोगों पर भी पड़ता है। लोग लाइक्स के जरिए मान्यता खोजते हैं और कम प्रतिक्रिया मिलने पर असुरक्षा महसूस करते हैं। धीरे-धीरे संख्या को गुणवत्ता मान लिया जाता है, जबकि वायरल होना सत्य का प्रमाण नहीं होता। फिर भी सोशल मीडिया पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। यह जागरूकता बढ़ाने और नई आवाजों को मंच देने में सहायक है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

बदलती जीवनशैली और गलत खानपान से युवाओं में बढ़ रहा हृदय रोग का खतरा

मुकेश विग
किसान निवास, सोलन

आज के समय में हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं और यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। यह समस्या अचानक नहीं बढ़ी, बल्कि हमारी बदलती जीवनशैली, गलत खानपान और बढ़ते तनाव का परिणाम है। पहले के समय में लोग सादा और पौष्टिक भोजन करते थे, नियमित शारीरिक श्रम करते थे और प्रकृति के अधिक निकट रहते थे। यही कारण था कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां कम देखने को मिलती थीं। आज इसके विपरीत, आरामदायक जीवनशैली और फास्ट फूड की आदतों ने दिल को कमजोर बना दिया है।

हमारे दैनिक आहार में नमक, चीनी और वसा की मात्रा अत्यधिक बढ़ चुकी है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के अनुसार, अधिक सोडियम का सेवन, फलों और सब्जियों की कमी, तथा साबुत अनाज से दूरी हृदय रोगों के प्रमुख कारण हैं। ज्यादा नमक खाने से उच्च रक्तचाप बढ़ता है, जो दिल और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव डालता है। धीरे-धीरे यह स्थिति दिल की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है और गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती है।

हमारा सामान्य हार्ट रेट 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट के बीच होना चाहिए। यदि यह 60 से कम हो जाए तो ब्रैडीकार्डिया और यदि 100 से अधिक हो जाए तो टैकीकार्डिया कहा जाता है। ये दोनों स्थितियां संकेत देती हैं कि दिल सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा है और समय रहते ध्यान देना आवश्यक है।

आजकल के युवाओं और बच्चों में भी जंक फूड का चलन बहुत बढ़ गया है। चिप्स, नमकीन, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड में अत्यधिक नमक, ट्रांस फैट और कृत्रिम पदार्थ होते हैं, जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक हैं। इनसे मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर ऊंचा होता है और धमनियों में रुकावट आने लगती है। इसके विपरीत, फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जीवनशैली में सुधार ही हृदय रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। नियमित व्यायाम, रोजाना कम से कम 30-40 मिनट पैदल चलना, साइकिल चलाना और सीढ़ियों का उपयोग करना दिल को मजबूत बनाता है। लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहना भी हानिकारक है, इसलिए बीच-बीच में सर्ि, य रहना जरूरी है। इसके साथ ही पर्याप्त नींद और मानसिक तनाव को नियंत्रित करना भी दिल के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

आज साइलेंट हार्ट अटैक के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें व्यक्ति को पहले से कोई स्पष्ट लक्षण महसूस नहीं होते। इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच बेहद जरूरी हो गई है। ईसीजी, ईकोकार्डियोग्राफी और रू जैसे परीक्षण दिल की स्थिति का सही आकलन करने में मदद करते हैं। यदि कभी सीने में दर्द, भारीपन, घबराहट या सांस लेने में परेशानी हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।

यह भी समझना जरूरी है कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जैसे किसी मशीन में खराब या गंदा ईंधन डालने से वह जल्दी खराब हो जाती है, उसी प्रकार गलत खानपान और अनियमित दिनचर्या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है।

बहरहाल, स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र संतुलन में छिपा है—संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच। यदि हम समय रहते अपनी आदतों में सुधार कर लें, तो न केवल हृदय रोगों से बच सकते हैं, बल्कि एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

लापरवाही ने फिर ली लोगों की जान

देश की राजधानी दिल्ली में सत्य निकेतन क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत के ढहने की घटना ने एक बार फिर भवन सुरक्षा से जुड़े सरकारी तंत्र की गंभीर खामियों को उजागर किया है। यह केवल एक इमारत के गिरने का मामला नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल है जो जर्जर और खतरनाक भवनों की पहचान करने, उनमें होने वाले अवैध निर्माण को रोकने और समय रहते लोगों की जान बचाने में विफल साबित हो रही है। किसी जर्जर इमारत में बरसात के मौसम के दौरान बेसमेंट में निर्माण कार्य चलना अपने आप में बड़ी लापरवाही का संकेत है। सवाल यह है कि जब भवन पहले से कमजोर था तो उसमें निर्माण की अनुमति या गतिविधि आखिर कैसे जारी रही।

किसी बहुमंजिला इमारत की सुरक्षा केवल उसके बाहरी ढांचे से तय नहीं होती। उसकी नींव, पिलर, बीम, दीवारों और भार वहन करने वाली संरचनाओं की नियमित जांच जरूरी होती है। विशेष रूप से बरसात के मौसम में जमीन में नमी बढ़ने और पानी के रिसाव के कारण पुरानी तथा कमजोर इमारतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। ऐसे में यदि बेसमेंट में खुदाई या निर्माण कार्य किया जाए तो जोखिम और बढ़ जाता है। सत्य निकेतन की घटना इसी खतरे की ओर गंभीर संकेत करती है।

दिल्ली में यह पहली घटना नहीं है। कुछ समय पहले साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक बहुमंजिला अवैध इमारत निर्माण के दौरान ढह गई थी और उसमें छात्रों की जान चली गई थी। सत्य निकेतन की घटना में भी छात्र ही प्रभावित हुए, जो पेइंग गेस्ट के रूप में वहां रह रहे थे। यह स्थिति और चिंताजनक है क्योंकि राजधानी में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और नौकरीपेशा युवा किराये या पेइंग गेस्ट व्यवस्था में रहते हैं। उनके लिए भवन की संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन करना संभव नहीं होता। वे मकान मालिक और प्रशासन की व्यवस्था पर भरोसा करते हैं।

हादसे के बाद हमेशा की तरह शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। नगर निगम तथा सरकार के अधिकारी जांच और कार्रवाई की बातें करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि कार्रवाई हादसे के बाद ही क्यों होती है। यदि किसी भवन के खतरनाक होने की जानकारी पहले से है तो उसे गिरने का इंतजार क्यों किया जाता है। बरसात से पहले जर्जर भवनों का सर्वेक्षण किए जाने का दावा भी अक्सर सामने आता है। इसके बावजूद यदि चिन्हित भवनों में लोग रह रहे हों और उनमें अवैध निर्माण चलता रहे तो इन सर्वेक्षणों की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

जर्जर भवनों की समस्या के लिए केवल प्रशासन को दोषी ठहराना भी पर्याप्त नहीं होगा। भवन मालिकों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई बार अधिक किराये या अतिरिक्त जगह हासिल करने की लालसा में भवनों में नियमों के विपरीत निर्माण कर दिया जाता है। बेसमेंट में बदलाव, अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण, कमजोर ढांचे पर अतिरिक्त भार और बिना विशेषज्ञ जांच के तोड़फोड़ जैसे काम इमारत की संरचनात्मक मजबूती को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे मामलों में मालिकों को यह समझना होगा कि नियमों की अनदेखी केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है।

दूसरी ओर प्रशासनिक भ्रष्टाचार और निगरानी की कमजोरी इस समस्या को और गंभीर बनाती है। यदि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ समय पर कार्रवाई हो और निरीक्षण व्यवस्था पारदर्शी हो तो अवैध निर्माण को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है। लेकिन जब निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित हो जाए और जिम्मेदार अधिकारी अपनी भूमिका ठीक से न निभाएं तो हादसे की आशंका बनी रहती है।

यह समस्या केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के अनेक शहरों में अवैध और मानकों के विपरीत निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। चिंताजनक बात यह है कि आधुनिक तकनीक, बेहतर निर्माण सामग्री और वैज्ञानिक इंजीनियरिंग उपलब्ध होने के बावजूद अपेक्षाकृत नई इमारतों के ढहने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। दूसरी ओर कई पुराने ऐतिहासिक भवन दशकों और सदियों बाद भी खड़े हैं। इससे निर्माण की गुणवत्ता, निगरानी और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल उठते हैं।

जरूरत इस बात की है कि जर्जर भवनों का सर्वेक्षण केवल बरसात से पहले की औपचारिक कवायद न रहे। प्रत्येक संवेदनशील भवन का वैज्ञानिक संरचनात्मक परीक्षण कराया जाए और उसकी स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो। अत्यधिक जोखिम वाले भवनों को तत्काल खाली कराया जाए। अवैध निर्माण पर समय रहते रोक लगे और दोषी अधिकारियों तथा भवन मालिकों दोनों की जवाबदेही तय हो। भवन निर्माण की अनुमति देने से लेकर उसके रखरखाव तक पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है।

हर हादसे के बाद मुआवजा और जांच से मृतकों की जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती। वास्तविक प्रशासनिक सफलता तब होगी जब हादसे होने से पहले खतरे को पहचानकर उसे टाल दिया जाए। राजधानी जैसे शहर में किसी जर्जर इमारत का गिरना केवल प्राकृतिक या आकस्मिक घटना नहीं माना जा सकता। इसके पीछे लापरवाही, अवैध निर्माण, कमजोर निगरानी और जवाबदेही की कमी जैसे कई कारण हो सकते हैं। इसलिए अब जरूरत केवल दोषियों को सजा देने की नहीं बल्कि उस पूरे तंत्र को सुधारने की है जो खतरे को देखकर भी समय रहते कार्रवाई नहीं करता। लोगों की जान से बड़ा कोई निर्माण कार्य, किराया या आर्थिक लाभ नहीं हो सकता।

-शिवांश धाकड़

कविता

मैं तेरे शहर का परिंदा हूं...

डॉ. अशोक प्यारे लाल चौबे

मैं तेरे शहर का परिंदा हूं,
तालीम न दे, उड़ने की मुझे,
अपनी उड़ान से मंजिल पा जाता हूं।
कभी तेरी मुंडेर पर बैठता हूं,
कभी किसी की मुंडेर पर ठहरता हूं, कभी पेड़ की डाल पर अपना घर बनाता हूं।
खुले आसमान को अपना साथी मानता हूं, हवाओं से बातें करता हूं,
बादलों के संग सपने बुनता हूं।
पिंजरे में कैद नहीं रह सकता, मेरी सांसों में आजादी बसी है।
मेरे पंखों को किसी सहारे की जरूरत नहीं,
मैं गिरकर भी उड़ना जानता हूं।
रास्ते कठिन हों तो क्या,
हौसले मेरे आसमान से बड़े हैं।
हर रोज तेरी छत पर आता हूं, शायद तेरी खिड़की से कोई सपना झांकता मिले।
तेरे शहर की गलियों में
मैंने मौसम बदलते देखे हैं, लोगों को आते-जाते देखा है, मगर अपनी उड़ान को कभी बदलते नहीं देखा।
आखिर परिंदों के भी शौक होते हैं, कभी पेड़ बदलते हैं, कभी छत बदलते हैं।
मगर मंजिल वही रहती है—
जहां खुला आसमान मिले, जहां पंखों पर कोई पहरा न हो, जहां उड़ने की आजादी हो।
मैं तेरे शहर का परिंदा हूं, मुझे कैद मत करना,
मेरी उड़ान को सीमाओं में मत बांधना।
मैं जहां भी जाऊंगा,
अपने पंखों में तेरे शहर की याद लिए जाऊंगा।

एकल परिवार और सामाजिक माध्यमों के बढ़ते प्रभाव ने नई पीढ़ी से छीने संस्कार और सामाजिक सरोकार

सुनीता गुप्ता कपूर
प्रवक्ता इतिहास, रा.व.मा.पा. (बाल) मंडी

भारतवर्ष प्राचीन काल से ही अपनी समृद्ध संस्कृति, उच्च नैतिक मूल्यों और गौरवशाली परंपराओं के लिए विश्वभर में विख्यात रहा है। यही तत्व हमारे समाज की आत्मा हैं, जो उसे विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उभरता है कि 'समाज' क्या है?

समाज मात्र व्यक्तियों का समूह नहीं, अपितु एक सुव्यवस्थित संरचना है, जिसमें विभिन्न लोग एक साझा भौगोलिक क्षेत्र, संस्कृति, परंपराओं और व्यवहारों के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। यह सामाजिक संबंधों, पारस्परिक क्रियाओं तथा विविध संस्थाओं का जटिल तंत्र है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सहयोग, सुरक्षा और सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परस्पर आश्रित रहता है।

समाज वह मंच है जहां भाईचारा, सम्मान, सुरक्षा और सह-अस्तित्व का भाव विकसित होता है। इसी समाज में हमारी संस्कृति और परंपराएं सुरक्षित रहती हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी उनका हस्तांतरण होता है। भाषा, त्योहार, पारंपरिक चिकित्सा, हस्तशिल्प और खानपान जैसी धरोहरें इसी माध्यम से जीवित रहती हैं। इस हस्तांतरण में 'परिवार' की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि परिवार ही वह प्रथम पाठशाला है, जहां बालक अपने संस्कार, व्यवहार और मूल्यों को आत्मसात करता है। इसके पश्चात विद्यालय और महाविद्यालय इन गुणों को और अधिक परिष्कृत करते हैं।

वर्तमान युग तकनीक का युग है, जिसने ज्ञानार्जन के नए द्वार खोले हैं। इसके माध्यम से हम अपनी प्राचीन परंपराओं और ज्ञान को पुनः समझ सकते हैं। समाज के भी अनेक स्वरूप हैं-परंपरागत समाज, आधुनिक समाज, ग्रामीण समाज और नगरीय समाज। परंपरागत समाज में रीति-रिवाजों का कठोर पालन होता है, जबकि आधुनिक समाज तर्क और विज्ञान को प्राथमिकता देता है। ग्रामीण समाज सरलता और कृषि पर आधारित होता है, वहीं नगरीय समाज विविध व्यवसायों और तीव्र गति वाले जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। समाज हमें जीवन जीने की कला सिखाता है- बोलना, चलना, व्यवहार करना और सह-अस्तित्व का महत्व समझाता है। यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है, किंतु इसके सुचारु संचालन हेतु नियमों का पालन आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, वर्तमान समय में इन नियमों का ह्रास हो रहा है, जिससे समाज दिशाहीन होता जा रहा है।

इस दिशाहीनता के मूल में नैतिक मूल्यों का पतन है। पारिवारिक ढांचे में परिवर्तन, शिक्षा के स्वरूप में बदलाव तथा सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रभाव इसके प्रमुख कारण हैं। संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ गया है, जिससे बच्चों को दादा-दादी जैसे अनुभवी सदस्यों के संस्कार और मार्गदर्शन से वंचित रहना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप, उनमें सहनशीलता, त्याग और आदर जैसे गुणों का अभाव देखा जा रहा है। शिक्षा का उद्देश्य भी सीमित होकर केवल आजीविका अर्जन तक सिमट गया है।

जहां पहले गुरु-शिष्य संबंध अत्यंत पवित्र और आदर्श हुआ करता था, वहीं आज उसमें भी गिरावट देखने को मिलती है। शिक्षा, जो जीवन को दिशा देने वाली शक्ति थी, आज अपने मूल उद्देश्य से भटकती प्रतीत होती है। सोशल मीडिया ने युवाओं को गहराई से प्रभावित किया है। आभासी दुनिया में खोकर वे वास्तविकता से दूर हो रहे हैं। त्वरित सफलता की चाह में उनका संतुलन और जिम्मेदारी प्रभावित होती है।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

मुफ्त स्वास्थ्य जांच के बहाने डाटा की लूट डर दिखाकर मरीज बनाने का बढ़ता खेल

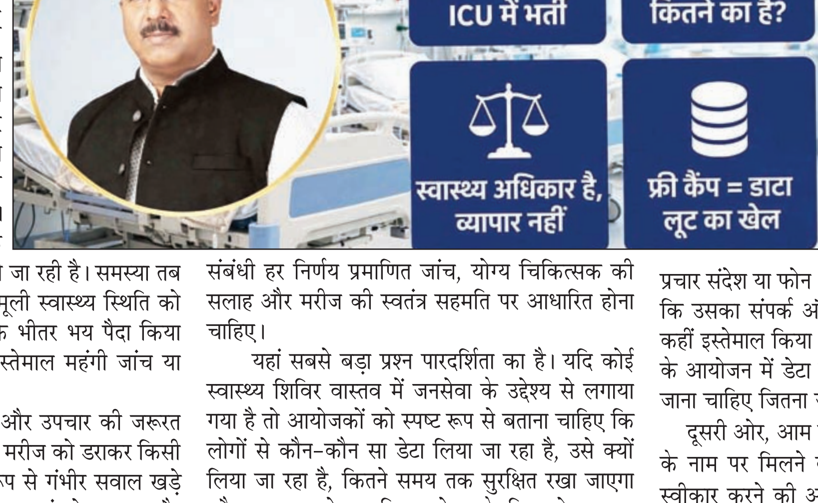

डॉ कौमार्या मनोज

आजकल महानगरों से लेकर छोटे शहरों और कस्बों तक जगह-जगह मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाते हैं। किसी बाजार के चौक पर, किसी आवासीय सोसायटी के सामुदायिक भवन में, किसी मंदिर परिसर में या किसी बड़े संस्थान के बाहर अचानक एक तंबू दिखाई देता है। उसके बाहर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा होता है—मुफ्त स्वास्थ्य जांच, मुफ्त नेत्र जांच, मुफ्त शुगर और रक्तचाप जांच या मुफ्त हृदय जांच। सामने मेज पर कुछ उपकरण रखे होते हैं। सफेद कोट पहने कर्मचारी लोगों की जांच करते दिखाई देते हैं और स्वागत कक्ष पर मौजूद कर्मचारी मुस्कुराते हुए लोगों से पंजीकरण करवाते हैं। पहली नजर में यह पूरा आयोजन समाजसेवा और जनकल्याण की मिसाल नजर आता है। लेकिन हर मुफ्त स्वास्थ्य शिविर को संदेह की नजर से देखना जरूरी नहीं होने के बावजूद यह सवाल जरूर उठना चाहिए कि इस मुफ्त सेवा की असली कीमत क्या है और लोगों से जुटाई जा रही निजी स्वास्थ्य जानकारी का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है।

स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी किसी भी व्यक्ति की बेहद निजी जानकारी होती है। उम्र, मोबाइल नंबर, पता, बीमारी का इतिहास, पहले से चल रही दवाएं, रक्तचाप, रक्त शर्करा, पारिवारिक बीमारियों का इतिहास और अन्य चिकित्सकीय विवरण किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इसलिए जब किसी शिविर में मुफ्त जांच के नाम पर इतनी विस्तृत जानकारी मांगी जाती है तो लोगों को बिना सोचे समझे हर जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। कई बार मुफ्त जांच कराने की उत्सुकता में लोग यह भूल जाते हैं कि उनके द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर और स्वास्थ्य संबंधी विवरण आगे चलकर प्रचार, फोन कॉल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकता है।

मामला तब गंभीर हो जाता है जब जांच के कुछ समय बाद व्यक्ति के पास लगातार फोन आने लगते हैं। उसे बताया जाता है कि उसकी रिपोर्ट में किसी गंभीर बीमारी के शुरुआती संकेत मिले हैं और उसे तत्काल किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति को आंखों की बीमारी का डर दिखाया जाता है तो किसी को रक्त शर्करा, हृदय या रक्तचाप को लेकर चिंतित किया जाता है। समस्या यह नहीं है कि जांच के बाद चिकित्सकीय सलाह क्यों दी जा रही है। समस्या तब पैदा होती है जब सामान्य या मामूली स्वास्थ्य स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर व्यक्ति के भीतर भय पैदा किया जाए और फिर उसी भय का इस्तेमाल महंगी जांच या उपचार के लिए किया जाए।

स्वास्थ्य क्षेत्र में जागरूकता और उपचार की जरूरत अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन मरीज को डराकर किसी सेवा की ओर धकेलना नैतिक रूप से गंभीर सवाल खड़े करता है। एक व्यक्ति जो सुबह तक स्वयं को सामान्य और स्वस्थ महसूस कर रहा था, यदि कुछ मिनट की बातचीत के बाद अचानक स्वयं को गंभीर रोगी समझने लगे तो यह स्थिति उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। इसके बाद जांचों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो सकती है। एक जांच के बाद दूसरी जांच, फिर विशेषज्ञ की सलाह और उसके बाद उपचार की सिफारिश। जरूरत होने पर चिकित्सा सुविधा लेना बिल्कुल उचित है, लेकिन चिकित्सा संबंधी हर निर्णय प्रमाणित जांच, योग्य चिकित्सक की सलाह और मरीज की स्वतंत्र सहमति पर आधारित होना चाहिए।

यहां सबसे बड़ा प्रश्न पारदर्शिता का है। यदि कोई स्वास्थ्य शिविर वास्तव में जनसेवा के उद्देश्य से लगाया गया है तो आयोजकों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि लोगों से कौन-कौन सा डेटा लिया जा रहा है, उसे क्यों लिया जा रहा है, कितने समय तक सुरक्षित रखा जाएगा और उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए होगा। क्या व्यक्ति को अपनी जानकारी साझा करने से इनकार करने का अधिकार है? क्या उसे बाद में अपना डेटा हटाने का विकल्प मिलेगा? क्या उसका मोबाइल नंबर किसी अन्य संस्था या व्यावसायिक एजेंसी के साथ साझा किया जाएगा? ऐसे सवालों के स्पष्ट जवाब होने चाहिए।

आज डिजिटल युग में स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का महत्व और बढ़ गया है। किसी व्यक्ति की बीमारी, दवा और चिकित्सकीय इतिहास जैसी जानकारी केवल कागज पर दर्ज आंकड़ा नहीं है। इसका दुरुपयोग व्यक्ति की निजता के लिए खतरा बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति को बार-बार बीमारी से संबंधित प्रचार संदेश या फोन आने लगें तो यह संदेह स्वाभाविक है कि उसका संपर्क और स्वास्थ्य संबंधी विवरण कहीं न कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन में डेटा सुरक्षा को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना जांच की गुणवत्ता को।

दूसरी ओर, आम नागरिकों को भी मुफ्त स्वास्थ्य जांच के नाम पर मिलने वाली हर सुविधा को बिना सवाल स्वीकार करने की आदत बदलनी होगी। जांच कराने से पहले यह जानना जरूरी है कि शिविर का आयोजन किस संस्था ने किया है, वहां जांच करने वाले स्वास्थ्यकर्मी कौन हैं और रिपोर्ट कौन जारी करेगा। यदि किसी जांच के बाद गंभीर बीमारी की आशंका बताई जाती है तो तुरंत घबराने के बजाय किसी स्वतंत्र और योग्य चिकित्सक से दूसरी राय लेना समझदारी होगी।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज

रीम शेख
जन्म : 8 सितंबर 2002

रीम शेख भारतीय टेलीविजन और हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हैं। 8 सितंबर 2002 को मुंबई में जन्मी रीम ने बेहद कम उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा और बाल कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। समय के साथ उन्होंने विभिन्न टेलीविजन धारावाहिकों, फिल्मों और मनोरंजन कार्यक्रमों में अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाकर अपनी अभिनय क्षमता साबित की। उनकी सहज अदाकारी और प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें युवा दर्शकों के बीच खास पहचान दिलाई।

रीम शेख ने महज आठ वर्ष की उम्र में धारावाहिक नीर भरे तेरे नैना देवी से अभिनय की शुरुआत की। बाल कलाकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने कैमरे के सामने आत्मविश्वास और अभिनय की बारीकियां सीखीं। वर्ष 2012 में वह मैं आज्जी और साहिब तथा ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे धारावाहिकों में नजर आईं। इसके बाद ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, खेलती है जिंदगी आंख मिचोली और दिया और बाती हम जैसे धारावाहिकों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं।

रीम को वास्तविक लोकप्रियता ऐतिहासिक धारावाहिक चक्रवर्ती सम्राट अशोक से मिली। इसमें उन्होंने युवा कौरवकी की भूमिका निभाई और सिद्धार्थ निगम के साथ अभिनय किया। उनके अभिनय को दर्शकों ने पसंद किया और इस भूमिका ने उन्हें टेलीविजन की उभरती हुई प्रतिभाओं में शामिल कर दिया। इसके बाद वर्ष 2018 में उन्होंने तू आशिकी में सनाया सेठ के रूप में अतिथि भूमिका निभाई।

वर्ष 2018 से 2021 तक रीम शेख ने तुझसे है राब्ता में कल्याणी मल्हार राणे की मुख्य भूमिका निभाई। इस धारावाहिक में उनके अभिनय को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली। उनकी मेहनत को पुरस्कारों के स्तर पर भी पहचान मिली और वर्ष 2019 में उन्हें मुख्य भूमिका में पदार्पण के लिए गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सफलता ने उनके अभिनय करियर को नई दिशा दी और वह टेलीविजन की प्रमुख युवा अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगीं। रीम शेख ने टेलीविजन तक खुद को सीमित नहीं रखा।

'भारतेन्दु शिखर'

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

सपा शासन में दलितों पर हुए सबसे ज्यादा अत्याचार: राकेश त्रिपाठी

एजेंसी, लखनऊ

समाजवादी पार्टी की ओर से अपने फ्रंटल संगठनों के लिए नीले रंग की ड्रेस तय किए जाने को लेकर भाजपा ने सपा पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि केवल रंग बदलने से दामन पर लगे दाग नहीं मिटेंगे। उन्होंने सपा पर दलितों को आकर्षित करने के लिए रंग बदलने का ढोंग करने का आरोप लगाया। राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी को 'रंगा सियार' बताते हुए कहा कि सपा की ओर से नीले रंग की ड्रेस तय करना दलित समाज को साधने की कोशिश है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता सपा की कथित राजनीति और उसकी असलियत से परिचित है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि केवल पहनावे या रंग में बदलाव करने से किसी राजनीतिक दल की छवि नहीं बदल सकती।

उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के कार्यकाल में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सपा के शासन में दलित समाज के साथ अन्याय की कई घटनाएं सामने आई थीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सपा की ओर से अंबेडकर स्मारक को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। राकेश त्रिपाठी ने सपा नेता आजम खान के पुराने बयान का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर को भूमाफिया बताया था। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे बयानों और पुराने रुख को जनता भूली नहीं है। उन्होंने कहा कि बार-बार रंग बदलने से राजनीतिक दल के पुराने आरोप और विवाद खत्म नहीं हो जाते। भाजपा ने सपा पर दलितों को लेकर दिखावटी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता समय आने पर इसका जवाब देगी।

न्यूज ब्रीफ

बाग में पेड़ से लटकता मिला अधेड़ का शव

एजेंसी, फतेहपुर। थाना औंग क्षेत्र के रामपुर गांव के बाहर सोमवार सुबह बाग में पेड़ से अधेड़ का शव लटकता मिला। ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान नीलू सिंह कछवाह (45) पुत्र गणपत सिंह कछवाह के रूप में हुई। ग्रामीणों के अनुसार सुबह करीब छह बजे रास्ते से गुजर रहे लोगों की नजर पेड़ पर लटके शव पर पड़ी। मृतक अविवाहित था। वह एक आंख से देख नहीं पाता था और उसका एक हाथ भी काम नहीं करता था। परिवार में उसका भाई सुनील सिंह है। सूचना पर थानाध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फतेहपुर भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मीरजापुरः सिवान में कपड़े में लिपटा मिला नवजात,ग्रामीणों ने बचाई जान

एजेंसी, मीरजापुर। मड़िहान थाना क्षेत्र के मलुआ गांव के सिवान में सोमवार सुबह खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों को नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो कपड़े में लिपटा नवजात पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटेहरा ले गई। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद नवजात को स्वस्थ बताया। नवजात मिलने की खबर से क्षेत्र में चर्चा फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनाई देती तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। थाना प्रभारी रविंद्र भूषण मौर्य ने बताया कि नवजात को सुरक्षित बरामद कर उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही बच्चे को सिवान में छोड़ने वाले व्यक्ति का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

गोरखपुर में श्मशान घाट के कई ढांचे असुरक्षित, नगर निगम ने लगाया बैनर

एजेंसी, गोरखपुर। राप्ती तट स्थित श्रीगोरक्ष घाट परिसर में गुंबद गिरने की घटना के बाद नगर निगम ने अन्य ढांचों की सुरक्षा जांच शुरू कर दी है। सोमवार को टीम ने श्रीराम और श्रीगोरक्ष घाट परिसर में बने गाजीबो तथा प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया। जांच के दौरान प्रवेश द्वार में हल्की दरार मिली। नगर आयुक्त अजय जैन के निर्देश पर अधिशासी अभियंता अशोक भाटी ने सहायक अभियंता और अवर अभियंता के साथ मौके पर पहुंचकर ढांचों की स्थिति का जायजा लिया। दरार मिलने के बाद प्रवेश द्वार के आसपास लोगों की आवाजाही को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। संभावित खतरे वाले स्थानों पर नगर निगम ने बैनर लगाकर लोगों से दूर रहने की अपील की है। निगम की टीम आगे भी परिसर के अन्य ढांचों की स्थिति पर नजर रखेगी।

कानपुर में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 20 सेंटीमीटर ऊपर

एजेंसी, कानपुर। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर सोमवार को फिर बढ़ गया। कानपुर बैराज पर गंगा 114.200 मीटर पर पहुंच गई, जो चेतावनी बिंदु 114 मीटर से 20 सेंटीमीटर अधिक है। बैराज के डाउनस्ट्रीम में जलस्तर 113.930 मीटर दर्ज किया गया, जबकि 3,59,202 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। रविवार की तुलना में अपस्ट्रीम में 24 और डाउनस्ट्रीम में 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। शुक्लागंज में भी गंगा का जलस्तर बढ़कर 112.640 मीटर पहुंच गया है। हरिद्वार बैराज से 1,21,147 और नरोरा बैराज से 99,297 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग निगरानी कर रहा है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने संवेदनशील और निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ाने तथा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं।

गोरखपुर राजघाट हादसाः गुंबद गिरने से दो अधिवक्ताओं की मौत

एजेंसी, गोरखपुर। राजघाट स्थित अंत्येष्टि स्थल पर रविवार को गुंबद ढहने से घायल दोनों अधिवक्ताओं की उपचार के दौरान मौत हो गई। अधिवक्ता आलोक अस्थाना ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि संजय सिंह की बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौत हुई। हादसे के बाद अधिवक्ता समाज में शोक और आक्रोश है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अंत्येष्टि स्थल के निर्माण कार्य की जांच के आदेश दिए हैं। कार्यदायी संस्था, संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका जांची जाएगी। रविवार को बारिश के दौरान गुंबद पर आकाशीय बिजली गिरने के बाद उसका हिस्सा भरभराकर नीचे गिरा था। मलबे में दबकर दोनों अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हुए थे। प्रत्यक्षदर्शी आलोक मिश्रा ने बताया कि हादसे से कुछ क्षण पहले वह गुंबद के नीचे से बाहर निकल आए थे। अधिवक्ताओं ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में एंबुलेंस की कथित देरी पर भी नाराजगी जताई।

जहरीली शराब के खिलाफ लगातार निगरानी जरूरी, तभी रोके जा सकेंगे हादसे

सागर हादसे से लखनऊ में फिर ताजा हुए पुराने शराब कांड

एजेंसी, लखनऊ

मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद राजधानी लखनऊ में भी पुराने शराब कांडों की खौफनाक यादें ताजा हो गई हैं। पिछले दो दशकों के दौरान लखनऊ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जहरीली तथा मिलावटी शराब कई परिवारों को उजाड़ चुकी है। बड़े हादसों के बाद प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन कुछ समय बाद निगरानी व्यवस्था फिर कमजोर पड़ती रही।

राजधानी में जहरीली शराब के कांडों का सिलसिला वर्ष 2003 में अमीनाबाद-कैसरबाग क्षेत्र से शुरू हुआ था। इसके बाद वर्ष 2015 में मलिहाबाद शराब कांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। वर्ष 2020 में बंथरा में सामने आए शराब कांड ने एक बार फिर अवैध और जहरीली शराब के कारोबार पर सवाल खड़े किए। इन हादसों में लोगों की जान जाने के बाद पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। जांच समितियां गठित हुईं और अवैध शराब के खिलाफ अभियान भी चलाए गए। हालांकि, इन अभियानों का असर लंबे समय तक कायम नहीं रह सका।

कुछ समय बाद अवैध शराब के कारोबार पर निगरानी ढीली पड़ती गई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री और निर्माण पर प्रभावी रोक लगाने की चुनौती बनी रही। सागर की घटना ने एक बार फिर इस व्यवस्था की खामियों और पुराने हादसों से सबक लेने की जरूरत को सामने ला दिया है। राजधानी में पूर्व में हुए शराब कांडों का अनुभव बताता है कि केवल हादसे के बाद कार्रवाई करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के नेटवर्क पर लगातार नजर रखने की जरूरत है।

इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र में जाकर स्थिति का जायजा लेना होगा। जहरीली शराब के मामलों में सबसे अधिक नुकसान उन परिवारों को उठाना पड़ता है, जिनके कमाने वाले सदस्य हादसों का शिकार होते हैं। ऐसे मामलों में परिवार आर्थिक और सामाजिक संकट में फंस जाते हैं। इसलिए प्रशासन के सामने केवल अवैध शराब पकड़ने की चुनौती नहीं, बल्कि संभावित हादसों को पहले ही रोकने की जिम्मेदारी भी है।

सागर हादसे के बाद लखनऊ में उठी चिंता इसी पुराने अनुभव से जुड़ी है। अधिकारियों को दफ्तरों तक सीमित रहने के बजाय क्षेत्र में सक्रिय निगरानी बढ़ानी होगी। अवैध शराब के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई और स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत करने से ही ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है।

बरेली में रिकॉर्डतोड़ बारिश, मानसून सीजन में पहली बार 381.1 मिलीमीटर

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ कई जिलों में बारिश का दौर तेज हो गया है। बीते 24 घंटों के दौरान बरेली और शाहजहांपुर में बारिश ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बरेली में 381.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो मानसूनी सीजन के दौरान अब तक की सर्वाधिक बारिश बताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, इससे पहले मानसून के किसी सीजन में बरेली में इतनी अधिक वर्षा दर्ज नहीं हुई थी।

मौसम में आए बदलाव के पीछे उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम और मध्य प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से के ऊपर बना मौसम तंत्र प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसके प्रभाव से क्षेत्र में वर्षा की तीव्रता बढ़ी है और कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। लगातार हुई तेज बारिश से बरेली और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

शाहजहांपुर में भी बारिश ने पुराने आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आने वाले घंटों में भी कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम तंत्र की सक्रियता के कारण वर्षा का दौर जारी रहने की उम्मीद है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।

लखनऊ में चौंकाने वाला मामला, अंतिम संस्कार के 28 महीने बाद जिंदा लौटी महिला

एजेंसी, लखनऊ

राजधानी लखनऊ में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिस महिला को परिवार ने मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, वह करीब 28 महीने बाद अचानक जिंदा अपने मायके पहुंच गई। महिला को सामने देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने भी महिला से पूछताछ शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, 28 वर्षीय शिवानी पांच सितंबर को बीकेटी तहसील क्षेत्र के नवीकोट नंदना गांव स्थित अपने मायके पहुंची। परिवार ने जब उसे देखा तो सभी हैरान रह गए। परिजनों के मुताबिक, करीब डेढ़ वर्ष पहले आईआईएम रोड के पीछे नाले में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। मायकेवालों ने उसकी पहचान शिवानी के रूप में की थी। इसके बाद शव का भैंसाकुंड में अंतिम संस्कार कर दिया गया था।

शिवानी के जिंदा मिलने के बाद पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो गए हैं। बताया गया कि विवाहिता के ससुरालवालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। वहीं, पुलिस के अनुसार शिवानी पारा क्षेत्र में अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। अब पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है कि नाले में मिला शव किस महिला का था और उसकी पहचान शिवानी के रूप में कैसे हुई।

कानपुर में बहू ने छह लाख की सुपारी देकर ससुर को मरवाया

एजेंसी, कानपुर

दवा कारोबारी विपिन मिनोचा हत्याकांड में पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कारोबारी की बहू शालू पर ही ससुर की हत्या की साजिश रचने का आरोप सामने आया है। बताया गया कि शालू ने अपने पूर्व नौकर विशाल गौतम को छह लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या करवाई।

पूछताछ में सामने आया कि वह ससुर की निगरानी और घर में कई तरह की पाबंदियों से परेशान थी। पुलिस के अनुसार, शालू ने पूर्व नौकर विशाल से संपर्क कर ससुर की हत्या की योजना बनाई। उसे हत्या के बदले छह लाख रुपये देने की बात कही गई। इतना ही नहीं, शालू ने विशाल को यह भी कहा था कि यदि वह पुलिस की पकड़ में आ जाए तो उसका नाम न बताए और पूछताछ में उसके पति सुब्रत का नाम ले।

जांच में यह बात भी सामने आई कि शालू अपने ससुर द्वारा घर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से परेशान थी। परिवार के भीतर उसकी गतिविधियों पर नजर रखे जाने को लेकर वह नाराज थी। बताया गया कि मनपसंद कपड़े पहनने जैसी बातों को लेकर भी उस पर रोक-टोक की जाती थी। इन्हीं परिस्थितियों के चलते उसने ससुर की हत्या की साजिश रचने का फैसला किया।

मामला कानपुर के कल्याणपुर स्थित रतन आर्बिट अपार्टमेंट का है। शनिवार रात दवा कारोबारी विपिन मिनोचा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। घटना के समय घर में कारोबारी अकेले थे। रात करीब तीन बजे बेटा और बहू पार्टी से वापस लौटे तो विपिन मिनोचा बेडरूम में खून से लथपथ पड़े मिले। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अपार्टमेंट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में दो युवक फ्लैट की ओर जाते और कुछ समय बाद वहां से बाहर निकलते दिखाई दिए। इससे पुलिस को हत्या में बाहरी लोगों की संलिप्तता का सुराग मिला। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ की और हत्या की साजिश से जुड़े लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया। पूछताछ में बहू शालू की भूमिका सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया।

◆ **पुलिस** जांच में सामने आया कि शालू ने हत्या की साजिश रचने के बाद विशाल को वारदात के तरीके और पकड़े जाने पर पति सुब्रत का नाम लेने की हिदायत दी थी। पुलिस अब मामले में अन्य आरोपितों की भूमिका और छह लाख रुपये के लेनदेन की भी जांच कर रही है। पुलिस ने शालू से पूछताछ के आधार पर विशाल की तलाश तेज कर दी और कई संदिग्धों से पूछताछ शुरू की।

मायावती ने दिल्ली और मध्य प्रदेश की घटनाओं पर जताई चिंता

एजेंसी, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली और मध्य प्रदेश में हुई घटनाओं में लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इन हादसों को लेकर शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि दक्षिण दिल्ली में पांच मंजिला पीजी हॉस्टल ढहने से पांच लोगों की मौत हुई है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत और करीब 190 लोगों के बीमार होने का भी उल्लेख किया। मायावती ने कहा कि अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों का इलाज चलना चिंताजनक है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में बाढ़ से जान-माल के नुकसान की खबरों को भी उन्होंने दुखद और चिंताजनक बताया। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं शासन-प्रशासन की जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने कहा कि जनहित और जनकल्याण के लिए सरकारों को अधिक सक्रिय और जिम्मेदार होने की आवश्यकता है।

विधायक डॉ नीलकंठ ने किया वार्ड प्रवास सीवर पाइप बदलने के दिया निर्देश

एजेंसी, वाराणसी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कोनिया में दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने सोमवार को वार्ड प्रवास के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। 76 दिवसीय वार्ड प्रवास के तहत विधायक ने श्री काशी विश्वनाथ मंडल के कोनिया वार्ड का दौरा किया और स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। विधायक ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियों की जानकारी ली।

उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का तत्काल प्रभाव से निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान दो कुओं के संरक्षण और सुंदरीकरण के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। विधायक ने क्षेत्र में खराब सीवर और पानी की पाइपलाइन की समस्या का भी संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों से वार्ता कर खराब सीवर और पानी की पाइप बदलने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वार्ड भ्रमण के दौरान कुछ स्थानों पर कूड़ा पड़ा देखकर विधायक ने स्वयं झाड़ू लगाकर सफाई की। उन्होंने आसपास रहने वाले लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। विधायक ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में साफ-सफाई बेहद जरूरी है। गंदगी रहने से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी अधिकारियों के साथ स्थानीय जनता की भी है। सभी को मिलकर स्वच्छता व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।

रूस में फंसा कानपुर का युवक, पत्नी को जबरन सेना में भेजे जाने की आशंका

◆ **कानपुर के चंदन गुप्ता रूस में हिरासत में, पत्नी ने सेना में जबरन भर्ती का जताया डर**

एजेंसी, कानपुर

रूस की राजधानी मॉस्को में कानपुर के चंदन गुप्ता को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया है। चंदन रूस में हाई-क्वालिफाइड वीजा पर रह रहे थे। उनकी गिरफ्तारी की जानकारी सामने आने के बाद परिवार की चिंता बढ़ गई है। पत्नी स्नेहा गुप्ता ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। स्नेहा गुप्ता ने आशंका जताई है कि उनके पति को रूस की सेना में जबरन भर्ती किया जा सकता है।

उन्होंने सरकार से चंदन की स्थिति स्पष्ट कराने और उनकी सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित कराने के लिए मदद मांगी है। परिवार के अनुसार, चंदन के मॉस्को में हिरासत में लिए जाने के बाद उनके भविष्य को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। परिवार का कहना है कि चंदन रूस में रोजगार के सिलसिले में रह रहे थे और उनके पास हाई-क्वालिफाइड वीजा था। ऐसे में अचानक पुलिस हिरासत में लिए जाने की खबर ने परिजनों को परेशान कर दिया है। पत्नी ने संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी जुटाने और आवश्यक कूटनीतिक हस्तक्षेप करने की मांग की है।

स्नेहा का कहना है कि परिवार इस समय बेहद चिंतित है और उन्हें चंदन की सुरक्षा को लेकर आशंका है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से अपील की है कि रूसी अधिकारियों से संपर्क कर मामले की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए तथा यदि चंदन को किसी प्रकार की जबरन सैन्य भर्ती का खतरा है तो उन्हें उससे बचाया जाए। परिवार ने भारत सरकार से चंदन को जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की गुहार लगाई है।

मृत्युदंड पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को मृत्युदंड, अदालत ने कहा- हमसफर ही बना कातिल

जिसे माना था महफूज ठिकाना, उसी पति ने छीन ली पत्नी की जिंदगी

एजेंसी, मुजफ्फरनगर

पत्नी शहजादी की हत्या के दोषी पति नदीम को न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने महिला की गरिमा, स्वतंत्रता और मानवीय पहचान को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि महिला का जीवन केवल उसकी शारीरिक उपस्थिति तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसके साथ उसकी गरिमा और स्वतंत्रता भी जुड़ी होती है।

न्यायालय ने अपने फैसले में पति-पत्नी के रिश्ते की संवेदनशीलता का उल्लेख करते हुए कहा कि निकाह को रहमत, साथ और अमानत का रिश्ता माना जाता है। शहजादी ने भी इसी भरोसे के साथ इस रिश्ते को अपनाया था, लेकिन जिस व्यक्ति को उसने अपना हमसफर और सुरक्षित ठिकाना समझा, वही उसकी जिंदगी का कातिल बन गया। अदालत की इस टिप्पणी ने मामले की गंभीरता को सामने रखा।

फैसले के दौरान न्यायाधीश ने प्रेम और दांपत्य संबंधों के संदर्भ में ऐतिहासिक प्रेम कहानियों का भी उल्लेख किया। अदालत ने लैला-मजनू और शीरी-फरहाद जैसी प्रेम कहानियों का जिक्र करते हुए पति-पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण के महत्व को रेखांकित किया। अदालत ने कहा कि विवाह का रिश्ता विश्वास और सुरक्षा पर आधारित होता है। ऐसे रिश्ते में महिला के साथ हिंसा और उसकी जान लेना बेहद गंभीर अपराध है। शहजादी की हत्या के मामले में न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी नदीम को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

न्यायालय के फैसले के बाद मामले में पीड़िता को न्याय मिलने की बात सामने आई है। अदालत ने अपने निर्णय के माध्यम से यह संदेश भी दिया कि वैवाहिक रिश्ते में महिला की गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा का सम्मान किया जाना आवश्यक है। पति द्वारा पत्नी की हत्या जैसे गंभीर अपराध को किसी भी स्थिति में सामान्य नहीं माना जा सकता। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि वैवाहिक संबंध में विश्वास, सम्मान और सुरक्षा का विशेष महत्व है। महिला के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा उसके अधिकारों और गरिमा का उल्लंघन है। न्यायालय ने दोषी पति को मृत्युदंड देकर गंभीर अपराधों के प्रति कठोर रुख का संदेश दिया।

महिला सम्मान पर अदालत का सख्त संदेश

अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी महिला के जीवन, सम्मान और स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। वैवाहिक संबंध विश्वास और जिम्मेदारी पर टिके होते हैं, इसलिए पति-पत्नी के बीच हिंसा को किसी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दंड तय किया जाना आवश्यक है। मृत्युदंड के फैसले से समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा के खिलाफ कड़ा संदेश गया है। परिवार ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए संतोष व्यक्त किया।न्यायालय ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

दहशत का सबब बना तेंदुआ पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

एजेंसी, बहराइच

◆ **आधा दर्जन मवेशियों का शिकार करने वाला तेंदुआ पकड़ा गया**

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में करीब 15 दिनों से ग्रामीणों के लिए दहशत का कारण बने तेंदुए को आखिरकार वन विभाग की टीम ने सोमवार तड़के पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही गोकुलपुर गांव और आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

मामला कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज अंतर्गत गोकुलपुर गांव का है। ग्रामीणों के अनुसार, पिछले कई दिनों से तेंदुए की गांव और आसपास के इलाकों में लगातार आवाजाही हो रही थी। तेंदुए के हमले में करीब आधा दर्जन मवेशियों की जान जा चुकी थी। इसके अलावा गांव के आसपास कई बार तेंदुए के पैरों के निशान भी मिले थे। इससे ग्रामीणों में लगातार भय बना हुआ था। दहशत का आलम यह था कि लोग अकेले खेतों की ओर जाने से भी बच रहे थे। ग्रामीणों की शिकायतों और तेंदुए की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए गोकुलपुर गांव में पिंजरा लगाया था। सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे तेंदुआ पिंजरे में फंस गया।

तेंदुए के पिंजरे में कैद होने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला और उसे सेफ हाउस पहुंचाया। डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि तेंदुए की लगातार निगरानी की जा रही है। उसके स्वास्थ्य और व्यवहार की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तलाक मांगने पर पत्नी की हत्या पति ने चाकू से किए कई वार

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला

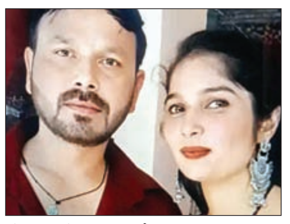

अंबाला में एक पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी के पेट और छाती पर चाकू से कई वार किए। गंभीर रूप से घायल महिला को परिजन अंबाला शहर के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

मृतका की पहचान हीना के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हीना और बंटी की शादी करीब 13 साल पहले हुई थी। दोनों के दो बच्चे भी हैं। परिवार के अनुसार, पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। हीना तलाक लेना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती थी। हीना के भाई ने आरोप लगाया कि बंटी उसकी बहन के चरित्र पर शक करता था। जब भी हीना का फोन व्यस्त आता था, तो आरोपी उसके साथ मारपीट करता था। परिवार का कहना है कि घरेलू विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच शराब के नशे में आरोपी ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया।

हमले के बाद घर में चीख-पुकार मच गई। परिजनों और आसपास के लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। मामले में परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस आरोपी की तलाश के साथ हत्या के कारणों की भी गहनता से जांच कर रही है।

घर लौट रहे युवक को बाइक ने मारी टक्कर, तीन बच्चों के पिता की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर। यमुनानगर जिले के बुड़िया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाने के कारण हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब युवक बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रही दूसरी बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायल को संभाला और घटना की सूचना उसके परिजनों को दी। परिजन उसे उपचार के लिए यमुनानगर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक तीन बच्चों का पिता बताया जा रहा है। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर मारने वाली बाइक तेज रफ्तार में थी। हादसे के बाद उसका चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया।

सूचना मिलने पर बुड़िया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे प्रतिष्ठानों और अन्य संभावित स्थानों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि फरार बाइक सवार की पहचान की जा सके। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज करने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे में शामिल बाइक और उसके चालक का पता लगाने के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान होने के बाद उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया भी की जा रही है। पुलिस ने बताया कि हादसे की परिस्थितियों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। फरार बाइक सवार की पहचान के लिए आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस जल्द आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। परिजनों से घटना से जुड़ी अन्य जानकारी भी ली जा रही है।

शुगर मिल एमडी को डीसी अकेले नहीं हटा सकते, हाई कोर्ट का अहम फैसला

हाई कोर्ट ने सोनीपत सहकारी चीनी मिल के एमडी पर हुई विभागीय कार्रवाई को रद्द कर दिया

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनीपत सहकारी चीनी मिल के प्रबंध निदेशक के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई को रद्द करते हुए सहकारी संस्थाओं में अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी सहकारी संस्था में सरकारी हिस्सेदारी होने या किसी अधिकारी के पद पर होने मात्र से उसे संस्था के वैधानिक अधिकारों से अधिक शक्ति हासिल नहीं हो जाती।

हाई कोर्ट के इस फैसले से सोनीपत सहकारी चीनी मिल के प्रबंध निदेशक को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र से जुड़ा मामला मानते हुए रद्द कर दिया। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रबंध निदेशक के खिलाफ कार्रवाई करने या उन्हें पद से हटाने का अधिकार निर्धारित प्रक्रिया और संस्था के सक्षम प्रबंधन निकाय के पास है।

अदालत ने कहा कि सहकारी चीनी मिल जैसी संस्था अपने निर्धारित नियमों और कानून के अनुसार संचालित होती है। इसमें सरकारी प्रतिनिधियों या अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इससे उन्हें संस्था के वैधानिक अधिकारों को अपने स्तर पर बदलने या किसी पदाधिकारी के खिलाफ मनमाने ढंग से कार्रवाई करने का अधिकार नहीं मिल जाता।

सोनीपत सहकारी चीनी मिल के मामले में प्रबंध निदेशक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई थी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह सवाल उठा कि क्या उपायुक्त या शुगरफेड के अधिकारी अपने स्तर पर मिल के प्रबंध निदेशक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। अदालत ने संबंधित प्रावधानों और अधिकार क्षेत्र पर विचार करने के बाद कार्रवाई को उचित नहीं माना। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू को भी रेखांकित किया।

अदालत ने कहा कि सरकार की हिस्सेदारी या किसी अधिकारी का प्रशासनिक पद अपने आप में उसे संस्था के प्रबंधन संबंधी सभी अधिकार नहीं देता। अधिकारियों को वही शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो कानून, नियमों और संस्था के उपनियमों के तहत निर्धारित हैं। फैसले के बाद यह स्पष्ट संदेश गया है कि सहकारी संस्थाओं में पदाधिकारियों और प्रबंधकीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। केवल प्रशासनिक पद या सरकारी प्रतिनिधित्व के आधार पर किसी अधिकारी को अतिरिक्त अधिकार नहीं दिए जा सकते।

नारनौल में सड़क हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, नारनौल

सदर थाना क्षेत्र के मित्रपुरा के पास सड़क हादसे में बाइक सवार महिला गुलशन की मौत हो गई। वह अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर नारनौल आ रही थी। इसी दौरान क्रीम रंग की अज्ञात कार ने उनकी बाइक को साइड से टक्कर मार दी। हादसे में गुलशन गंभीर रूप से घायल हो गई।

आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि टक्कर मारने वाली कार की पहचान की जा सके।

पुलिस के अनुसार, कार क्रीम रंग की बताई जा रही है। इसी आधार पर आसपास के मार्गों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसे के समय कार किस दिशा से आ रही थी और घटना के बाद चालक किस रास्ते से फरार हुआ। हादसे में महिला की मौत से परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

एमएसपी-कर्जमाफी की मांग को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन, 26 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार

राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रविवार को किसान-मजदूर क्रांतिकारी मान पार्क में किसान और मजदूर एकत्रित हुए। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने हिसार सांसद जयप्रकाश जेपी, नलवा विधायक रणधीर पनिहार, बरवाला विधायक रणबीर गंगवा और हिसार विधायक सावित्री जिंदल को किसानों-मजदूरों की विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

मोर्चा नेताओं ने सभी फसलों के लिए सी2 के आधार पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की खरीद की गारंटी देने की मांग की। इसके अलावा किसानों और मजदूरों की व्यापक कर्जमाफी तथा आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई। किसान नेताओं ने भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते सहित सभी मुक्त व्यापार समझौतों को रद्द करने की मांग की।

उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों और आंदोलन करने के अधिकार पर किसी भी तरह का दमन बंद करने तथा धर्म के नाम पर नफरत और विभाजन की राजनीति समाप्त करने की बात कही। मोर्चा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 26 नवंबर से विशाल और निरंतर देशव्यापी किसान संघर्ष दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने, न्यूनतम मजदूरी 31 हजार रुपये करने और मनरेगा में 200 दिन काम के साथ 700 रुपये दैनिक मजदूरी देने की मांग रखी गई।

ज्ञापन में बिजली के निजीकरण पर रोक लगाने, बीज विधेयक वापस लेने, जबरन भूमि अधिग्रहण रोकने तथा किसानों, आदिवासियों और वनवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा की मांग भी शामिल रही।

माथा टेकने जा रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने कुचला, मौत

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल। करनाल के डाचर-जलमाणा रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 72 वर्षीय बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग करीब 15 फीट दूर खेत में जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और घटना की सूचना परिजनों को दी। मृतक की पहचान बुटा सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह बाइक पर सवार होकर गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में तेज गति से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह उछलकर सड़क किनारे खेत में जा गिरे। हादसे के बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हुड्डा के आरोपों पर जेपी दलाल का जवाब बोले- भाजपा राज में लगीं दोगुनी नौकरियां

भारतेन्दु संवाददाता, भिवानी

भिवानी शहर के सेक्टर-13 स्थित अपने आवास पर हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की ओर से भाजपा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार किया। जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार की तुलना में दोगुनी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने दावा किया कि युवाओं को योग्यता और पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां भी जाते हैं, वहां विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास करवाना है। भिवानी जिले में भी कई महत्वपूर्ण विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।

जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को भाजपा सरकार के काम दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस शासनकाल में रोजगार और विकास को लेकर किए गए दावों की तुलना मौजूदा सरकार के कामकाज से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं के हित में कई फैसले लिए हैं और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की है।

चरित्र पर शक में पति ने पत्नी को छुरी से गोदा, दो बच्चों से छिना मां का साया

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला

बलदेव नगर थाना क्षेत्र के गुरु नानक नगर में रविवार शाम चरित्र पर शक के चलते एक पति ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी की छुरी से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या और आपराधिक धमकी की धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान बंटी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार शाम शराब के नशे में उसका पत्नी हिना के साथ विवाद हो गया। विवाद के दौरान आरोपी ने रसोई से छुरी उठाई और पत्नी के पेट, छाती तथा कोहनी पर कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल हिना की मौत हो गई। घटना के दौरान पत्नी को बचाने पहुंचे उसके भाई नन्नू को भी आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। वारदात के बाद वह वहां से फरार हो गया। नन्नू ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी बहन हिना की शादी करीब 13 वर्ष पहले बहादुरगढ़ निवासी बंटी पुत्र अशोक के साथ हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं।

इनमें 11 वर्ष का बेटा और नौ वर्ष की बेटी है। परिवार पिछले करीब तीन महीने से गुरु नानक नगर स्थित मकान नंबर 19-सी में किराये पर रह रहा था। नन्नू के मुताबिक बंटी एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है और पिछले कुछ समय से हिना के चरित्र पर शक करता था। वह अक्सर उसके फोन व्यस्त मिलने पर विवाद करता था। इसी शक को लेकर दोनों के बीच कई बार कहासुनी भी हुई थी। रविवार को भी इसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ, जिसके बाद बंटी ने गुस्से में छुरी से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस हत्या के कारणों और वारदात से पहले हुए विवाद की पूरी जानकारी जुटाने में लगी है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले में और तथ्य सामने आने की संभावना है।

फरीदाबाद में छात्रा को बाइक ने मारी टक्कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद

करनेरा चौक पर छह दिन पहले बाइक की टक्कर से घायल हुई छात्रा के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। छात्रा के पिता नितेश कुमार का आरोप है कि पुलिस आरोपी बाइक सवार को तलाशने के बजाय उनसे ही उसका सुराग और बाइक का नंबर मांग रही है। उनका कहना है कि हादसे की पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। इसके बावजूद पुलिस फुटेज की मदद से आरोपी तक पहुंचने के प्रयास नहीं कर रही है।

नितेश कुमार ने बताया कि 30 अगस्त को उनकी बेटी करनेरा बालाजी कॉलोनी स्थित धर्म मेडिकल के पास से सब्जी लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि छात्रा की जांघ की हड्डी टूट गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर जांघ में राड डाली। पीड़ित परिवार का कहना है कि हादसे के बाद से बेटी दर्द से परेशान है और उसके इलाज में काफी खर्च हो रहा है। ऐसे समय में पुलिस से आरोपी को जल्द पकड़ने और परिवार को न्याय दिलाने की उम्मीद थी।

लेकिन पुलिस द्वारा बाइक सवार का नंबर और अन्य जानकारी मांगने से परिवार की परेशानी और बढ़ गई है। पिता का कहना है कि जब हादसा सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुआ है तो पुलिस फुटेज खंगालकर बाइक सवार की पहचान कर सकती है। उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। करणेरा चौक हादसे में घायल छात्रा के पिता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के बावजूद आरोपी बाइक सवार की तलाश नहीं हुई।

यूके में नौकरी का झांसा देकर ठगी की आरोपी महिला दिल्ली से गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद। यूके भेजने और वहां नौकरी दिलाने का झांसा देकर 9 लाख 31 हजार 500 रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में साइबर क्राइम थाना फतेहाबाद पुलिस ने दिल्ली से एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान उत्तर-पश्चिम दिल्ली के शकूरपुर आनंदवास निवासी पूजा के रूप में हुई है। पुलिस उससे पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। साइबर क्राइम थाना फतेहाबाद के प्रभारी निरीक्षक राहुल देव ने बताया कि टोहाना तहसील के गांव डांगरा निवासी मंजीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार कुछ समय पहले उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से जान-पहचान हुई थी। बातचीत के दौरान युवती ने बताया कि उसका परिचित यूके में बड़ा कारोबार करता है और वहां भारतीय युवकों को नौकरी की जरूरत है।

झांसे में आकर मंजीत और उसके रिश्तेदार यूके जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद विदेश भेजने, दस्तावेज प्रक्रिया और हवाई टिकट के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में कुल 9 लाख 31 हजार 500 रुपये जमा करवाए गए। रकम मिलते ही आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया और इंस्टाग्राम खाता भी हटा दिया। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत की। 25 जून को मामला दर्ज कर पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों और बैंक खातों की जांच के आधार पर पूजा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने बैंक खातों की जांच के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार किया, पूछताछ में अन्य आरोपियों का पता लगाया जा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

करनाल में अंतरजातीय विवाह पर युवती ने उठाए सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल। करनाल के तरावड़ी में आयोजित अनिरुद्धाचार्य की कथा के दौरान प्रश्नोत्तरी में एक युवती ने अंतरजातीय प्रेम विवाह को लेकर सवाल किया। युवती ने बताया कि वह ब्राह्मण परिवार से है और अनुसूचित जाति के युवक से उसके रिश्ते को लेकर उसकी मां नाराज है। युवती ने परिवार की सहमति और रिश्ते को लेकर अपनी चिंता रखी। इस पर अनिरुद्धाचार्य ने प्रेम को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रेम किसी से भी हो सकता है। उन्होंने युवती को विवाह से पहले सामने वाले की पहचान और परिवार की पृष्ठभूमि जांचने की सलाह दी।

अलॉय व्हील डलवाकर ट्रायल के बहाने कार लेकर युवक फरार

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में अलॉय व्हील डलवाने के बाद 'ट्रायल' के बहाने काले रंग की वरना कार लेकर युवक फरार हो गया। घटना सेक्टर-12ए की ऑटोमोबाइल मार्केट स्थित 'सिद्धदाता टायर्स' में हुई। दुकान मालिक दीपक चौधरी ने सेक्टर-14 थाने में शिकायत देकर सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल किया और आरोपी की जानकारी देने वाले को 5 हजार इनाम देने की घोषणा की। मामला वायरल होने के बाद आरोपी के परिजन गुरुग्राम पहुंचे और दुकानदार से माफी मांगी। दोनों पक्षों में समझौता हुआ और परिजनों ने करीब 1.20 लाख की पूरी रकम चुकाने पर सहमति जताई।

कैथल में छह पे रोल कर्मचारी टर्मिनेट, दरोगा सस्पेंड; सफाई व्यवस्था चरमराई

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल। शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने के मामले में नगर परिषद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। परिषद ने छह पे रोल कर्मचारियों को टर्मिनेट करने के आदेश जारी किए हैं, जबकि एक पक्के कर्मचारी दरोगा को सस्पेंड किया गया है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की ओर से यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि संबंधित कर्मचारियों को पहले नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा कई कर्मचारी ड्यूटी से गैरहाजिर पाए गए, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई और सड़कों पर जगह-जगह कूड़े के ढेर लग गए। कार्रवाई के बाद सफाई कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अपनी मांगें प्रशासन के सामने रखीं। परिषद प्रशासन ने सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं।

भिवानी में सीवर संकट गहराया दूषित पानी से लोग बेहाल

भारतेन्दु संवाददाता, भिवानी। शहर के वार्ड नंबर 27 में पिछले करीब चार वर्षों से सीवर जाम की समस्या बनी हुई है। सीवर का गंदा पानी बिना बारिश के ही गलियों में बह रहा है और कई घरों तक पहुंच रहा है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूषित पानी के कारण जनस्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि समस्या लंबे समय से बनी होने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ। क्षेत्र के पार्षद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त से शिकायत की है। उन्होंने सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त कर लोगों को राहत दिलाने की मांग की है।

50 हजार आबादी के लिए सेक्टर-20 डिस्पेंसरी को 24 घंटे अस्पताल बनाने की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला

सेक्टर-20 और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली 50 हजार से अधिक आबादी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग तेज हो गई है। स्थानीय लोगों की जरूरत को देखते हुए सेक्टर-20 स्थित सरकारी डिस्पेंसरी को 24 घंटे चिकित्सा सुविधा वाले अस्पताल के रूप में अपग्रेड करने की मांग उठाई गई है। वर्तमान में डिस्पेंसरी में सीमित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने के कारण आपात स्थिति में लोगों को नागरिक अस्पताल का रुख करना पड़ता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सेक्टर-20 और आसपास के क्षेत्रों में आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा स्वास्थ्य केंद्र पर दबाव भी बढ़ गया है। रात के समय अचानक बीमारी या किसी आपात स्थिति में तत्काल उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से मरीजों और उनके स्वजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पताल तक ले जाने में समय लगने से स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

नगर पार्षद राकेश गोयल ने इस संबंध में सांसद रेखा शर्मा को पत्र सौंपकर सेक्टर-20 की सरकारी डिस्पेंसरी को 24 घंटे संचालित करने और अस्पताल के रूप में विकसित करने की मांग की है। उनका कहना है कि क्षेत्र की बड़ी आबादी को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस दिशा में जल्द कदम उठाए जाने चाहिए। मांग में डिस्पेंसरी को आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं से लैस करने, चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा आपातकालीन सेवाएं शुरू करने पर जोर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल बनने से सेक्टर-20 के साथ आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी लाभ मिलेगा।

लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन और सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे। 50 हजार से अधिक आबादी की स्वास्थ्य जरूरतों को देखते हुए डिस्पेंसरी के विस्तार और चौबीसों घंटे चिकित्सा सुविधा शुरू होने से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहतर हो सकती है। प्रशासन की मंजूरी के बाद यहां मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर और समय पर उपचार मिल सकेगा।

डीजीपी अश्विंदर चावला ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जरूरी

हांसी में विजिलेंस की नई यूनिट शुरू, रिश्वतखोरों पर बढ़ेगा शिकंजा

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार

हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई लगातार जारी है। हांसी में नई विजिलेंस यूनिट के उद्घाटन के दौरान हरियाणा विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक अश्विंदर चावला ने कहा कि भ्रष्टाचार जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई और निगरानी जरूरी है। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई पूछे कि आज नहाने का क्या फायदा, कल फिर गंदे हो जाएंगे, तो इसका जवाब यही है कि सफाई रोज करनी पड़ती है। इसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ भी नियमित रूप से कार्रवाई करनी होगी।

डीजीपी चावला ने बताया कि विजिलेंस की ओर से इस वर्ष अब तक 133 से अधिक सफल कार्रवाई की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में बड़ी रकम के मामलों के साथ छोटी रिश्वत के मामलों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा आम लोगों से रिश्वत मांगना व्यवस्था के प्रति विश्वास को प्रभावित करता है, इसलिए ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हांसी में नई विजिलेंस यूनिट शुरू होने से क्षेत्र में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई और निगरानी को गति मिलने की उम्मीद है।

अधिकारियों के अनुसार, स्थानीय स्तर पर यूनिट उपलब्ध होने से शिकायतों की जांच और आवश्यक कार्रवाई में सुविधा होगी। विजिलेंस अधिकारियों को आम लोगों से मिलने वाली शिकायतों पर तत्परता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। चावला ने कहा कि भ्रष्टाचार को केवल कार्रवाई के जरिए ही खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए व्यवस्था में लगातार सुधार और अधिकारियों-कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखना भी आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी काम के बदले रिश्वत मांगता है तो इसकी सूचना विजिलेंस को दें। डीजीपी ने बताया कि शिकायत प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए जल्द ही मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से लोग भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें आसानी से दर्ज करा सकेंगे। इससे शिकायतों तक पहुंच बढ़ाने और कार्रवाई की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में सहयोग करने वाले गवाहों को सम्मान दिया जाएगा। विजिलेंस का उद्देश्य केवल आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों में यह विश्वास पैदा करना भी है कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर उनकी बात सुनी जाएगी और उचित कार्रवाई होगी। डीजीपी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए विजिलेंस के साथ आम लोगों का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को सक्रिय रहने और शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

न्यूज ब्रीफ

अवैध इमारतों की गिनती में निगम सुस्त तीन महीने बाद भी सर्वे पूरा नहीं

एजेंसी, नई दिल्ली। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर नगर निगम अधिकारियों की सुस्ती सामने आई है। तीन माह पहले बिना नक्शे के बने भवनों का सर्वे पूरा करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक गिनती पूरी नहीं हो सकी है। जून में लखनऊ में बिना नक्शे के बने भवन में आग लगने की घटना के बाद तत्कालीन नगर निगम आयुक्त ने फरीदाबाद में भी ऐसे भवनों का सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद सर्वे की रफ्तार बेहद धीमी है। एनआईटी जोन में अब तक केवल 22 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं। अन्य जोन में भी सर्वे पूरा नहीं हुआ है। इससे निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। नए आयुक्त ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई तेज करने का आश्वासन दिया है।

तेज रफ्तार पर भारी पड़ा गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का अभियान, 6231 चालान से जुटे 1.24 करोड़

एजेंसी, नई दिल्ली। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अगस्त में तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। एक से 31 अगस्त तक चले अभियान में 6,231 वाहन चालकों के चालान किए गए और करीब 1.24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने बताया कि अभियान का उद्देश्य सड़क हादसों पर अंकुश लगाना और शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाना है। कार्रवाई के दौरान मुंबई एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स रोड समेत गुरुग्राम की प्रमुख सड़कों पर निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार वाहन सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनते हैं। इसी को देखते हुए ओवरस्पीडिंग के खिलाफ लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। अगस्त में हुई कार्रवाई से स्पष्ट है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है।

दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान बदलेगा मौसम, बारिश को लेकर अलर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दिल्ली में बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा के अनुसार, 11-12 सितंबर के आसपास उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम बदल सकता है। राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। बारिश के कारण सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों की आवाजाही और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसे देखते हुए भारत मंडपम और सम्मेलन से जुड़े प्रमुख मार्गों पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन की नजर मौसम के पूर्वानुमान पर बनी हुई है।

अमेठी में कक्षा 1-2 के बच्चों को नहीं मिलेंगे अंक, अब स्टार से होगा मूल्यांकन

एजेंसी, नई दिल्ली। अमेठी में कक्षा एक और दो के बच्चों के मूल्यांकन की व्यवस्था बदली गई है। अब नौनिहालों की काबिलियत अंकों के बजाय स्टार के माध्यम से दर्ज होगी। नई शिक्षा नीति के तहत शुरू की जा रही इस व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों को परीक्षा के दबाव से बचाना है। मूल्यांकन में स्वच्छता, व्यवहार, रचनात्मकता और अन्य गतिविधियों को भी महत्व दिया जाएगा। इससे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर रहेगा और उनकी प्रगति का आकलन व्यापक तरीके से किया जा सकेगा। इससे बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ेगी और बिना तनाव अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर मिलेगा।

पीएम मोदी की डॉक्यूमेंट्री पर बीबीसी के खिलाफ 10 हजार करोड़ का मानहानि केस वापस

बीबीसी के खिलाफ 10 हजार करोड़ का मुकदमा वापस, संस्था अब नया केस करेगी दायर

एजेंसी, नई दिल्ली

गुजरात की गैर सरकारी संस्था 'जस्टिस ऑन ट्रायल' ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन (बीबीसी) के खिलाफ दायर 10 हजार करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा वापस ले लिया है। संस्था की ओर से अदालत को बताया गया कि इसी आधार पर अब नया मुकदमा दायर किया जाएगा।

इसके बाद अदालत ने पुराना मुकदमा वापस लेने की अनुमति दे दी और मामले को खारिज कर दिया। यह मानहानि मुकदमा बीबीसी की दो भागों वाली डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को लेकर दायर किया गया था। याचिकाकर्ता संस्था का आरोप था कि डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण से भारत की प्रतिष्ठा, न्यायपालिका और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचा है।

इसी को आधार बनाकर संस्था ने बीबीसी से 10 हजार करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी। मामले में याचिकाकर्ता संस्था की तरफ से अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा अदालत में पेश हुए।

उन्होंने न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि संस्था इसी आधार पर एक नया मुकदमा दायर करना चाहती है। इसके बाद पीठ ने मुकदमा वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अदालत की अनुमति मिलने के बाद 10 हजार करोड़ रुपये के मानहानि दावे वाला पुराना मुकदमा समाप्त हो गया। हालांकि, संस्था ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले को पूरी तरह छोड़ नहीं रही है।

उसके मुताबिक, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जिन आधारों पर पहले मुकदमा दायर किया गया था, उन्हीं आधारों पर नए सिरे से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' दो भागों में तैयार की गई थी। डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में भी काफी विवाद हुआ था। इसके प्रसारण और इससे जुड़ी सामग्री को लेकर अलग-अलग स्तरों पर आपत्तियां सामने आई थीं। इसी क्रम में 'जस्टिस ऑन ट्रायल' ने अदालत का रुख करते हुए बीबीसी के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया था।

पीडीए की नई सुविधा: घर बैठे ऑनलाइन बुक करें फ्लैट और भूखंड

एजेंसी, नई दिल्ली

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) अब लोगों को घर बैठे फ्लैट और भूखंड बुक करने की सुविधा देने की तैयारी में है। यह सुविधा अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों को पीडीए कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपनी पसंद की संपत्ति का चयन कर ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे।

पीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध आवासीय संपत्तियों से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। इसमें भूखंड और फ्लैट का आकार, कीमत और स्थान जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी। इससे खरीदार अपनी जरूरत और बजट के अनुसार संपत्ति का चयन कर सकेंगे। ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने से बिक्री प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आने की उम्मीद है। पीडीए की ओर से आठ आवासीय योजनाओं में करीब 500 फ्लैट और 200 भूखंडों की बिक्री की जाएगी।

इन संपत्तियों को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। इच्छुक लोग वेबसाइट पर योजनाओं और उपलब्ध संपत्तियों की जानकारी देखकर आवेदन और बुकिंग कर सकेंगे। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि दूसरे शहरों में रहने वाले लोग भी बिना प्रयागराज आए संपत्तियों की जानकारी हासिल कर सकेंगे।

मानिकपुर-इरादतगंज तीसरी लाइन का रास्ता साफ, 37 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण तय

एजेंसी, नई दिल्ली

प्रयागराज समेत पूर्वांचल और बिहार से मुंबई व दक्षिण भारत जाने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। मानिकपुर इरादतगंज तीसरी रेल लाइन के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रयागराज जिले में परियोजना के लिए करीब 37 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की अंतिम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। केंद्र सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण से संबंधित गजट जारी होने के बाद इस महत्वपूर्ण परियोजना के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।

उत्तर मध्य रेलवे के निर्माण विभाग की इस परियोजना को मुंबई रूट के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में माना जा रहा है। मानिकपुर-इरादतगंज रेलखंड पर वर्तमान में दो रेल लाइनें हैं और इस मार्ग पर ट्रेनों का दबाव अधिक रहता है। यातायात बढ़ने के कारण कई बार ट्रेनों को पीछे रोकना पड़ता है। इसका असर लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन और समयपालन पर पड़ता है। तीसरी लाइन बनने के बाद इस समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।

परियोजना के तहत तीसरी रेल लाइन बनने से इस व्यस्त रेलखंड की क्षमता बढ़ेगी। मौजूदा दोनों लाइनों पर यातायात का दबाव कम होगा और ट्रेनों को अधिक सुचारु ढंग से चलाने में मदद मिलेगी। इसका सीधा लाभ प्रयागराज, पूर्वांचल और बिहार से मुंबई तथा दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब परियोजना के निर्माण कार्य को गति मिलने की संभावना है।

केंद्र की ओर से गजट जारी होने से जमीन अधिग्रहण को लेकर लंबित प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। रेलवे की ओर से इसके बाद निर्माण से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। तीसरी रेल लाइन बनने के बाद इस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की संभावना भी मजबूत होगी।

मोबाइल के दौर में भी मजबूत भारतीय पुस्तक बाजार, ई-बुक और ऑडियोबुक का बढ़ा क्रेज

एजेंसी, नई दिल्ली

मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद भारत में किताबों की मांग और पुस्तक बाजार लगातार मजबूत बना हुआ है। पाठकों की पसंद में बदलाव जरूर आया है, लेकिन छपी किताबों के साथ ई-बुक और ऑडियोबुक जैसे डिजिटल विकल्पों ने पढ़ने की आदत को नया विस्तार दिया है। इससे प्रकाशन क्षेत्र को नए पाठक और नए बाजार मिल रहे हैं।

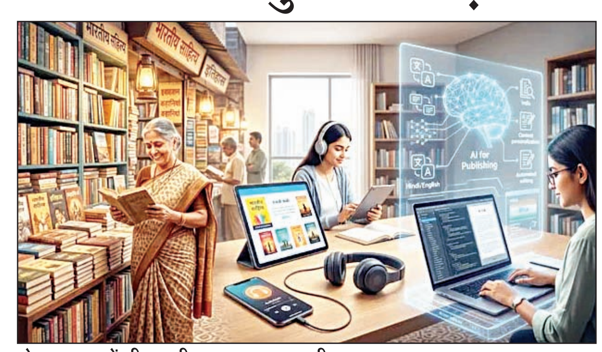
मोबाइल युग में भी भारतीय पुस्तक बाजार की चमक बरकरार।

भारतीय पुस्तक बाजार का आकार करीब 95,816 करोड़ रुपये बताया गया है, जबकि डिजिटल पुस्तक बाजार करीब 7,048 करोड़ रुपये का है। आंकड़े बताते हैं कि पारंपरिक छपी किताबों के साथ डिजिटल माध्यम भी तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। पाठक अब अपनी सुविधा के अनुसार पुस्तक पढ़ने या सुनने का विकल्प चुन रहे हैं। खासकर मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों ने ई-बुक तथा ऑडियोबुक तक पहुंच आसान कर दी है। पुस्तक बाजार में यह बदलाव केवल पाठकों की पसंद तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकाशन उद्योग के कामकाज को भी प्रभावित कर रहा है।

डिजिटल माध्यमों के कारण पुस्तकों को तैयार करने और पाठकों तक पहुंचाने के नए रास्ते खुले हैं। इससे छोटे और नए लेखकों तथा प्रकाशकों के लिए भी अपनी सामग्री अधिक लोगों तक पहुंचाने की संभावनाएं बढ़ी हैं। इस क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल से आने वाले समय में प्रकाशन प्रक्रिया को और गति मिलने की उम्मीद है।

सामग्री तैयार करने, संपादन, अनुवाद और पाठकों की पसंद के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध कराने में तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते इस्तेमाल के साथ कॉपीराइट और मौलिकता की सुरक्षा बड़ी चुनौती भी बनी रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में छपी किताब और डिजिटल माध्यम एक-दूसरे के विकल्प के बजाय साथ-साथ आगे बढ़ेंगे।

पॉक्सो आरोपी ट्रेन से कूदकर फरार पुलिसकर्मियों की लापरवाही पर केस

एजेंसी, नई दिल्ली

गुजरात से मीरजापुर लाया जा रहा पॉक्सो एक्ट का आरोपित आगरा में किरावली रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले में मीरजापुर पुलिस के उपनिरीक्षक ने आगरा जीआरपी थाना फोर्ट में आरोपी के फरार होने और उसके साथ तैनात तीन पुलिसकर्मियों की लापरवाही के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है।

मीरजापुर के थाना पड़री में तैनात उपनिरीक्षक जयप्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि थाने में दर्ज एक मामले की विवेचना के दौरान नाबालिग पीड़िता और आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसी सिलसिले में उपनिरीक्षक विजय शंकर यादव, महिला हेड कांस्टेबल गीता और कांस्टेबल नीरज कुमार दो सितंबर को गुजरात के सूरत स्थित थाना उमरा पहुंचे थे। पुलिस टीम ने आरोपी सूरज कुमार पांडेय उर्फ हर्ष पांडेय को हिरासत में लिया था।

इसके बाद उसे मीरजापुर लाने के लिए पुलिसकर्मी ट्रेन से रवाना हुए। यात्रा के दौरान आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया था। आगरा के किरावली रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के पहुंचने पर आरोपी अचानक चलती ट्रेन से कूद गया और मौके से फरार हो गया। आरोपी के ट्रेन से कूदते ही पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने आसपास के क्षेत्र में उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई। इसके बाद मामले में पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच शुरू हुई।

मीरजापुर पुलिस की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर आगरा जीआरपी थाना फोर्ट में आरोपी के फरार होने और पुलिसकर्मियों की लापरवाही को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि पुलिस अभिरक्षा के दौरान सुरक्षा में किस स्तर पर चूक हुई और आरोपी चलती ट्रेन से कैसे कूदने में सफल रहा।

कुत्ता घुमाने पर हुआ विवाद, रिटायर्ड इंस्पेक्टर और परिजनों पर मुकदमा

एजेंसी, नई दिल्ली

राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज एंपायर सोसायटी में कुत्ता घुमाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। पीड़ित शिवम गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर आनंद कुमार और उनके परिजनों समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है।

पुलिस के अनुसार, रविवार देर रात करीब 12 बजे शिवम गुप्ता की शिकायत पर नंदग्राम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायत में रिटायर्ड इंस्पेक्टर आनंद कुमार समेत चार लोगों पर विवाद और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि सोसायटी परिसर में कुत्ता घुमाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। विवाद बढ़ने के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत और उपलब्ध वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान और उनकी भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी। इसके साथ ही घटना के दौरान मौजूद लोगों से पूछताछ कर विवाद की वास्तविक वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना जारी है। सोसायटी में हुए इस विवाद के बाद स्थानीय लोगों के बीच भी चर्चा का माहौल बना हुआ है।

कानपुर में घर गिरने से पिता और तीन बेटियों की मौत, एक साथ उठीं चार अर्थियां

एजेंसी, नई दिल्ली

साढ़ थाना क्षेत्र के हिरनी गांव में कच्चा मकान गिरने से पिता और उनकी तीन बेटियों की मौत के बाद सोमवार को गांव में मातम पसरा रहा। जिस आंगन में कुछ समय पहले तक तीनों बेटियों की हंसी गूंजती थी, वहीं सोमवार को चीख-पुकार और सिसकियों का माहौल था। पिता मुकेश और उनकी बेटियों माया, नीतू और पल्लवी के शव जब एक साथ घर पहुंचे तो परिजनों का कलेजा फट पड़ा। अपनों के चार शव सामने देखकर परिवार के लोग बदहवास हो गए।

हादसे में जान गंवाने वाले चारों लोगों का रविवार रात पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार सुबह सभी के शव एक साथ हिरनी गांव स्थित घर पहुंचे। शवों को देखते ही परिजन और ग्रामीण भावुक हो उठे। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हर किसी की आंखें नम थीं और परिवार को

हिरनी गांव में पिता और तीन बेटियों के शव पहुंचने पर गमगीन हुए परिजन।

सांत्वना देने के लिए ग्रामीण जुटे रहे।

हादसे के बाद प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई। अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया। प्रशासनिक सहायता मिलने के बाद चारों शवों को अंतिम संस्कार के लिए मूसानगर ले जाया गया। परिजन और ग्रामीण शवों को यमुना नदी के किनारे स्थित हलिया घाट ले गए, जहां पिता और तीनों बेटियों का अंतिम संस्कार किया गया।

एक ही परिवार के चार सदस्यों को एक साथ अंतिम विदाई ने पूरे गांव को झकझोर दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। वहीं, घटना के बाद प्रशासन की ओर से राहत और सहायता की प्रक्रिया पूरी की गई।

20 सितंबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर करणी सेना की याचिका पर हाई कोर्ट ने पुलिस को जल्द निर्णय लेने को कहा

करणी सेना ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

एजेंसी, नई दिल्ली

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए विनियम-2026 को अधिसूचित किए जाने के विरोध में क्षत्रिय करणी सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। संगठन ने 20 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है। इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शन की अनुमति के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

क्षत्रिय करणी सेना की ओर से अदालत में दायर याचिका में कहा गया कि संगठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए विनियमों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना चाहता है। इसके लिए 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन प्रस्तावित किया गया है। संगठन ने पुलिस से प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बाद उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में क्षत्रिय करणी सेना ने कहा कि उसका प्रस्तावित प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा।

यूजीसी के नए नियमों के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगने हाई कोर्ट पहुंची करणी सेना।

संगठन का उद्देश्य यूजीसी के नए विनियम-2026 के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज कराना और इस मुद्दे पर विरोध जताना है।

इसके लिए जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान संगठन की ओर से अदालत के समक्ष प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया। अदालत ने इस मामले में सीधे अनुमति देने के बजाय दिल्ली पुलिस को याचिका पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

अब पुलिस को संगठन की मांग और प्रस्तावित प्रदर्शन से संबंधित पहलुओं पर विचार करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने से संबंधित विनियम-2026 अधिसूचित किए गए हैं। इन्हीं नए नियमों को लेकर क्षत्रिय करणी सेना ने आपत्ति जताई है।

संगठन का कहना है कि वह इन्हीं विनियमों के विरोध में सार्वजनिक प्रदर्शन करना चाहता है। जंतर-मंतर दिल्ली में निर्धारित प्रदर्शन स्थलों में शामिल है, जहां विभिन्न संगठन और समूह समय-समय पर अपनी मांगों और मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। हालांकि, किसी भी प्रदर्शन के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुमति और निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इसी अनुमति को लेकर संगठन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब दिल्ली पुलिस को करणी सेना की ओर से प्रस्तावित प्रदर्शन पर फैसला लेना है। पुलिस प्रदर्शन के स्थान, तारीख, संभावित लोगों की संख्या और अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकती है।

फिलहाल अदालत ने पुलिस को इस मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। क्षत्रिय करणी सेना की ओर से 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। संगठन ने अदालत के समक्ष इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताया है। अब प्रदर्शन की अनुमति को लेकर पुलिस के निर्णय का इंतजार है। इस मामले में अदालत के निर्देश के बाद करणी सेना की मांग पर अगला कदम दिल्ली पुलिस के निर्णय पर निर्भर करेगा। यदि पुलिस की ओर से अनुमति दी जाती है, तो संगठन निर्धारित तारीख पर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर सकेगा। वहीं, अनुमति से संबंधित कोई शर्त लगाए जाने पर संगठन को उसका पालन करना होगा।

पत्नी ने पति का शव बाथरूम में दबाया, तीन महीने बाद कंकाल बरामद

एजेंसी, नई दिल्ली

पत्नी रूबी शर्मा पर पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या कर शव को घर के बाथरूम में दबाने के मामले में पुलिस अब बरामद कंकाल की पहचान के लिए डीएनए जांच कराएगी। करीब तीन महीने बाद बाथरूम से बरामद कंकाल सुरेंद्र शर्मा का ही है या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद होगी। इसके लिए पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मृतक की मां के खून का नमूना लिया है।

पुलिस के अनुसार, पति की हत्या के बाद उसके शव को बाथरूम में करीब तीन फीट नीचे दबाया गया था। शव के ऊपर प्लास्टर करा दिया गया था, जिससे किसी को इसकी भनक न लगे। कई सप्ताह तक शव बाथरूम के नीचे दबा रहा। बाद में मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने बाथरूम की खुदाई कर वहां से कंकाल बरामद किया। कंकाल मिलने के बाद उसकी पहचान को लेकर पुलिस ने वैज्ञानिक जांच का सहारा लेने का निर्णय लिया है। मृतक की मां के रक्त नमूने और बरामद कंकाल के नमूने का मिलान कराया जाएगा। डीएनए रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद अवशेष सुरेंद्र शर्मा के ही हैं या नहीं।

मामले में पुलिस पत्नी रूबी शर्मा की भूमिका और हत्या के पीछे के कारणों की भी जांच कर रही है। डीएनए रिपोर्ट के बाद विवेचना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिलने की उम्मीद है। पुलिस के मुताबिक मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों को भी जुटाया जा रहा है। जांच में सामने आए तथ्यों, गवाहों के बयान और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हत्या कब और किन परिस्थितियों में हुई।

चीनी के दाम में आई गिरावट, थोक भाव फिर पुराने स्तर पर पहुंचा

एजेंसी, नई दिल्ली। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के दौरान चीनी के दाम में आई तेज उछाल अब थम गई है। बाजार में तेजी का बुलबुला फूटने के बाद चीनी का थोक भाव फिर पुराने स्तर पर लौट आया है। अगस्त में चीनी का एक्स-मिल भाव 44 रुपये प्रति किलो से बढ़कर करीब 70 रुपये तक पहुंच गया था। अब बाजार में अतिरिक्त स्टाक आने के बाद भाव घटकर 44 से 45 रुपये प्रति किलो रह गया है। इससे उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने थोक चीनी का दाम 45 से 46 रुपये प्रति किलो तय किया है। वहीं लखनऊ में चीनी का फुटकर भाव अभी 63 से 64 रुपये प्रति किलो है। राज्य सरकार ने भी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकारी बिक्री केंद्रों पर 52 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी उपलब्ध कराई है। बाजार में अतिरिक्त स्टाक पहुंचने से कीमतों में नरमी आई है। कारोबारियों के अनुसार, त्योहारी मांग के कारण अगस्त में कीमतों में अचानक तेजी आई थी, लेकिन अब आपूर्ति बढ़ने से बाजार सामान्य स्थिति में लौट रहा है।

न्यूज ब्रीफ

आयुष ठाकुर विद्यालय में हुए सम्मानित

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। उपमंडल अर्की के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनी-मटेरनी के पूर्व छात्र आयुष ठाकुर को सोमवार को विद्यालय में नीट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करने पर सम्मानित किया गया। आयुष ने नीट में हिमाचल प्रदेश में 62वां रैंक हासिल कर आईजीएमसी शिमला में एमबीबीएस के लिए प्रवेश प्राप्त किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव शर्मा व विद्यालय परिवार ने आयुष को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आयुष ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, दादाजी और विद्यालय के अध्यापकों को दिया। आयुष ने इसी विद्यालय से दसवीं से जमा दो तक की पढ़ाई पूरी की है। उनकी सफलता की खास बात यह है कि उनके पिता भी इसी विद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता हैं। आयुष की उपलब्धि पर विद्यालय परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम

भारतेन्दु संवाददाता, बद्दी। अटल शिक्षा कुंज, कालू झंडा स्थित आईईसी विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति व महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. प्रल्हाद गुप्ता और वरिष्ठ संकाय सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर तथा डॉ. राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। इसके बाद विभिन्न विभागों के छात्र-छात्राओं ने शास्त्रीय नृत्य, संगीत और लघु नाटिकाओं की प्रस्तुतियां दीं। शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने वाली प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। विद्यार्थियों ने शिक्षकों को स्मृति चिह्न भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. प्रल्हाद गुप्ता ने कहा कि शिक्षक का दायित्व केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण कर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। उन्होंने सभी प्राध्यापकों के समर्पण और योगदान की सराहना की। अंत में शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी गईं।

नाहन-कुमारहट्टी एनएच पर निजी बस व कार के बीच टक्कर, दोनों तरफ लगा लंबा जाम

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। नाहन-कुमारहट्टी नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह साढ़े 9 बजे के आसपास निजी बस और कार के बीच टक्कर हो गई। हालांकि, हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन कार को काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि एक बाइक को बचाते वक्त बस और कार की टक्कर हो गई। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए जाम लग गया। इससे वाहन चालकों समेत कामकाजी और नौकरीपेशा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार हादसा चंबाहा स्थित काली मंदिर के समीप पेश आया। सवारियों से भरी बस राजगढ़ से नाहन की ओर आ रही थी, जबकि दूसरी ओर से कार दोसड़का की ओर जा रही थी। जैसे ही दोनों वाहन चबाहां के समीप पहुंचे तो इनमें साइड की टक्कर हो गई। हादसे में कार के एक हिस्से को नुकसान हुआ है। जहां दुर्घटना हुई है, वहां पहाड़ी से मलबा भी सड़क पर गिरा है। बस अपनी साइड छोड़ निचली तरफ कार से टकरा गई। इसके बाद सड़क पर दोनों तरफा लंबा जाम लग गया। इससे नाहन आने वाले मुसाफिरों के साथ साथ सराहां, कुमारहट्टी, शिमला और श्री रेणुकाजी की तरफ जाने वाले यात्रियों को कुछ समय के लिए दिक्कतें झेलनी पड़ीं। बहरहाल, हादसे में किसी को चोट नहीं है। दुर्घटना के बाद वाहन चालकों और यात्रियों ने अपने स्तर पर कार और बस को घटनास्थल से हटाने और जाम खोलने के प्रयास किए।

आरसेटी ने 29 लोगों को सिखाई मशरूम की खेती

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) हमीरपुर द्वारा भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत करहा के लोगों के लिए मशरूम की खेती पर आयोजित दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सोमवार को संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण शिविर में 29 लोगों ने भाग लेकर मशरूम की खेती के गुर सीखे। संस्थान के परिसर में आयोजित शिविर के समापन समारोह में पंजाब नेशनल बैंक के लोन प्वाइंट के मुख्य प्रबंधक राजेश कुमार मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए राजेश कुमार ने कहा कि आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे घर में सीमित जगह पर भी बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त करने में आरसेटी भी उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने प्रतिभागियों से विभिन्न विभागों और बैंकों की ऋण एवं सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीपीएफ अकाउंट, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह भी किया।

सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों का ड्रेस कोड छात्रों की यूनिफॉर्म जल्द होगी तय : सीएम

ग्रामीण विद्यार्थियों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड, विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म तथा स्कूल भवनों के लिए एक अलग और विशिष्ट रंग योजना अतिशीघ्र निर्धारित की जाए।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड इस वर्ष 1 अक्तूबर से लागू किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित सीबीएसई स्कूलों के 'लोगो' को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों के साथ आवश्यक प्रक्रियाओं पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों में अनुशासन और समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए दिन में तीन बार उपस्थिति दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सीबीएसई स्कूलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सीबीएसई स्कूलों में विद्यार्थियों को सुलभ दरों पर शिक्षा प्रदान की जाएगी, जबकि निजी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षा अपेक्षाकृत महंगी है। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इन स्कूलों में पहले ही शिक्षकों की नियुक्ति कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी कारण से शिक्षकों के पद रिक्त होने पर उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा, ताकि स्टाफ की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में महाधिवक्ता अनूप रतन, सचिव शिक्षा राकेश कंवर, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

◆ सीबीएसई स्कूलों में दिन में तीन बार होगी उपस्थिति दर्ज

कंगना ने बैठक में आपा खोया, अधिकारियों से भाषा नहीं थी उचित : नरेश

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के अधिकारियों के साथ व्यवहार को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी) समिति की बैठक में कंगना रनौत ने आपा खोया और अधिकारियों के साथ जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वह उचित नहीं थी। उन्होंने कहा कि सांसद को अपनी मर्यादा में रहकर अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए थी। नरेश चौहान ने सोमवार को कहा कि सांसद को अधिकारियों से काम लेने और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने का अधिकार है, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि बैठक में ऐसी स्थिति क्यों बनी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ योजना के अनुसार और विषयवार चर्चा होनी चाहिए थी। उनके अनुसार कंगना रनौत के व्यवहार में उनकी निराशा दिखाई दे रही थी और यह पूरा घटनाक्रम प्रचार पाने के प्रयास जैसा लगा।

अनुराग ठाकुर ने ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने पर दिया जोर

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में संसदीय स्थायी समिति, कोयला, खान एवं इस्पात ने मुन्नार में अपने अध्ययन दौरे की शुरुआत की।

समिति ने देश के कोयला क्षेत्र की कार्यप्रणाली, उत्पादन क्षमता, परिचालन दक्षता और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान समिति ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी प्रमुख सहायक कंपनियों ईसीएल, एनसीएल और डब्ल्यूसीएल के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। बैठक में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कोल इंडिया की भूमिका, उत्पादन क्षमता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर विचार-विमर्श हुआ। अध्ययन दौरे के दौरान कोयला गैसीकरण योजना पर भी विशेष चर्चा हुई। बैठक में एमसीएल, एसईसीएल और सीसीएल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समिति ने कोयला गैसीकरण की रणनीति, प्रभावी क्रियान्वयन और स्वच्छ एवं आधुनिक कोयला प्रौद्योगिकियों के उपयोग की संभावनाओं की समीक्षा की। अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में समिति ने आधुनिक तकनीक और नवाचार के माध्यम से कोयला संसाधनों के जिम्मेदार, प्रभावी और टिकाऊ उपयोग पर जोर दिया। समिति ने कहा कि बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए कोयला क्षेत्र का आधुनिकीकरण और स्वच्छ तकनीकों को बढ़ावा देना जरूरी है। समिति का यह अध्ययन दौरा ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े नीतिगत विषयों की समीक्षा और संसदीय निगरानी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हणोगी में फोरलेन टनलों से यातायात शुरू होना क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात : जयराम ठाकुर

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। कीरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर डयोड-हणोगी तथा हणोगी से दवाड़ा तक वाहनों की आवाजाही नव निर्मित टनलों से शुरू होने पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रसन्नता व्यक्त की है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि इन टनलों में यातायात शुरू होने से क्षेत्रवासियों के साथ-साथ मंडी और कुल्लू-मनाली आने वाले पर्यटकों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। इस मार्ग पर सफर पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक होगा तथा यात्रा के समय में भी कमी आएगी। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे से पूर्व ये यातायात इन अत्याधुनिक टनलों से बहाल पर्यटन कारोबार को और गति देगा। साथ ही घंटों जाम की समस्या से भी निजात मिल गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमाचल प्रदेश में ऐसी परियोजनाएं विकास की गति को तेज करने में सहायक हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कारोबार को लाभ पहुंचेगा और लोगों की आवाजाही आसान होगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मंडी-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन टनलों का संचालन क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिकी, पर्यटन और जनजीवन को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल में सड़क और सुरंगों का मजबूत नेटवर्क प्रदेश के विकास को नई गति दे रहा है। यह कनेक्टिविटी हिमाचल की आर्थिकी, पर्यटन और जनजीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

पच्छाद में थार और बाइक में टक्कर, बाइक चालक घायल

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। पुलिस थाना पच्छाद के अंतर्गत क्वागधार हेलीपैड के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सोमवार को पुलिस थाना पच्छाद में सूचना मिली कि क्वागधार हेलीपैड के पास कार और बाइक की टक्कर हुई है। सूचना पर पुलिस टीम सराहां अस्पताल पहुंची। वहां डॉ. निखिल भारद्वाज निवासी गांव धनोह, डाक बागटा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर ने शिकायत दर्ज करवाई कि वह आज अपनी थार नंबर में चंडीगढ़ से सराहां जा रहे थे। सुबह करीब 10 बजे क्वागधार हेलीपैड से थोड़ा पीछे मोड़ पर सराहां की ओर से बाइक नंबर बहुत तेज रफ्तार और गलत दिशा में आकर उनकी गाड़ी से सीधी टकरा गई। पुलिस थाना पच्छाद में मोटरसाइकिल चालक पंकज कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर अन्वेषण जारी है।

विधायक मलेंद्र राजन ने अंडर-19 छात्राओं की खेल प्रतियोगिता का किया शुभारंभ

28 स्कूलों की 280 छात्राएं दिखा रहीं खेल प्रतिभा

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डाह-कुल्हाड़ा में शिक्षा खंड इंदौरा की अंडर-19 छात्राओं की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक मलेंद्र राजन ने किया।

प्रतियोगिता में 28 विद्यालयों की करीब 280 छात्राएं भाग ले रही हैं। शुभारंभ अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। विधायक मलेंद्र राजन ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने छात्राओं से पूरी मेहनत, लगन व खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर सफलता हासिल करनी चाहिए। खेलों से अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना जैसे गुण विकसित होते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ने में सहायक हैं।

विधायक ने बताया कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तीन विद्यालयों राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंदौरा, गंगथ और ठाकुरद्वारा को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है। डाह-कुल्हाड़ा स्कूल में शौचालय निर्माण के लिए चार लाख रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं, जबकि नए भवन निर्माण के लिए चालू वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने विद्यालय में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए भी प्रयास करने की बात कही। मलेंद्र राजन ने क्षेत्र की शास्त्रीय गायिका सुनंधा शर्मा की प्रतिभा की सराहना करते हुए स्थानीय प्रतिभाओं को उचित मंच देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने प्रतियोगिता के आयोजन के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 21 हजार रुपए और विद्यालय के अंडर-14 खेलों में विजेता खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए 11 हजार रुपए देने की घोषणा की पुलिस अधीक्षक नूरपुर इल्मा अफरोज ने छात्राओं को खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

कागजों से बाहर निकलो, धरातल पर आओ जिप की बैठक में खूब गरजे जनप्रतिनिधि

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। नवगठित जिला परिषद की पहली त्रैमासिक बैठक सोमवार को अनीता शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

इस बैठक में परिषद के विभिन्न सदस्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों एवं प्रश्नों पर संबंधित अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की गई। इसके अलावा बीबी-जी राम जी योजना के शैल्फों और परिषद की आय-व्यय को लेकर पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में जिला परिषद सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और होने वाले विकास कार्यों के बारे में चर्चा की। बैठक के दौरान एचआरटीसी द्वारा बसें न चलाने को लेकर जन प्रतिनिधि भड़क गए। जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि अधिकारी समय पर सांसद, विधायक निधि का सही उपयोग करें जिससे गांव और उस क्षेत्र का विकास हो। बैठक में नए सदस्यों ने मुख्यतः मूलभूत सुविधाओं जैसे-सड़क, पेयजल और परिवहन इत्यादि से संबंधित समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट ली। इस अवसर पर अध्यक्ष अनीता शर्मा ने कहा कि जिला परिषद के सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं। इसलिए, संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर इनका समाधान सुनिश्चित करें। एडीसी व परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक गर्ग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परिषद के सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करें।

बैठक का संचालन जिला परिषद की सचिव एवं जिला पंचायत अधिकारी बबीता गुलेरिया ने किया। इस अवसर पर परिषद के सदस्य और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला परिषद हमीरपुर की अध्यक्ष अनीता शर्मा ने कहा कि बैठक में कुछ विभागों के उच्च अधिकारी नहीं आए थे उन्हें अगली बैठक संबंधी प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि लोगों की समस्याओं और विकास कार्यो को लेकर जनता के बीच जाते हैं। इस अवसर पर जिला परिषद के सदस्यों ने डीसी ऑफिस में निशुल्क पार्किंग की सुविधा दिलाने की भी बैठक में मांग रखी। जिला परिषद की बैठक में सभी वार्डों के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे।

कल्लर में अंडर-19 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कल्लर में स्वारघाट खंड की तीन दिवसीय अंडर-19 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ एसडीएम सदर राज कुमार ने किया। इसमें स्वारघाट खंड के 11 स्कूलों की 175 छात्रा खिलाड़ी कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन और वॉलीबॉल की विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रही हैं। एसडीएम राज कुमार ने कहा कि खेलकूद विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास होता है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवीण सिंह चंदेल ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और प्रतियोगिता की जानकारी दी।

विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका निर्णायक : जीतराम कटवाल

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। झंडूता चुनाव क्षेत्र के विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है।

65 प्रतिशत से अधिक युवा आबादी के दम पर भारत विश्व को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। कटवाल सोमवार को झंडूता व शाहतलाई मंडलों के भाजयुमो पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति भाजपा की सबसे बड़ी रीढ़ है। युवा मोर्चा केवल कार्यक्रमों तक सीमित न रहकर पार्टी की विचारधारा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे हर बूथ पर सक्रिय होकर युवाओं को संगठन से जोड़ें और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मुद्रा योजना जैसी पहलों से युवाओं को नौकरी मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 5 लाख पक्की नौकरियों की गारंटी पूरी तरह गायब हो चुकी है। मानसून सत्र में इस पर सरकार केवल टालमटोल करती नजर आई। भाजपा युवाओं के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से युवाओं को नशे से दूर रख खेलों, कौशल विकास और स्वरोजगार से जोड़ने का संकल्प लेने को कहा। बैठक में जिलाध्यक्ष कृष्णलाल चंदेल, सचिव दिनेश चंदेल, मंडल अध्यक्ष रामप्रकाश शर्मा व महामंत्री सुशील नड्डा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

समीक्षा 24 संवेदनशील पंचायतों में नशा निवारण समितियां सक्रिय करने के निर्देश

नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाने पर जोर

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। डीसी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नारकोटिक्स समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान, एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई, वित्तीय जांच, अवैध भांग व अफीम की खेती की रोकथाम तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की विस्तार से समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करते हुए अभियान को जन आंदोलन का रूप देना होगा। उन्होंने नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए मंडी पुलिस की सराहना की। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उपायुक्त ने 'अपना विद्यालय' योजना के तहत गोद लिए गए स्कूलों में विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति नियमित जागरूक करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग को प्रत्येक माह स्कूलों में आयोजित एंटी चिट्टा गतिविधियों की रिपोर्ट एनकॉर्ड बैठक में प्रस्तुत करने को कहा।

खेल प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थियों को एंटी चिट्टा की शपथ दिलाने और एक वक्ता के माध्यम से जागरूकता व्याख्यान करवाने के भी निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि इस वर्ष एक जनवरी से 31 अगस्त तक मंडी जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 230 मामले दर्ज कर 368 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 349 पुरुष और 19 महिलाएं शामिल हैं। दर्ज मामलों में 80 हेरोइन या चिट्टा, 119 चरस, 10 एमडीएमए, सेवन और अन्य एनडीपीएस मामलों तथा 15 अवैध अफीम व भांग की खेती से संबंधित मामले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 30 और अगस्त में 23 मामले दर्ज किए गए। जुलाई में 197.68 ग्राम चिट्टा या हेरोइन बरामद हुई, जबकि अगस्त में 57.05 ग्राम चिट्टा या हेरोइन, 4.626 किलोग्राम चरस और 60.728 किलोग्राम अफीम डोडा बरामद किया गया। इस वर्ष अवैध भांग की खेती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5,11,160 पौधे नष्ट किए गए हैं। बैठक में जिले की 24 अति संवेदनशील ग्राम पंचायतों में नशा निवारण समितियों की गतिविधियों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने और पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, नगर निकायों तथा पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से व्यापक जागरूकता अभियान चलाने को कहा। उन्होंने ड्रग्स फ्री हिमाचल ऐप का अधिक प्रचार करने के निर्देश भी दिए।

भांग व अफीम की अवैध खेती पर होगी कार्रवाई

डीसी ने भांग उखाड़ो अभियान की समीक्षा करते हुए अवैध भांग व अफीम की खेती की समयबद्ध पहचान कर उसे नष्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा पंचायत प्रतिनिधियों से नशे से जुड़ी गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने का आग्रह किया। 15 सितंबर से आईटीबीपी के सहयोग से प्रस्तावित भांग उन्मूलन अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

पठानकोट में 1.68 किलो चरस के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत पठानकोट और सुजानपुर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुल 1 किलो 682 ग्राम चरस, 12 हजार रुपये की ड्रग मनी और तस्करी में प्रयुक्त ऑल्टो कार बरामद की। पहले मामले में पठानकोट पुलिस ने मिलिट्री अस्पताल की सर्विस रोड पर कार में ग्राहक का इंतजार कर रहे चंबा निवासी गुलजार मोहम्मद और लाल दीन को पकड़ा। तलाशी के दौरान कार से 1 किलो 82 ग्राम चरस बरामद हुई। दूसरे मामले में सुजानपुर पुलिस ने रेलवे रोड स्थित पीर बाबा दरगाह के पास संदिग्ध युवक सचिन गुप्ता उर्फ बाबा निवासी झलाकड़ी मोहल्ला, सुजानपुर को पकड़ा। उसके फेंके लिफाफे से 600 ग्राम चरस और 12 हजार रुपये बरामद हुए। पुलिस ने दोनों मामलों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जबरदस्ती की जा रही स्मार्ट मीटरिंग पूर्ण रूप से बिजली उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और प्रदेश के हितों के खिलाफ

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। कंडरोला प्लासी पंचायत में उपभोक्ता कल्याण मंच की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंच के संयोजक कुलदीप सिंह खरवाड़ा सहित बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ताओं ने भाग लिया। बैठक में स्मार्ट मीटरिंग, बिजली संशोधन विधेयक और बिजली बोर्ड के कार्यों के निजीकरण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

संयोजक कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत की जा रही स्मार्ट मीटरिंग बिजली उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और प्रदेश के हितों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं पर दबाव बनाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब करीब 600 रुपए के डिजिटल मीटर से बिजली खपत मापी जा सकती है तो 9 से 10 हजार रुपए की लागत वाले स्मार्ट मीटर को अनिवार्य रूप से लगाने का क्या औचित्य है। खरवाड़ा ने कहा कि प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2025 के प्रावधानों से बिजली वितरण क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश का रास्ता खुल सकता है। उनके अनुसार निजी कंपनियों के लिए स्मार्ट मीटरिंग आवश्यक होगी और इन मीटरों की लागत बिजली उपभोक्ताओं से टैरिफ के माध्यम से कई वर्षों में वसूल की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्यों को निजी कंपनियों के नियंत्रण में देने की प्रक्रिया चल रही है। इससे कर्मचारियों की पदोन्नति, नौकरी और कार्यालयों के अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों से निजीकरण का विरोध करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के घरों के बिजली कनेक्शन गैरकानूनी तरीके से काटकर उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से नियमों के अनुरूप कार्य करने की मांग की। खरवाड़ा ने चेतावनी दी कि यदि उपभोक्ताओं का उत्पीड़न जारी रहा तो उपभोक्ता कल्याण मंच संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों का घेराव करेगा। बैठक में सुभाष चंद, जसवंत सिंह, रत्न चंद, सचिन कुमार, धर्म सिंह, वेद प्रकाश, लेखराज, किशोर चंद, जोगिंदर सिंह, तृप्ता देवी, पवना कुमारी, पुमना देवी, सुमन कुमारी, तिलक राज, राजकुमार चौधरी, प्रेम चंद, औंकार शर्मा और संदीप शर्मा सहित कई उपभोक्ता मौजूद रहे।

न्यूज ब्रीफ

हिरिल महासचिव, स्नेहा को सचिव की जिम्मेदारी

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए वल्लभियन बॉटनी क्लब के पुनर्गठन को लेकर इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्लब के नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया और आगामी वर्ष की गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शैक्षणिक, पाठ्येतर एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में हिरिल ठाकुर को महासचिव और स्नेहा को सचिव चुना गया। तन्वी ठाकुर को सह सचिव कार्यक्रम सचिव की जिम्मेदारी दी गई। स्वाति, मीनाक्षी, सानिया और देवृति को कार्यक्रम सह-सचिव बनाया गया। पल्लवी को वॉल मैगजीन सचिव तथा आर्यन, कनन और लक्ष्य को सह-सचिव चुना गया। क्लब के तहत जैव-विविधता पहचान, हर्बेरियम निर्माण, क्षेत्रीय भ्रमण और विभागीय वॉल मैगजीन के प्रबंधन जैसी गतिविधियां करवाई जाएंगी। कार्यक्रम में विभाग की शिक्षिकाएं और गैर-शिक्षण कर्मचारी मौजूद रहे।

घुमारवीं-झंडूता में खैर कटान पर रोक से किसान परेशान

भारतेन्दु संवाददाता, घुमारवीं। वन परिक्षेत्र घुमारवीं व झंडूता में खैर उत्पादक किसान वन विभाग की ओर से कटान की अनुमति नहीं मिलने से आर्थिक संकट झेल रहे हैं। किसानों के अनुसार सरकार की 10 वर्षीय कटान नीति के तहत वर्ष 2012-13 के बाद यह क्षेत्र 2022-23 में खुलना था, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली है। इसके चलते बीमारी और प्राकृतिक कारणों से सैकड़ों खैर के पेड़ सूख चुके हैं और किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। सारटी गांव के किसान एवं समाजसेवी लक्ष्मण सिंह ठाकुर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के 30 अक्तूबर 2009 के आदेश और हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, 1978 में निजी भूमि से खैर कटान का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सूखे और रोगग्रस्त पेड़ों को 10 वर्ष की अवधि की शर्त से छूट देकर तत्काल काटने की अनुमति दी जा सकती है। किसानों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और प्रधान सचिव वन से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है।

उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन आमंत्रित

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। विकास खंड घुमारवीं की ग्राम पंचायत दधोल के गांव दधोल कलां के वार्ड नंबर-दो में उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शीतल शर्मा ने बताया कि इच्छुक आवेदक 30 सितंबर 2026 तक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास और आयु 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, लागू होने पर बीपीएल, ओबीसी, एससी, एसटी प्रमाण पत्र, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज देने होंगे। दुकान संचालन के लिए कमरे या गोदाम की व्यवस्था का प्रमाण, साइट मैप तथा संबंधित घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। दुकान का आवंटन प्राप्त आवेदनों की मेरिट और सरकार के निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

संस्कृत प्रवक्ता डॉ. पद्मनाभ शर्मा सम्मानित

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। अमृता सेवा समिति के सौजन्य से सरस्वती विद्या मंदिर सरकाघाट में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पाठशाला की चेयरमैन एवं समिति अध्यक्ष तथा राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित सोमा राणा ने की। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं हिमाचल शिक्षा समिति के अध्यक्ष तथा राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित सरस्वती नंदन पराशर ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त प्रेम कुमारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। समारोह में क्षेत्र के 13 शिक्षकों को पठन-पाठन के साथ अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षकों में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिस्सा के संस्कृत प्रवक्ता डॉ. पद्मनाभ शर्मा के अलावा नीलम कुमारी, डॉ. विजय कुमार, सुभाष रावत, डॉ. लता पठानिया, सपना कुमारी, राकेश ठाकुर, आनंद पठानिया, डॉ. बलवंत सिंह, सुरेश पठानिया, अजय कुमार, ज्योति प्रकाश और पवन कुमार शामिल रहे। समारोह में विद्यालय के शिक्षक और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

एनकॉर्ड समिति की बैठक में नशे के खिलाफ सख्ती के निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में मादक पदार्थों की तस्करी, नशे के दुरुपयोग की रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और जनजागरूकता अभियानों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए। बैठक में एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में संलिप्त पाए गए 10 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ की गई विभागीय और कानूनी कार्रवाई की भी समीक्षा हुई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा। वन एवं सरकारी भूमि पर नशा तस्करी से जुड़े लोगों के अवैध कब्जों के खिलाफ भी एक माह में कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने नशामुक्ति और शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। स्कूल एडेप्शन कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के लिए नियमित संवाद और करियर परामर्श आयोजित करने को कहा गया। जिले में 27 पंचायत स्तरीय नशा निवारण समितियों का गठन किया गया है। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान सहित अधिकारी मौजूद रहे।

पेट्रोल, चीनी और अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ाने पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ कमरतोड़ महंगाई को लेकर धरना-प्रदर्शन किया।

कांग्रेस नेताओं ने रेस्ट हाउस से गांधी चैक तक बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती ने कहा कि केंद्र में बैठी हुई सरकार गरीब विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है और आम जनता विरोधी सरकार है। उसी के खिलाफ आज यह धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। हिमाचल की खराब वित्तीय स्थिति व केंद्र से सहायता न मिलने का मामला एक बार फिर गरमा गया है। पहले 70 वर्षीय बुजुर्ग राज कुमार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को सुझाव पत्र भेजकर क्रांति लाने की अपील की थी, अब कांग्रेस नेताओं ने भी केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में सुमन भारती ने कहा कि हिमाचल के लिए पहले भी मांग की जा चुकी है। प्रदेश की रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर दी गई है और आपदा के समय जो नुकसान हुआ था, उसका पैसा भी केंद्र नहीं दे रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 1500 करोड़ की घोषणा प्रधानमंत्री धर्मशाला में कर चुके थे, घोषणा के मुताबिक एक पैसा भी हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया गया। दो-तीन बार आपदा आई, उसका भी एक पैसा प्रदेश को नहीं मिला। इसके बावजूद जो आरडीजी बंद कर दी, उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने मांग रखी कि हमारा जो हिस्सा बनता है वो दे दीजिए ताकि हिमाचल को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल के पास अब आय के साधन नहीं बचे हैं और केंद्र फिर भी महंगाई थोप रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप अमीरों का कर्ज माफ कर सकते हैं, आप अडानी-अंबानी का पैसा माफ कर सकते हैं, तो गरीबों के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये गरीबों के साथ दोगला व्यवहार है। गरीबों को महंगाई से और चीनी के दाम बढ़ाकर मारा जा रहा है।

महंगाई से गरीबों की चाय भी हुई फीकी : सुमन

महंगाई का जिक्र करते हुए सुमन भारती ने कहा कि आज चीनी का भाव क्या हो गया है। जो गरीब लोग चाय पीते थे, आज एक मजदूर जो चाय पीता है, उसकी चाय भी फीकी हो गई है। प्याज के रेट कहां पहुंच गए हैं। इसके साथ-साथ पेट्रोल और गैस की कीमतें आज आसमान छू रही हैं। पेट्रोल में एथनॉल मिलावट के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी कंपनियों को फायदा देने के लिए, अपने लोगों को फायदा देने के लिए केंद्र सरकार ने कंपनियों के ऊपर एथनॉल की मात्रा बढ़ाने का प्रेशर बनाया हुआ है। इसके खिलाफ यह धरना प्रदर्शन है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम यह लड़ाई आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह गरीबों की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी पहले भी गरीबों की लड़ाई लड़ती आ रही है, आज भी लड़ रही है।

खेलो इंडिया से गांवों की प्रतिभाओं को मिल रहा अवसर : नरेंद्र अत्री

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष व भाजपा नेता नरेंद्र अत्री ने कहा कि खेलो इंडिया संवाद के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति और खेल शक्ति के प्रति अपना सकारात्मक व दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेलों के माध्यम से स्वस्थ, अनुशासित और सशक्त युवा भारत का निर्माण करना है।

एनसीओई, हमीरपुर खेल उत्सव के तहत आयोजित वॉलीबाल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्यातिथि खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए नरेंद्र अत्री ने कहा कि आज खेलों में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार की खेलो इंडिया जैसी योजनाओं से गांवों और छोटे शहरों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना, अनुशासन और निरंतर मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। अत्री ने कहा कि खेल युवाओं को नशे और अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रखकर सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। इस अवसर पर एनसीओई केंद्र प्रभारी एवं ओलंपियन दिव्या शर्मा, फुटबॉल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एसडी शर्मा, फुटबॉल संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष नरेश राणा कोच नेहा सूद, मंजू, पिंकी चौहान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उद्घाटन मैच डिग्री कॉलेज हमीरपुर और एनसीओई केंद्र की टीमों के बीच खेला गया।

एप्लॉम्ब टैलेंट में लक्ष्य कॉन्वेंट स्कूल का रहा शानदार प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। लक्ष्य कॉन्वेंट स्कूल, मंज्याट के विद्यार्थियों ने गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, कुनिहार में आयोजित चौथे सविता गर्ग मेमोरियल इवेंट 'एप्लॉम्ब टैलेंट 2026' में शानदार प्रदर्शन करते हुए चार महत्वपूर्ण स्थान हासिल किए। अंतरविद्यालयी प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतिभा, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, समस्या-समाधान क्षमता और संचार कौशल प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करना था।

मिस्ट्री मिशन-क्ले मोल्डिंग प्रतियोगिता में कक्षा छठी के कर्मण्य और गर्विश ने रचनात्मकता व कल्पनाशीलता का प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्टोरी टेलिंग चैलेंज में कक्षा पांचवीं की तन्वी और शुभा ने प्रभावशाली कहानी प्रस्तुति के साथ द्वितीय स्थान हासिल किया। वरिष्ठ वर्ग की पावर टू चेंज-पीपीटी प्रस्तुति में कक्षा दसवीं के खुशी और भास्कर ने हिमाचल प्रदेश को नशामुक्त बनाने संबंधी व्यावहारिक विचार प्रस्तुत कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इको ग्लैम प्रतियोगिता में कक्षा नौवीं की गार्गी और मनस्वी तथा कक्षा आठवीं की कल्पिता ने रचनात्मकता और टीमवर्क का प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान हासिल किया। विद्यालय प्रबंधन व प्रधानाचार्या ने विजेता व प्रतिभागी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने शिक्षकों के मार्गदर्शन और सहयोग की भी सराहना की। विद्यालय परिवार ने विद्यार्थियों को भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।

नादौन में सेल्स-मार्केटिंग व सर्विस इंजीनियर के साक्षात्कार 15 को

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। अणु, हमीरपुर की प्रसिद्ध कंपनी मैसर्स विमांशु एलिवेटर एंड एस्क्लेटर में सेल्स-मार्केटिंग और सर्विस इंजीनियर के 5-5 पदों को भरने के लिए 15 सितंबर को सुबह 10 बजे उपरोजगार कार्यालय नादौन में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि सेल्स-मार्केटिंग के 5 पदों के लिए 25 से 35 वर्ष तक के बारहवीं पास या इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले पुरुष अभ्यर्थी (फ्रेशर्स) पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 18 हजार से 20 हजार रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा। सर्विस इंजीनियर के पदों के लिए भी दसवीं-बारहवीं पास और किसी भी ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमाधारक पुरुष उम्मीदवार (फ्रेशर्स) पात्र होंगे। उनकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 15 हजार से 20 हजार रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा।

57 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब के दो तस्कर काबू

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पट्टा फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान दो अलग-अलग मामलों में पंजाब के दो युवकों को 57.01 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ सदर थाना में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

पहले मामले में चार सितंबर को स्पेशल डिटेक्शन टीम ने पट्टा फोरलेन पर नाकाबंदी कर बस की जांच की। तलाशी के दौरान संदिग्ध यात्री के कब्जे से 37.17 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी की पहचान 42 वर्षीय अमित गुप्ता पुत्र सुशील कुमार निवासी दशमेश कॉलोनी, जीरकपुर, जिला मोहाली, पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मामले में पांच सितंबर को इसी स्थान पर एक अन्य बस की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने अमृतसर के गुमटाला निवासी 25 वर्षीय पंकज पुत्र सुखा के कब्जे से 19.84 ग्राम चिट्टा बरामद किया। दोनों मामलों में सदर थाना पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी चिट्टे की खेप बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में बेचने के उद्देश्य से लेकर आए थे। अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर नशे की खेप के स्रोत और स्थानीय स्तर पर इसके संभावित खरीदारों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस आरोपियों के संपर्कों और नेटवर्क की भी जांच कर रही है, ताकि तस्करी से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके। अधिकारियों ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

विधायक कमलेश ने सेरा में बांटी 49 लाख की राहत राशि

कहा- गरीब व बेसहारा लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने आरंभ की हैं सराहनीय योजनाएं

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के गरीबों, बेसहारा बच्चों एवं महिलाओं और समाज के अन्य जरूरतमंद लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए बहुत ही सराहनीय योजनाएं आरंभ की है, जिसका सीधा लाभ इन लोगों तक पहुंच रहा है।

सोमवार को सेरा के विश्राम गृह में आयोजित मुख्यमंत्री राहत कोष राशि वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कमलेश ने कहा कि बेसहारा बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, बेसहारा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, आवास योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री ने समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया है। कमलेश ने बताया कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की अन्य पात्र महिलाओं को भी शीघ्र ही 1500-1500 रुपए की राशि मिलनी आरंभ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करके प्रदेश के लाखों अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बहुत बड़ी सौगात दी है, जो सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी एनपीएस में नाममात्र पेंशन ले रहे थे, अब उन्हें ओपीएस के तहत कई गुणा अधिक पेंशन मिल रही है। नादौन विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करते हुए कमलेश ठाकुर ने बताया कि इस क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ने अरबों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है और इन परियोजनाओं के कार्य युद्ध स्तर पर पूरे किए जा रहे हैं। इनमें जोल सप्पड़ में 1000 करोड़ रुपए का मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, डेंटल कालेज, अलाइड हेल्थ सर्विसेज कालेज और कैंसर केयर संस्थान, नादौन में लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम, 45 करोड़ रुपए का एचपीटीडीसी का होटल, जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह, राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल, विभिन्न स्कूलों एवं कालेजों तथा स्वास्थ्य केंद्रों के भवन, पेयजल योजनाएं, सभी मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण, ई-बस डिपो एवं बस स्टैंड का निर्माण, टूरिज्म का प्रोजेक्ट और कई अन्य बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

इस अवसर पर कमलेश ठाकुर ने 194 जरुरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत कुल 49 लाख रुपए की राहत राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए तथा लोगों की समस्याएं भी सुनीं। इससे पहले, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वी चंद ने विधायक का स्वागत किया तथा क्षेत्र में जारी विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी। तहसीलदार निधि सकलानी ने प्रशासन की ओर से कमलेश ठाकुर का स्वागत किया।

स्वच्छ वायु स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक : डॉ . शांडिल

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस फॉर ब्लू स्काइज के अवसर पर सिविल अस्पताल अर्की में महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस वर्ष दिवस का विषय 'स्वच्छ वायु के लिए कार्रवाई का समय' रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना और स्वच्छ वातावरण के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का आयोजन खंड चिकित्सा अधिकारी अर्की डॉ. मुक्ता रस्तोगी के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर एचआईवी काउंसलिंग एवं टेस्टिंग सेंटर के काउंसलर डॉ. विजय कुमार शांडिल ने महिलाओं को वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदूषित हवा में मौजूद धूल, धुआं, सूक्ष्म कण और हानिकारक गैसें सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर खांसी, एलर्जी, आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। लंबे समय तक संपर्क से फेफड़ों और हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और सांस व हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। लोगों से कचरा न जलाने, धूम्रपान से बचने, वाहनों का कम इस्तेमाल करने, पौधे लगाने और घरों में उचित वेंटिलेशन रखने का आग्रह किया गया। सिविल अस्पताल अर्की के प्रभारी डॉ. बाल कृष्ण कौण्डल ने भी लोगों को वातावरण स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। प्रतिभागियों ने स्वच्छ वायु और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

9 सितंबर को अर्की में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

भारतेन्दु संवाददाता,, अर्की। राज्य स्तरीय सायर मेले की तैयारियों के मद्देनजर 33 केवी सब स्टेशन अर्की का आवश्यक रखरखाव कार्य किया जाएगा। इसके चलते बिजली उपमंडल अर्की के अधीन 11 केवी अर्की लोकल फीडर की बिजली आपूर्ति 9 सितंबर 2026 को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक बाधित रहेगी। बिजली उपमंडल अर्की के सहायक अभियंता ई. नीरज कुमार कत्तना ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सायर मेले की तैयारियों को लेकर बिजली व्यवस्था को सुचारू व सुरक्षित बनाए रखने के लिए सब स्टेशन का रखरखाव जरूरी है। निर्धारित अवधि में अर्की क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। सहायक अभियंता ने क्षेत्रवासियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान विभाग का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि रखरखाव कार्य पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।

प्रधानाचार्य राकेश राणा को मिला नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड

भारतेन्दु संवाददाता, चलवाड़ा। तृप्ता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलवाड़ा के प्रधानाचार्य राकेश राणा को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्यों के लिए नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान ऑल इंडिया प्रिंसिपल्स एसोसिएशन की ओर से शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में देश भगत विश्वविद्यालय, मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब में आयोजित समारोह के दौरान प्रदान किया गया।

समारोह में देशभर से करीब 400 प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, उत्कृष्ट कार्य और उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य राकेश राणा को यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके कर्तव्यनिष्ठा, लगन, मेहनत और शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए मिला है। उनके नेतृत्व में विद्यालय ने शिक्षा, अनुशासन, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अवार्ड मिलने की सूचना से विद्यालय परिसर में खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय के चेयरमैन वरिंद्र नरियाल, मैनेजमेंट कमेटी और समस्त स्टाफ ने राकेश राणा को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। चेयरमैन वरिंद्र नरियाल ने कहा कि यह सम्मान प्रधानाचार्य की कड़ी मेहनत, लगन और शिक्षा के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राकेश राणा के कुशल नेतृत्व ने विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह उपलब्धि पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय है। विद्यालय परिवार ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वे आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते रहेंगे।

निगरानी डीसी बिलासपुर ने खेल और रोजगार से युवाओं को नशे से दूर रखने पर दिया जोर

नशामुक्त बिलासपुर के लिए सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से राष्ट्रीय मादक पदार्थ मांग न्यूनीकरण कार्ययोजना के तहत सोमवार को संस्कृति सदन बिलासपुर में एकदिवसीय हितधारक कार्यशाला आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त राहुल कुमार ने की। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान और अतिरिक्त उपायुक्त रूपिंदर कौर भी मौजूद रहे। कार्यशाला में विभिन्न विभागों, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों और अन्य हितधारकों ने नशे के खिलाफ समन्वित प्रयासों पर चर्चा की। इस दौरान 'नशामुक्त युवा, विकसित भारत' पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि नशामुक्त बिलासपुर के निर्माण में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। प्रदेश सरकार चिट्टे के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रशासन के 'प्रहार अभियान' से अब तक एक लाख से अधिक लोगों को नशाविरोधी मुहिम से जोड़ा जा चुका है। जिले की 27 पंचायतों को रेड जोन चिह्नित कर विशेष निगरानी और जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए बचाव को इलाज से बेहतर मानते हुए समय रहते पहचान और हस्तक्षेप पर जोर देना होगा। पंचायतों से उन्होंने स्वयं को नशामुक्त पंचायत घोषित करने की दिशा में पहल करने का आह्वान किया।

जागरूकता गतिविधियों के लिए पंचायतों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। राहुल कुमार ने कहा कि नशे की गिरफ्त में आए युवाओं के पुनर्वास के साथ उन्हें सम्मानजनक जीवन देना भी जरूरी है। रेडक्रॉस और गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग से कौशल विकास तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पर काम किया जा रहा है। युवाओं को खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने पर भी बल दिया गया। उन्होंने पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की सराहना करते हुए लोगों से ड्रग-फ्री बिलासपुर का संकल्प लेने का आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने विभागीय प्रयासों की जानकारी दी। जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने भी विचार साझा किए। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष लेखराम, उपाध्यक्ष प्रोमिला चंदेल, पंचायतीराज प्रतिनिधि, अधिकारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

पेंशनरों ने लंबित देनदारियों के जल्द भुगतान की उठाई मांग

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। भारतीय राज्य पेंशनर संघ जयनगर इकाई की बैठक अध्यक्ष सोहन लाल ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक की जानकारी महासचिव हरदेव महाजन ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। बैठक में सबसे पहले 1 सितंबर को शिमला में प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय धरना-प्रदर्शन में भाग लेने वाले सभी पेंशनर साथियों का आभार व्यक्त किया गया।

बैठक में पेंशनर्स ने प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने पर रोष जताया। वक्ताओं ने कहा कि 67 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों की सभी बकाया राशि के भुगतान को लेकर सरकार का दावा वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल मूल पेंशन की बकाया राशि का भुगतान किया गया है, जबकि लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी तथा अन्य देय लाभ अभी भी लंबित हैं। पेंशनर्स ने सरकार से सभी लंबित देनदारियों का जल्द भुगतान करने के साथ-साथ 15 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) की बकाया किस्तें जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से भुगतान लंबित होने के कारण पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की, तो जयनगर इकाई प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के आगामी आंदोलनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करेगी। इस अवसर पर विद्यासागर, रामलाल, जगत राम, रतीराम, हरिदास, गोपालचंद, बाबूराम, श्याम सिंह, हरदेव महाजन, जीत राम, प्रताप सिंह और रमेश चंद्र सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

इवोन नोचेज़ का खूबसूरत अंदाज

अल सल्वाडोर। इवोन नोचेज़ अल सल्वाडोर की प्रमुख महिला स्पीड स्केटरों में शामिल हैं। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। उन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया।

दलीप ट्रॉफी : फाइनल मुकाबले में ईस्ट जोन 708 पर ऑलआउट

ईशान ने 334 बॉल पर बनाए 270 रन, कुमार कुशाग्र का शतक

एजेंसी, बेंगलुरु

दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया। चेन्नई में साउथ जोन के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में ईशान 334 गेंदों पर 270 रन बनाकर आउट हुए। ईस्ट जोन की टीम सोमवार को दूसरे दिन पहली पारी में 708 रन पर ऑलआउट हो गई।

ईशान ने 270 गेंदों में दोहरा शतक ठोका। ईशान ने 10 सालों के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये कमाल किया। इससे पहले उन्होंने साल 2016 में रणजी ट्रॉफी में पहला दोहरा शतक लगाया था। ईशान ने दिल्ली के खिलाफ 273 रनों की पारी खेली थी। वे अबतक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10 शतक लगा चुके हैं। वहीं, कुमार कुशाग्र ने ईस्ट जोन के लिए शतकीय पारी खेली। उन्होंने 132 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। कुशाग्र 101 रन के स्कोर पर चामा मिलिंद की गेंद पर त्रिपुराना विजय के हाथों कैच आउट हुए। ईस्ट जोन ने रविवार को पहले दिन टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम की शुरुआत भी अच्छी रही थी। वैभव सूर्यवंशी ने 37 गेंदों पर 44 रन बनाए, जबकि अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 और शिखर मोहन ने 85 रन की पारियां खेलीं। सूर्यवंशी और ईश्वरन ने पहले विकेट के लिए 100 रन जोड़े थे। इसके बाद ईशान ने पारी को संभाला और टीम को बड़े स्कोर की ओर पहुंचाया।

थकान के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए थे ईशान किशन

ईशान किशन 250 रन के स्कोर पर थकान के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे। 130.2 ओवर में एक रन लेने के बाद वे काफी थके हुए नजर आए। इसके बाद फिजियो ने मैदान पर आकर उनसे बातचीत की, जिसके बाद ईशान पवेलियन लौट गए। उस समय ईस्ट जोन का स्कोर 5 विकेट पर 611 रन था। हालांकि, टीम का 7वां विकेट गिरने के बाद ईशान दोबारा मैदान पर लौटे और अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए 270 रन बनाए।

सिराज को अब तक एक भी विकेट नहीं मिली

मोहम्मद सिराज समेत साउथ जोन के गेंदबाज ईस्ट जोन के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाने में नाकाम रहे हैं। सिराज ने 17 ओवर में 109 रन दिए और उन्हें अब तक कोई विकेट नहीं मिला है।

20 साल बाद एएफसी-20 एशियन कप में पहुंचा भारत

एजेंसी, ताशकंद

भारतीय अंडर-20 फुटबॉल टीम ने 20 साल के लंबे इंतजार के बाद एएफसी-20 एशियन कप के मेन टूर्नामेंट में जगह बना ली है। भारत ने रविवार को ताशकंद में खेले गए ग्रुप-बी के आखिरी क्वालिफायर में बांग्लादेश को 3-0 से हराया। इसके बाद उज्बेकिस्तान ने सीरिया को भी 3-0 से मात दी, जिससे भारत 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वालिफाई कर गया। भारत ने आखिरी बार 2006 में इस टूर्नामेंट के मेन स्टेज में हिस्सा लिया था। भारत ने क्वालिफाइंग राउंड में तीन मुकाबले खेले। टीम ने पहला मैच सीरिया के खिलाफ 1-0 से जीता था। इसके बाद उज्बेकिस्तान के खिलाफ उसे 0-4 से हार मिली। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच भारत के लिए करो या मरो जैसा था।

भारत की जीत के बाद सभी की नजर सीरिया और उज्बेकिस्तान के मुकाबले पर थी। उज्बेकिस्तान ने सीरिया को 3-0 से हरा दिया। इस नतीजे के बाद उज्बेकिस्तान 9 अंक के साथ ग्रुप-बी में पहले स्थान पर रहा। भारत 6 अंक के साथ दूसरे, सीरिया 3 अंक के साथ तीसरे और बांग्लादेश बिना अंक के चौथे स्थान पर रहा। भारत ने सात सर्वश्रेष्ठ उपविजेता टीमों में जगह बनाकर मुख्य टूर्नामेंट में प्रवेश किया। बांग्लादेश अपने तीनों मैच हारने के बाद डेवलपमेंट फेज में चला गया।

स्पोर्ट्स विंडो

डूरंड कप चैंपियन ईस्ट बंगाल को राष्ट्रपति ने सौंपी प्रेसिडेंट्स कप ट्रॉफी

एजेंसी, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में डूरंड कप-2026 की विजेता टीम ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को प्रेसिडेंट्स कप की ट्रॉफी सौंपी। ईस्ट बंगाल ने अगस्त में खेले गए 135वें डूरंड कप के फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी मोहन बागान सुपर जायंट को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। यह ईस्ट बंगाल का डूरंड कप में 17वां खिताब था। इस जीत के साथ ईस्ट बंगाल ने सबसे ज्यादा डूरंड कप खिताब जीतने के मामले में मोहन बागान की बराबरी कर ली। विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले गए फाइनल में ईस्ट बंगाल की ओर से थिलबाम बिपिन सिंह ने 10वें मिनट में, जबकि एडमंड लालरिंदिका ने 12वें, 22वें और 44वें मिनट में गोल किए। एडमंड ने हैट्रिक पूरी की। मोहन बागान की ओर से एकमात्र गोल मनवीर सिंह ने 33वें मिनट में किया था।

लाबुशेन साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल

एजेंसी, मेलबर्न। मार्नस लाबुशेन को खराब फॉर्म के बावजूद साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की 16 सदस्यीय टीम में बरकरार रखा गया है। तीन मैचों की सीरीज 9 अक्टूबर से शुरू होगी। बांग्लादेश के खिलाफ जुलाई में खेली गई टेस्ट सीरीज में लाबुशेन ने 1, 31 और 4 रन की पारियां खेली थीं, जिसके बाद उनके चयन पर सवाल उठ रहे थे। हालांकि, सेलेक्टर्स ने नंबर-3 बल्लेबाज पर भरोसा कायम रखा है। टीम में मैथ्यू कुहनेमन, कूपर कोनोली और माइकल नेसर को भी शामिल किया गया है। सीरीज का पहला टेस्ट 9 अक्टूबर से डरबन में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 18 अक्टूबर से जीक्वेबरहा और तीसरा 27 अक्टूबर से केप टाउन में होगा। लाबुशेन ने अपना पिछला टेस्ट शतक 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में लगाया था। इसके बाद से वे 43 पारियों में 24.69 की औसत से रन बना पाए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ हालिया सीरीज में भी उनका प्रदर्शन प्रभावी नहीं रहा।

विमेंस एशिया कप-2026: श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में पहुंची

एजेंसी, दुबई। दुबई में रविवार को विमेंस एशिया कप 2026 के ग्रुप-बी मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 114 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका ने 19.2 ओवर में 6 विकेट पर 115 रन बनाकर मैच जीत लिया। हरशिता समरविक्रमा ने दबाव के बीच 37 गेंदों पर नाबाद 48 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। श्रीलंका ग्रुप-बी के अपने सभी मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है और अब सेमीफाइनल में ग्रुप- में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम से शुक्रवार को भिड़ेंगी। टीम टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन भी है। 115 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की शुरुआत खराब रही। कप्तान चमारी अटापट्टू सिर्फ 1 रन बनाकर मारुफा अख्तर की गेंद पर आउट हो गईं। मारुफा ने इसके बाद इमेशा दुलानी को भी पवेलियन भेज दिया। इसके बाद सुल्ताना खातून और रितु मोनी ने भी विकेट निकाले। कवीशा दिलहारी रन आउट हो गईं और श्रीलंका 10वें ओवर तक 44 रन पर 5 विकेट गंवा चुका था। यहां बांग्लादेश जीत की स्थिति में दिखाई दे रहा था।

टेस्ट में सीमित मौके, इसलिए चीजों को हल्के में नहीं ले सकते: पडिक्कल

एजेंसी, चेन्नई। भारतीय टेस्ट टीम में जगह पक्की करना आसान नहीं है और मौके भी सीमित मिलते हैं इसलिए कर्नाटक के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल श्रीलंका के हालिया दौरे पर लगातार दो शतक लगाने के बावजूद किसी चीज को हल्के में नहीं ले रहे हैं।

पाकिस्तान क्रिकेट वेंटिलेटर पर टीम से कोई उम्मीद नहीं : अख्तर

एजेंसी, इस्लामाबाद

पाकिस्तान क्रिकेट 'वेंटिलेटर पर' है और मौजूदा टीम से कोई उम्मीद नहीं बची है। इंग्लैंड दौरे पर लगातार खराब प्रदर्शन के बीच पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने

पीसीबी और टीम की मौजूदा स्थिति पर तीखी टिप्पणी की है। शोएब अख्तर ने 'आउटसाइड एज' शो में कहा, टीम को दोबारा मजबूत स्थिति में आने में करीब दो साल लग सकते हैं। अख्तर ने कहा कि पीसीबी मौजूदा टीम के प्रदर्शन से निराश है और अब उसकी उम्मीदें अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों से हैं। उनका मानना है कि ऐसे क्रिकेटरों को तैयार करने की जरूरत है जो लंबे समय तक पाकिस्तान के लिए खेलें। पूर्व तेज गेंदबाज ने शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ को लेकर अलग से सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इन तीनों के करियर में अभी काफी क्रिकेट बाकी है, इसलिए उनके वर्कलोड और फिटनेस का ध्यान रखा जाना चाहिए।

विदेशी और स्थानीय कोचों संग अलग-अलग व्यवहार: मिस्बाह

हाल ही में राष्ट्रीय चयनकर्ता पद से हटे पूर्व टेस्ट कप्तान मिस्बाह-उल-हक ने पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम में कोचों के साथ होने वाले व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय कोचों को विदेशी कोचों की तुलना में ज्यादा जांच और आलोचना का सामना करना पड़ता है। मिस्बाह ने कहा कि उनके मुताबिक पीसीबी, मीडिया, आलोचकों और प्रशंसकों का रवैया विदेशी कोचों के प्रति ज्यादा नरम रहता है। उन्होंने कहा कि विदेशी कोचों को ज्यादा अधिकार और ताकत भी दी जाती है।

पीटरसन इंग्लैंड की व्हाइट बॉल टीम के बने मेंटर

एजेंसी, लंदन। इंग्लैंड ने पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को पुरुष व्हाइट-बॉल टीम का स्पेशलिस्ट मेंटर नियुक्त किया है। वे साउथ अफ्रीका में अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में टीम के साथ काम करेंगे। पीटरसन इसी महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टी-20 इंटरनेशनल और वनडे सीरीज से ब्रेंडन मैकुलम की टीम के साथ जुड़ेंगे। कोचिंग टीम में मार्कस ट्रेस्कोथिक, टिम साउदी, जीतन पटेल और सारा टेलर भी शामिल हैं। पीटरसन ने टीम से जुड़ने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा- 'मुझे बेहद गर्व है कि इस टीम के वर्ल्ड कप जीतने के सफर में मदद करने के लिए मुझे कहा गया है। 2014 के बाद पहली बार इंग्लैंड की जर्सी पहनना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान और बेहद खास पल है।' पीटरसन ने लगभग 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। उन्होंने 104 टेस्ट मैचों में 8181 रन बनाए हैं।

यूएस ओपन : अल्काराज क्वार्टर फाइनल में

टॉमी पॉल को 6-4, 6-3, 6-4 से हराया, अब बेन शेल्टन से भिड़ेंगे

एजेंसी, न्यूयॉर्क

डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने न्यूयॉर्क में खेले जा रहे यूएस ओपन 2026 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मेंस सिंगल्स में अल्काराज ने अमेरिका के टॉमी पॉल को 6-4, 6-3, 6-4 से हराया। इस जीत के साथ उनकी ग्रैंड स्लैम में लगातार 18 मैच जीतने की लय बरकरार रही। टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने सिर्फ एक सेट गंवाया है। अल्काराज दाहिनी कलाई की चोट के कारण करीब चार महीने कोर्ट से दूर रहने के बाद लौटे है।अब क्वार्टर फाइनल में अल्काराज का सामना अमेरिका के 8वीं सीड बेन शेल्टन से होगा। शेल्टन ने स्टेफानोस सिटसिपास को 6-2, 6-3, 6-4 से हराकर अंतिम-8 में जगह बनाई।

महिला एकल में भी अमेरिका की खिलाड़ियों के बीच क्वार्टर फाइनल होगा मुकाबला

महिला एकल में भी अमेरिका की दो खिलाड़ियों के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। जेसिका पेगुला ने सोराना क्रिस्टिया को 6-3, 6-4 से हराया, जबकि एमा नवारो ने अन्ना कलिन्सकाया को सीधे सेटों में मात देकर अंतिम-8 में जगह बनाई।

सबालेंका छठी बार क्वार्टर फाइनल में

महिला एकल में सबालेंका ने अमेरिका की टेलर टाउनसेंड को 6-4, 6-3 से मात दी। सबालेंका ने पहला सेट 6-4 से जीता। दूसरे सेट में 1-3 से पिछड़ने के बाद उन्होंने लगातार पांच गेम जीते और मैच अपने नाम किया।इस जीत के साथ सबालेंका लगातार छठी बार स ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। अब उनका सामना छठी सीड और मौजूदा विंबलडन चैंपियन लिंडा नोस्कोवा से होगा। नोस्कोवा ने मार्ता कोस्ट्युक को 7-5, 5-7, 6-4 से हराया।

एचडीएफसी बैंक ने सस्ता किया कर्ज

एजेंसी, नई दिल्ली। एचडीएफसी बैंक ने सितंबर 2026 के लिए अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट में कटौती की है। बैंक ने विभिन्न अवधि वाली एमसीएलआर में 5 से 10 आधार अंक तक की कमी की है। नई दरें 7 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी गई हैं। इस बदलाव के बाद बैंक की एमसीएलआर अब 7.90 प्रतिशत से 8.60 प्रतिशत के बीच हो गई है, जबकि इससे पहले यह 8 प्रतिशत से 8.65 प्रतिशत तक थी। एमसीएलआर में कमी का असर उन ग्राहकों पर पड़ सकता है जिनके ऋण की ब्याज दर इस दर से जुड़ी हुई है। ऐसे ग्राहकों की मासिक किस्त में राहत मिल सकती है या ऋण की अवधि कम हो सकती है। हालांकि वास्तविक लाभ ऋण की अवधि, बकाया राशि और ब्याज दर के प्रकार पर निर्भर करेगा।

... नई बलेनो की बुकिंग शुरू, 11 हजार रुपए में कर सकेंगे बुक

6.09 लाख से शुरू नई बलेनो की कीमत

एजेंसी, नई दिल्ली

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में नई बलेनो पेश की है। कंपनी ने इसे खासतौर पर युवा और महत्वाकांक्षी शहरी ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। 'डेर टू गो ग्लैम' थीम के साथ पेश की गई नई बलेनो में डिजाइन, सुरक्षा, आराम और तकनीक पर खास जोर दिया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,09,900 रुपये रखी गई है, जबकि ग्राहक 11,000 रुपये की शुरुआती राशि के साथ इसकी बुकिंग करा सकते हैं। नई बलेनो के बाहरी डिजाइन में भी बदलाव किए गए हैं। कार में नई नेक्सवेव ग्रिल दी गई है, जिसमें त्रि-आयामी पैटर्न और क्षैतिज क्रोम स्लैट्स मिलते हैं।

हादसों से बचाएगी कार की उन्नत तकनीक

नई बलेनो की सबसे बड़ी खूबियों में लेवल-2 एडीएएस तकनीक शामिल है। रडार और कैमरा आधारित इस सुरक्षा प्रणाली में उन्नत आपातकालीन ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन से बाहर जाने की चेतावनी, लेन छोड़ने से रोकने की सुविधा, अनुकूली क्रूज नियंत्रण, हाई बीम असिस्ट और आगे की टक्कर की चेतावनी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता कार्यक्रम, एबीएस के साथ ईबीडी, हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर और तीन-बिंदु सीट बेल्ट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।

नई बलेनो में दमदार इंजन

इंटीरियर में डुअल-टोन थीम और पियानो ब्लैक इंसर्ट दिए गए हैं। कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री और क्लैरियन का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है। 22.86 सेंटीमीटर का स्मार्टप्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, सक्रिय शीतलन, 360 डिग्री कैमरा और हेड-अप डिस्प्ले जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। सुजुकी कनेक्ट के जरिए 40 से अधिक कनेक्टेड सुविधाएं उपलब्ध हैं। इंजन की बात करें तो नई बलेनो में 1,197 सीसी का उन्नत जेड12ई पेट्रोल इंजन दिया गया है। पेट्रोल संस्करण में इंजन 61 किलोवाट की अधिकतम शक्ति और 112.4 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है। इसे पांच-स्पीड मैनुअल और एजीएस स्वचालित गियरबॉक्स विकल्पों के साथ पेश किया गया है। कंपनी के अनुसार मैनुअल पेट्रोल मॉडल 23.80 किलोमीटर प्रति लीटर और एजीएस मॉडल 24.77 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है।

एयर इंडिया के नए सीईओ बने 'तेवोल्दे गेब्रेमरियम'

एजेंसी, नई दिल्ली। टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तेवोल्दे गेब्रेमरियम ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। टाटा समूह और एयर इंडिया के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन तथा निवर्तमान सीईओ एवं प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने टाउनहॉल कार्यक्रम में उनका स्वागत किया। गेब्रेमरियम की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब एयर इंडिया सुरक्षा से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना और हाल में एक पायलट के नशीले पदार्थों के सेवन का मामला सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भी विमानन क्षेत्र के लिए चुनौती बनी हुई हैं। चंद्रशेखरन ने नए नेतृत्व से सुरक्षा, यात्रियों का भरोसा, परिचालन दक्षता और लागत अनुशासन को प्राथमिकता देने की अपेक्षा जताई। इथियोपियन एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख गेब्रेमरियम को विमानन उद्योग के सफल अधिकारियों में माना जाता है।

निफ्टी 23800 के नीचे फिसला सेंसेक्स में भी 383 अंकों की गिरावट

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी बिकवाली से घरेलू शेयर बाजार में गिरावट जारी

एजेंसी, मुंबई

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर भारतीय शेयर बाजार पर लगातार दिखाई दे रहा है। सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में पिछले चार सप्ताह से जारी कमजोरी का सिलसिला आगे बढ़ा और दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार समाप्त होने पर सेंसेक्स 382.62 अंक यानी 0.50 प्रतिशत टूटकर 76,132.81 अंक पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 118.55 अंक यानी 0.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,779.15 अंक पर बंद हुआ। इस गिरावट के कारण निफ्टी एक बार फिर 23,800 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे चला गया।

बाजार में निवेशकों की धारणा कमजोर रहने के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारण रहे। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के एक बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से देश के आयात बिल और कंपनियों की लागत पर दबाव बढ़ने की आशंका रहती है।

एसबीआई लाइफ में 2.42 प्रतिशत गिरावट

निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल, लार्सन एंड टुब्रो और कोल इंडिया बढ़त के साथ बंद हुए। अपोलो हॉस्पिटल में 1.27 प्रतिशत, लार्सन एंड टुब्रो में 0.88 प्रतिशत और कोल इंडिया में करीब 0.84 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। इसके विपरीत इन्फोसिस 3.81 प्रतिशत गिरा। एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ में भी करीब 2.42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। सोमवार को बाजार में कुल 4,729 शेयरों में कारोबार हुआ।

कोयला बढ़ोतरी | चार दिनों में कोयला आपूर्ति में 74 रैक प्रतिदिन का इजाफा

बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ी

एजेंसी, नई दिल्ली

बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार पिछले चार दिनों में बिजली संयंत्रों के लिए कोयला रैक लोडिंग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां बिजली क्षेत्र को प्रतिदिन करीब 370 रैक कोयला भेजा जा रहा था वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 444 रैक प्रतिदिन हो गया है। इस तरह चार दिनों के भीतर आपूर्ति में 74 रैक प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है जो करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि है। सरकार के मुताबिक अकेले छह सितंबर को ही कोयला आपूर्ति व्यवस्था में 31 रैक का सुधार दर्ज किया गया।

कोयला मंत्रालय ने बताया कि बिजली क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के साथ ही सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड तथा कैप्टिव खदान संचालकों की ओर से भी आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना और ताप विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त भंडार बनाए रखना है।

मंत्रालय के अनुसार ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है जहां कोयले का भंडार निर्धारित आवश्यकता के 25 प्रतिशत से भी कम है। इन संयंत्रों की स्थिति में सुधार के लिए आपूर्ति बढ़ाने से जुड़े सुधारात्मक उपाय पहले ही लागू किए जा चुके हैं। संबंधित एजेंसियों को कम भंडार वाले संयंत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखने और आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कोयला पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार का कहना है कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए कोयले की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर ताप विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त ईंधन भंडार रहने से बिजली उत्पादन पर अचानक पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है। रैक लोडिंग में हुई वृद्धि को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में भी कोयला उत्पादन और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा ताकि बिजली संयंत्रों की जरूरत के अनुसार उन्हें समय पर कोयला उपलब्ध कराया जा सके।

कोयला संकट टला

कोयला मंत्रालय ने बताया कि बिजली क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के साथ ही सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड तथा कैप्टिव खदान संचालकों की ओर से भी आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्रालय के अनुसार ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है जहां कोयले का भंडार निर्धारित आवश्यकता के 25 प्रतिशत से भी कम है।